राजस्थान विधान सभा

१५ वीं बैठक, शनिवार दिनांक--१५ अक्टूबर, सन् १९५५ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में ८.१७ बजे (प्रातः) प्रारम्भ हुई

(प्रातःकालीन बैठक)

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

राजस्थान राजगामी सम्पत्ति नियमन विधेयक, १९५५ (प्रवर समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति हेतु समय में वृद्धि)

श्री अध्यक्ष—So we are having no question-hour today.

Yes. Shri Vyas.

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय अध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान राजगामी सम्पत्ति नियमन विधेयक, १९५५ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन की उपस्थिति के हेतु नियत समय को ३१ दिसम्बर, १९५५ तक बढ़ाया जाए।

माननीय अध्यक्ष, इन दिनों में एसेम्बली चल रही है इसलिये इसकी कमेटी के लिये समय नहीं निकाल सके, इसलिये समय बढ़ाने की प्रार्थना है

कु० श्री जसवन्तसिंह—एसेम्बलीकी वजह से आपने यह आपत्ति उठाई है, एसेम्बली के समय तो मीटिंग्ज़ बुलाई जा सकती थीं।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—लैंड रिफोर्मस् बिल चल रहा था इसलिये प्रवर समिति के लोग उसमें इन्ट्रेस्टेड थे और मेरा भी यहां हाउस में उपस्थित रहना जरूरी था इसलिये इस समिति में प्रगति नहीं हो सकी।

कु० श्री जसवन्तसिंह—एक दिन में २४ घन्टे होते हैं। यहां एसेम्बली की बैठक तो चार घन्टे ही हुआ करती है; फिर भी २० घन्टे रहते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास—इसके अलावा भी और काम बहुत होते हैं। विरोधी दल के नेता को अगर दो घन्टे ज्यादा बैठना पड़ता है तो आपत्ति होती है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—ऐसी बात नहीं है। मैं २४ घन्टे बैठने को तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष—So what is the wish ? Sbould the time be extended or not ?

(सदन में "यस सर" की आवाज)

कु० श्री जसवन्तसिंह—As a very special case.

श्री अध्यक्ष—Why not a special favour ?

क्या सदन की अनुमति है कि समय बढ़ाया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विराम)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १६५५ (विचार-विमर्श स्थगित)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १६५५ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय अध्यक्ष, मैं इसको ऑपोज़ करता हूं। इसको ऑपोज करने का पहला कारण तो यह है कि बिल की कॉपीज़ जो हमको मिली हैं वे १३ तारीख को मिली हैं और अभी ३ दिन पूरे नहीं हुए हैं। रूल १२२ के तहत बिल उसी वक्त मंजूर होता है कि तीन क्लियर डेज़ मिल जावें। इसलिये इसको आज न लिया जावे।

कु० श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्षजी, मेरे मित्र द्वारा यह जो ओब्जेक्शन रखा गया है वह बिल्कुल वाजिब ओबज़ेक्शन है। इसलिए वाजिब है कि यह बिल एक बहुत महत्व का है और इस बिल के द्वारा जो कार्यवाही माननीय मंत्रीजी सदन से चाहते है, उसके फार रीचिंग इफेक्ट (for reaching effect) होंगे। जो सरकार द्वारा पंचायतों में बेजाब्तगियां हुई हैं, हमें पूरी जानकारी है कि जानकर बेजाब्तगियां हुई हैं जिससे देश भर में, हमारे प्रान्त भर

[कुं श्री जसवन्तसिंह]

में रोष है और उन बेजाब्तगियों को इस तरह से मामूली तरीके से पास कर हम राजस्थान की जनता के साथ अन्याय करेंगे और हमें उनको अपनी ओर से सदन में प्रकट करना होगा। उन बेजाब्तगियों को पास नहीं होने देंगे जहां तक विरोधी दल का सवाल है। इसलिए यह बिल मामूली नियम को तोड़ कर भी सदन के सामने रख दिया गया है, हम इसके लिए रजामन्द नहीं होंगे कि ऐसा बिल इस तरह से सदन में आवे।

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष, अभी हाल में प्रश्नोत्तर काल में मालूम हुआ कि कई जगह; नागौर, झुंझुनु में चुनाव हुए हैं, ग्राम पंचायतों के सर्कल बने हैं। उनमें काफी अनियमिततायें बरती गई हैं और अब उन अनियमितताओं के कारण गांव के गांव रह गये हैं, किसी गांव को विलेज पंचायत के सर्कल में शामिल करना है, दूसरी जगह एक घर एक जगह है, दूसरा घर गवर्मेन्ट होस्टल के पास, दोनों उसमें है लेकिन तीसरा दूसरे गांव के सर्कल में मिला दिया गया है। ये अनियमिततायें हुई हैं और उनको मानते हुए भी उन अनियमितताओं को पास कराना चाहते हैं। राजस्थान की जनता देख रही है कि बेजाब्तगियां हो रही हैं। उसके लिये बहतर तो यही होगा कि जो बेजाब्तगियां हुई हैं उनमें सुधार करें और उनको सुधारने का तरीका यह नहीं हो सकता है कि एक कानून में संशोधन करके जो जो गलतियां की हैं उनको सही मानें। यह इन्साफ के खिलाफ होगा। सही तरीका तो यह होगा कि जो अनियमिततायें की हैं उनमें सुधार करें, उनको सुधारें। पंचायत एक्ट की दफा ८० मौजूद है। ग्राम पंचायतों के एरिया को एक जगह से दूसरी जगह ट्रान्सफर करना है और अगर एक एरीया रह गया है तो उसे ग्राम पंचायत के सर्कल में शामिल करना है। उस दफा में प्रावधान मौजूद है। एक एरिया को दूसरे एरीया में जो एरिया रह गया है उसको मिला सकते हैं और इस प्रकार गलतियों को सुधार सकते हैं। लेकिन अगर उन गलतियों को सही करना चाहते हैं कानून के जरिये तो यह बड़ी ज्यादती है, जनता के साथ धोखा है। इसलिए १२२ धारा के तहत जो ओब्जेक्शन श्री त्यागीजी ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूँ। मैं यह अनुरोध करूंगा माननीय अध्यक्ष, आपके जरिये से सदन के सदस्यों को कि वे इस पर गंभीरता से विचार करें और इसको पास करने के पहले काफी समय दिया जाना चाहिए ताकि विचार विनिमय कर सकें और सही निर्णय पर पहुँच सकें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष,..................

श्री अध्यक्ष—जरा इधर से भी कुछ कह लेने दीजिये।

(स्वायत्त शासन मंत्री के खड़े होने पर)

Not the reply, but by way of informat ion.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—मिनिस्टर साहब बाद में बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष—कुछ इन्फार्मिशन दे दें कि क्यों जल्दी हो रही है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, यह अमेन्डिग बिल १२ को सबमिट हुआ है और अगर १२ तारीख को शामिल किया जाय तो फिर तीन दिन हो जाते हैं और अगर पूरे तीन दिन नहीं होते हैं तो अध्यक्ष महोदय को कानून के अनुसार अख्तियार है कि वे चाहें तो इजाजत दे सकते हैं और कल सदन में इस बात का जिक्र भी आया था और अध्यक्ष महोदय ने कल यह बात भी फरमायी थी कि इसको आज लिया जायगा।

कु० श्री जसवन्तसिंह—अध्यक्ष महोदय जितने आपके हैं उतने ही हमारे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास—सब के हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जहाँ तक अध्यक्ष महोदय, यह एतराज किया गया है कि पंचायतों में बेजाब्तगियां हुई हैं मैं बड़े अदब से निवेदन करूंगा कि यह बात उल्टी समझी जा रही है। दर असल जैसी इस अमेंडिंग बिल की मंशा है उसको समझ लें तो यह दिक्कत पेश नहीं आयगी।

पिछली जो हमारी पंचायतें मौजूद थीं इस कानून के आने से पहले ऐसे बहुत से स्थान हैं कि जहां सिंगल विलेज है, इस कानून के आने पर एक पंचायत बनाने का कानून बनाया और एक पंचायत बनाने के बाद हाईकोर्ट ने निर्णय किया कि पंचायतें बनाने का गवर्नमेन्ट को इस कानून के अनुसार हक नहीं है। अब एक पंचायत पहले से मौजूद है उसमें और एरियाज़ और गांव शामिल किये जा सकते हैं इसी सिलसिले में यह अमेन्डिग बिल आयाहै। मैं यह नहीं समझ सका कि बहुत सी गलतियां हैं और उनको ठीक करना है और गवर्नमेन्ट के पॉवर की बात हो तो उसको ओपॉज करते हैं। ये दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं और महज समझने की बात है। गवर्नमेन्ट को पॉवर है कानून के अनुसार कि एक दूसरे एरियाज़ को शामिल किया जा सकता है और अगर नहीं किया जाने देता है तो लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट की प्रोसेस नहीं होने वाली है। इसलिए यह अमेन्डिंग बिल पेश किया गया है। मै यह निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर कोई गलतियां रह गई हैं, कोई एरिया गलती से शामिल हो गया है, दफा ८६ को अमेन्ड नहीं करेंगे तो गवर्नमेन्ट के पास कोई पॉवर नहीं है, पंचायतें मूव न करें, पब्लिक की ओर से रिप्रेज़ेन्टेशन न आवे तो उस एरिया को निकाल नहीं सकते हैं, इसलिए यह रखा गया है। और मैं समझता हूँ कि यह अमेन्डमेन्ट इसमें नहीं होगा तो पंचायतों का कार्य बन्द हो जावेगा। इसलिए हाउस से निवेदन करूंगा कि इस पर दुबारा विचार कर लें और अगर इस बिल को आज लिया जाना मुनासिब न हो तो कल बैठें या परसों इसको ले लें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—महज समझ का फर्क है साहब।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--मेरी या आपकी ?

(हंसी)

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, कोटा से आये हुए माननीय सदस्य ने जो कानूनी एतराज किया है उसका मैं न केवल टेक्निकल ग्राउन्ड पर समर्थन करता हूँ लेकिन अध्यक्ष महोदय से यह कहा जाय कि वे अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करें विशेष रूप से इस पर विचार करने के लिए इजाजत दें ; मैं यह कहूँगा कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है और वह भी एक गैरवाजिब रिक्वेस्ट मानी जानी चाहिए ।

जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने अभी बताया कि हाईकोर्ट में ऐसे डिस्कशन्स आये जिनके जरिये यह आवश्यक हो गया कि इस प्रकार का संशोधन किया जाय।

माननीय अध्यक्ष, मैं आपके जरिये सदन को यह बताना चाहता हूँ कि हाईकोर्ट के निर्णय के बारे में गलतफहमी जाने में या अनजाने में फैलाने का प्रयत्न किया गया है । जहां तक मेरी जानकारी है बर पंचायत का केस जब हाईकोर्ट में गया तो उस पर हाईकोर्ट ने निर्णय दिया था । हाईकोर्ट ने पंचायत एक्ट की धारा ८६ के अन्तर्गत उस पंचायत की रिक्वेस्ट अथवा उस एरिया के लोगों की प्रार्थना पर एक महीने का शाया करके नोटिस की अवधि पूरी हो जाने के बाद उस पर विचार करके सरकार पंचायत क्षेत्र की रद्दोबदल कर सकती है ।

धारा ८६ के सिलसिले में जो संशोधन प्रस्तुत होने जा रहा है उसमें सरकार को यह अधिकार दिया गया है नये एरियाज़ को इनक्लूड करने का । इस संशोधन के जरिये वे बकरार रहते हैं । जैसा कि एक महीने के नोटिस का मेन्डेटरी प्रोवीजन है उन शब्दों को हटा दिया जाय । उसके हटा देने का तात्पर्य यह होगा पंचायत, पंचायत क्षेत्र के आम नागरिकों की सलाह लिये बिना ही जहां बना दिये गये तो उन क्षेत्रों की जनता की राय जाने बगैर अगर परिवर्तन किया है ऐसी जगहों के लिये जिनको एमरजेन्सी के कारण तोड़ दिया गया और बगैर नोटिस दिये परिवर्तन किया है तो ऐसी हालत में वे क्षेत्र ठीक नहीं माने जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष—It is on the merits. I do not want...........

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं तो यह अर्ज करने जा रहा हूँ कि आप अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके किसी इर्रेगुलर चीज़ को रेगुलेराइज़ करना चाहते हैं और वह इस एक्ट के जरिये से किया जा सकता है, एक महिने के नोटिस का प्रयोग किया जा सकता हैं ।

श्री अध्यक्ष—Everything on the earth can be relevant to this, I do not admit. (राज्य पक्ष से) Are the Heavens going to fall if we do not take it today ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—Even if we do not take it at all, no heavens will fall.

श्री रामकिशोर व्यास (सदन के उपनेता)—माननीय अध्यक्ष, वैसे यह बिल १२ तारीख को सर्क्युलेट हुआ था जिसको आज तीन दिन हो जाते हैं। क्लिअर थ्रि डेज़ तो नहीं होते, इसके लिए रूल्स ऑफ बिज़नेस में अध्यक्ष महोदय, ऐसा अधिकार है कि अध्यक्ष महोदय अगर चाहे तो अपने विशेषाधिकार से इसे ले सकते हैं। मैं इस सम्बन्ध में आपसे प्रार्थना करूंगा कि इसमें जो अमेन्डमेन्ट रखा गया है वह फोर्मल नेचर का है और बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसलिये आप अपना डिसक्रिशन यूज़ करें। यदि किसी कारणवश आज इस पर बहस नहीं हो सकती तो इसे मन्डे को लिया जाय। तब तक तीन दिन पूरे हो जायेंगे।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—आप इसे फोर्मल अमेन्डमेन्ट कैसे मानते हैं ? यह छोटा सा तो जरूर है लेकिन इसका मतलब बड़ा इफेक्ट रखने वाला है, इसलिये आप लोगों के लिए यह छोटा सा हो सकता है किन्तु हम लोगों के लिये तो आपत्तिजनक है।

श्री रामकिशोर व्यास—मैंने इस बारे में अपने ख्यालात जाहिर किये थे। चाहे आप इसे छोटा समझें या बड़ा, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो सिर्फ यह कह रहा था कि यह बहुत आवश्यक है अतः इस पर विचार किया जाय।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—ऐसी कौनसी आपत्ति आने वाली है। नवम्बर के सेशन में भी इस पर अच्छी तरह विचार हो सकता है।

श्री जवानसिंह—इसको नवम्बर के बाद रखा जाय।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)—इसका असर ६५० पंचायतों पर होने वाला है माननीय अध्यक्ष, अतः इसको आज ही लिया जाय।

श्री वेदपाल त्यागी—आप धान्धल बाजी करके इस प्रकार पंचायतें कायम करना चाहते हैं उन्हीं के ऊपर इसका असर पड़ सकता है, और किसी पर नहीं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैं इसको धान्धलबाजी नहीं मानता।

श्री अध्यक्ष—I defer this and come to the next item on the agenda. After this discussion I hope that the Member will meet amongst themselves and will find out some solution.

श्री रामकिशोर व्यास—बहुत मुमकिन है कि कोई तसफिया न हो। अगर किसी प्रकार से तसफिया नहीं हो सकता तो आपको ही अपना निर्णय देना होगा।

श्री अध्यक्ष—मैं तो यह चाहता हूं कि दोनों मिलकर तसफिया कर सकते हैं, आखिर निर्णय तो मुझे ही देना है। This is a very technical affair in which I do not want to Interfere.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—नवम्बर में लेने में आपको क्या एतराज हो सकता है?

श्री अध्यक्ष— When was the Judgment of the High court delivered, I want to know:

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—सितम्बर में हुआ है।

श्री अध्यक्ष—I want the date.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—९ सितम्बर को हुआ है।

द्वितीय पंच वर्षीय योजना के सुझावों पर वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष—Yes. We come to the discussions on the proposals on the Second Five Year Plan.

(कुछ विराम के अनन्तर)

My eyes are open and no member wants to catch it.

श्री जसवन्तसिंह—If nobody speak, I will like to speak.

श्री अध्यक्ष—Welcomed.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्ष, कल द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री का भाषण हमने सुना। इस योजना की मूल मूल बातें उन्होंने हमें बतलाई। मुझे अधिक प्रसन्नता होती यदि माननीय मुख्य मंत्री इस वक्त यहां उपस्थित होते, लेकिन फिर भी जो कुछ मुझे कहना है वह मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूँ।

[कु॰ श्री जसवन्तसिंह]

सर्व प्रथम मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को और मन्त्रि मन्डल को बधाई देता हूँ जिन्होंने प्रयत्न किया और उन प्रयत्नों के फलस्वरूप हमारी धनराशि केन्द्रीय सरकार द्वारा पहली पंच वर्षीय योजना के मुकाबले में काफी ज्यादा तादाद में राजस्थान को हासिल हो सकी। इस पंच वर्षीय योजना में राजस्थान की भलाई की बहुत कुछ गुंजाइश है। अगर काबलियत से और राजस्थान कीसब जनता का सहयोग प्राप्त करके हमारे माननीय मित्र कदम रखेंगे तो हमें पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान का इसमें बहुत हित हो सकता है।

मैं इस विषय पर आने से पहले यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस योजना पर राजस्थान सरकार द्वारा जो विचार रखे गये,जो तजबीजें और जो स्कीम्स रखी गयीं हैं वह काफी ताद में में प्रशंसनीय है उनका उल्लेख करने के लिये तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारे उस तरफ बैठने वाले साथी अवश्य उसकी प्रशंसा करेंगे।

श्री हरिदेवी जोशी—अच्छाई का उल्लेख आप नहीं करेंगे ?

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—इसलिये मुझे गलत न समझा जाय। उन बातों का उल्लेख न करके हम लोगों की नजर में जो त्रुटियां रह गई हैं उनका ही उल्लेख करूंगा।

एक माननीय सदस्य—तो यह एक तरफा बात होगी।

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—अभी तक जब कि मैंने अपने विचार व्यक्त ही नही किये उससे पहले ही मेरे कुछ मित्र यह समझने लग गये हैं कि मैं विरोधी पक्ष का हूँ इसलिये विरोध ही करता हूँ। यह बात नहीं। सही बात के लिये सरकार की प्रशंसा हर कोने से हर पक्ष से होती है। किन्तु विरोधी पक्ष का एक खास कर्तव्य है और वह कर्तव्य यह है कि सरकार की जो त्रुटियां हो वे सरकार के समक्ष रखे, उनकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करे। मेरे ध्यान से जिन बातों को सही करना चाहिये और जिस दृष्टिकोण से इस योजना में और सुविधा मिल सकती है उसको ध्यान में रखते हुए मैं कुछ कहना पसन्द करूंगा; अतः जो कुछ मैं कहूँ उसको आप गलत न समझें।

सबसे पहले मैं, मुख्य मन्त्री जी ने जो यह अपील की है कि इस काम में प्रान्त के हर कोने के सहयोग को प्राप्त करने की आवश्यकता है, उसका जिक्र कर देता हूँ और उस सिलसिले में निवेदन कर देना चाहता हूँ कि हम विश्वास दिलाते हैं कि अगर हम लोगों से सहयोग लेने की सरकार की इच्छा है। तो राजस्थान के प्रान्त की भलाई और उन्नति के लिए हम बड़ी प्रसन्नता के साथ उनको सहयोग देंगे। मगर इसके साथ साथ हम यह चाहते हैं कि सच्चे दिल से हमारा सहयोग वे चाहें तब है।

कुछ गलतफहमी इस सदन के माननीय सदस्यों द्वारा देखने में आई जिसका एक छोटा सा दृष्टान्त मेरे सामने भी आया। कल जब हम किसी भी कारण से इस सदन से जल्दी उठ कर

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

बाहर जाने लगे तो हम लोगों के सुनने में ऐसा आया कि एक माननीय सदस्य ने ऐसा कहा कि ऑपोजीशन के तरफ से यहां कोई नहीं है तो इसलिए आज बहस न हो, इस पर एक माननीय सदस्य ने ऐसा कहा यह सुनने में आया है कि योजना तो हमें चलानी है, विरोधी पक्ष हो तो हमें क्या मतलब और न हो तो क्या मतलब।

(श्री हिम्मतसिंह अटरू, सभापति, पदासीन)

कई सरकारी पक्ष के सदस्य—यह आपको गलतफहमी हो गई।

श्री रामकिशोर व्यास—For your information. I was here and I did not hear anything like that.

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह कहा गया था कि योजना में विरोधी पक्ष को तो कोई दिलचस्पी है नहीं इसलिए हमें ही इस पर सोचना-विचारना है और यह सवाई माधोपुर, जहां के पानी में मलेरिया होता है, वहां से आये सदस्य ने कहा।

एक माननीय सदस्य—हां, ऐसा ही कुछ कहा गया था।

श्री सभापति (श्री हिम्मतसिंह)—Order ! Order !!

कुं० श्री जसवन्तसिंह—तो यह बात शुरू में कह कर अब मैं अपने विषय पर आता हूँ। यह मैं कह चुका हूँ कि हम लोगों को अच्छी तादाद में रकम मिली है और सबके परस्पर सहयोग से हम राजस्थान में बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ राजस्थान को भी इसमें काफी धन-राशि खर्च करनी पड़ेगी और अगर बुद्धिमत्ता से और चतुराई से हमारा मन्त्री मण्डल इस कार्य को आगे बढ़ावे तो मैं समझता हूँ कि यह धन राशि भी प्राप्त करने में हमें कोई मुश्किल नहीं मालूम होनी चाहिये। ईश्वर की कृपा से राजस्थान में लाखों करोड़पति और लखपति मौजूद हैं। उनका सहयोग लिया जावे और मैं यह भी कह दूं कि उनका सहयोग आसानी से नहीं लिया जा सकता। अगर मन्त्री मण्डल के सदस्य उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, उनको इस बात की दिलासा दिलावें कि यह प्रान्त और यह सरकार उनकी है तो मैं विश्वास करता हूँ और विश्वास ही नहीं मैं अपने मित्रों को आशा भी दिलाता हूँ कि जितनी धन राशि उनको जिस रूप में चाहिये, स्माल सेविंग की स्कीम के रूप में चाहिये, लॉन के रूप में चाहिये और किसी भी रूप में चाहिये, वह आ सकती है। लेकिन इसके विपरीत अगर वे यह चाहें कि उन सज्जनों को अपने विश्वास में न लेकर अपने रौब से उनसे रुपया प्राप्त करना चाहें तो यह मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं, इसमें मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है कि वह रुपया उनको प्राप्त नहीं होने वाला है। एक-आध दृष्टान्त भी मैं इस विषय में आपको दे देना चाहता हूँ ताकि हमारा यह मन्त्री मण्डल भी यह देखे कि किस तरह से इन लोगों से रुपया प्राप्त किया जा सकता है। बीकानेर और शेखावाटी में आपको लाखों

[कु० श्री जसवन्तसिंह]

लखपति और करोड़पति सेठ मिलेंगे उनसे अगर आप खुले दिल से बात करें तो मालूम होगा कि उनमें काफी रोष है कि सरकार उनके साथ अच्छी तरह बरताव नहीं करती। एक दिन एक कमेटी जो डेवलप्मेन्ट कमेटी है वह बीकानेर में हो रही थी उसका मैं भी एक सदस्य हूँ, उसमें कभी कभी मुझे भी बुला लिया जाता है। तो उसकी उस दिन की मीटिंग में एक घटना का मैं जिक्र कर रहा हूँ। उस कमेटी में आये सरदार शहर के एक करोड़पति सेठ को सबके सामने मैंने निवेदन किया कि एक अमुक सार्वजनिक काम के लिए तीन हजार रुपया आप अगर दें तो अच्छा। हो उन्होंने कहा कि तीन हजार की क्या बात है, आप चाहें जितना मेरे नाम लिख दें। उस वक्त कमिश्नर साहब भी वहां मौजूद थे। स्माल सेविंग स्कीम के लिए रुपया चाहिये था तो सबके सामने ही उन्होंने कहा, उनका नाम भी मैं बतला सकता हूँ; कि जब आप ही सरकार हमें राजस्थानी ही नहीं समझती है तो फिर हम आपको रुपया किस प्रकार से दें। हमें जो सुविधाएं दी जानी चाहिये और जो रीज़नेबल हैं वे भी नहीं दी जाती हैं, हमें इस प्रान्त का शुभचिन्तक ही नहीं समझा जाता है. तो ऐसी हालत में आप हमसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। और भी उन्होंने उदाहरण दिये कि पुलिस वालों का हमारे साथ क्या सलूक रहता है। रात-बिरात पुलिस के सिपाही या दूसरे अफसर वगैरह आते हैं और कहते हैं कि हमें आपकी लॉरी चाहिये, मोटर चाहिये; ले जाते हैं, तेल भी ले जाते हैं, पैसा तक नहीं देते और यदि कभी किसी कारण से न दे सकते हों और इन्कार कर दें तो यह ऑब्जेक्शन उठा दिये जाते हैं कि इनका लाइसेन्स नहीं है, आर्म्स लाइसेन्स नहीं है और इस तरह से झूठे झूठे मामले में फंसाने की कोशिशें की जाती हैं। यह सारी बात उन्होंने कमिश्नर के सामने स्पष्ट तौर से कहीं। तो यह तो मैंने केवल एक उदाहरण के तौर पर जिक्र किया।

तो मैं कह रहा था कि जैसा मुख्य मन्त्रीजी ने कहा कि सबका सहयोग चाहिये तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम लोगों का जहां तक सवाल है, हम पूर्णतया खुले दिल से सहयोग देंगे। पर जहां तक राजस्थान में रुपयों के ज्यादा इकट्ठा करने की जरूरत है तो वहां इन पैसे वाले लोगों के साथ, जो हमारे यहां लाखों की संख्या में है, अच्छा बर्ताव करें और इस तरह उनका भी सहयोग इसमें लें, वे भी राजस्थानी ही हैं, व्यापार के लिये ही वे बाहर रहते हैं, उनको आप राजस्थानी समझें और राजस्थान का हितचिन्तक भी समझें। ऐसा अगर आप करेंगे तो यह जो धन राशि राजस्थान के डेवलप्मेन्ट के लिए चाहिये उसमें कमी नहीं होगी। मैं यह निवेदन कर रहा था।

अब मैं इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर कहना चाहूँगा। सबसे पहले, यह तो मैं पहले कह चुका था कि हमें अच्छी धनराशि मिली है और इसके लिए हमारा मन्त्री मण्डल और हमारी सरकार हमारी धन्यवाद की पात्र है और संक्षेप में मैंने यह भी कहा था कि मैं सदन का समय ज्यादा न लेकर सिर्फ उन्हीं बातों का जिक्र करूंगा जिनके बारे में कि मेरी दृष्टि में कुछ कमी है और जिसको कि अगर सरकार ठीक समझे तो दुरुस्त करने की कोशिश करे और बहुत अच्छी

[कु० श्री जसवन्तसिंह]

बातें भी इस योजना में हैं जिसके लिए मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे साथी बहुत कुछ उस पर कहेंगे।

पिछली पंचवर्षीय योजना के मुकाबले में इस बार हमें यह बताया गया है कि १२१ करोड़ की रकम भारतीय सरकार द्वारा हमें प्राप्त हुई है। यह बहुत बड़ी रकम है और इससे राजस्थान प्रान्त का बहुत भला हो सकता है और सब के सहयोग से अत्यन्त भला हो सकता है। लेकिन जहां तक मेरा अनुभव है उसके आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि इन १२१ करोड़ रुपयों को खर्च करने के लिये मेरी जानकारी में आपके पास पर्सोनल नहीं हैं और मैं बिल्कुल इस बात में निश्चिन्त हूँ कि ये पर्सोनल नहीं होने की वजह से इन १२१ करोड़ रुपयों का जो फायदा हम उठा सकते हैं उससे आधा ही फायदा हम उठा सकेंगे और यह किस तरह से: यह मैं इस योजना के विस्तार पर जब जाऊंगा तब बताऊंगा। पर इस बारे में मेरी निश्चित राय है कि आपके पास इतनी बड़ी रकम खर्च करने के लिए जिस स्टेटस के और जिस केडर के और जिस केरेक्टर के ऑफिसर्स चाहिये, उस स्टेटस उस केडर के और उस केरेक्टरके ऑफिसर्स आपके पास नहीं हैं। यह बिल्कुल निश्चित है और यह मैं बताऊंगा।

सबसे पहले आपका मुद्दा है कृषि व ग्राम विकास जो हमारा पहली पंचवर्षीय योजना का अनुभव है उसके मुआफिक। इसके लिए हमें ज्यादा संतोष नहीं मिला। कुछ २ इलाकों में, और इलाके हो सकते हैं, इसके लिए ज्यादा संतोष नहीं मिला। टेक्निकल ग्राउन्ड्स पर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स बिल्कुल ही इस बात से महरूम रख दिये गये। मैं आशा करता हूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में वह भावना नहीं रहेगी। उदाहरण के रूप में माइनर वर्क्स के मुत्तलिक कहना चाहूंगा कि बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में माइनर वर्क्स ही नहीं लेकिन प्रथम पंचवर्षीय योजना अगर आप अच्छी तरह से देखेंगे और आपका प्लानिंग डिपार्टमेंट देखेगा तो मैं यह कहता हूं कि पब्लिक के हित के लिए एक पैसा भी वहां खर्च नहीं हुआ और किसी रूप में कोई एक बिल्डिंग बना दी यह हो गया वह दूसरी बात है, लेकिन गांवों में या जिससे कि ग्राम जनता को कोई लाभ पहुँचे वैसा बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में तो कोई एक पैसा, एक पैसे से मतलब यह आप समझिये कि सब्स्टेन्शियल रूप में किसी प्रकार से कोई मदद नहीं मिली, और जहां तक वहां की डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी जिसमें कि एम० एल० ए० की हैसियत से मैं भी एक सदस्य हूँ, कलेक्टर ने कमेटी बुलाई और कई दफा राजस्थान सरकार को तजवीजें भेजीं। जितनी दफा तजवीजें भेजीं वे या तो टर्न डाउन कर दी गईं या महीनों तक जवाब ही नहीं आया और यह भी हमें देखने में आया था कि जहां पर प्लान्स के अन्दर जो रूपया जिस डिस्ट्रिक्ट को दिया जाना चाहिये था और जहां नहीं दिया गया और वहां पर ऐसे कन्सीडरेशन्स नहीं थे कि वह रूपया काम आ सकता था तो स्पेशल फन्ड मुकर्रर हुआ था सरकार द्वारा। वह स्पेशल फन्ड काफी १०-१५ लाख की रकम थी, मुझे पूरा याद नहीं। उसके एलॉटमेंट के लिए यह बात थी कि पंचवर्षीय योजना में खर्च नहीं कर सकते, कोई योजना तैयार नहीं कर सकते हैं तो यह रूपया दिया जायगा। उस रूपये के लिये हमारे यहां से कई तजवीजें

[कु० श्री जसवन्तसिंह]

गई, लेकिन वहां से भी एक पैसा नहीं मिला। कई तजवीजें यों की यों रह गई। जब किहम देखते हैं कि हमारे पास के डिस्ट्रिक्ट नागौर को पंचवर्षीय योजना में काफी मिला, इस स्पेशल फन्ड में बहुत तादाद में रूपया मिला। उन्होंने खर्च किया। बीकानेर में रूपया मिला और रूपया खर्च नहीं किया, और अलॉट भी नहीं हुआ।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में, मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी से कि वे खुद इस बात पर ध्यान दें कि किसी कारण से जो पीछे हुआ सो हुआ, लेकिन आयन्दा के लिए यह देखें कि राजस्थान एक शरीर है और उस शरीर के जितने भी डिवीज़न्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं या तहसीलें हैं वे अंग हैं, और यदि एक अंग की वे परवाह नहीं करेंगे तो वहां गैंगरीन सेट होकर सारे शरीर को नष्ट कर देगी। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह पूरा ध्यान दिया जाय कि शरीर के हर प्रकार के अंग को पूरा पूरा पोषण दें।

मि० चेयरमेन, सर, सामुदायिक योजना और राष्ट्रीय विस्तार सेवा विकास पर इस समय ११ करोड़ रुपये रखे गये हैं, इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। इसमें बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन प्रथम पंचवर्षीय योजना का हमें दुखद अनुभव है। बीकानेर डिस्ट्रिक्ट ही एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें न सामुदायिक योजना वहां पर काम में लाई गई और न राष्ट्रीय विस्तार सेवा की वहां पर किसी तरह की कोई योजना लागू की है। अभी हाल में शायद मन्त्री मण्डल ने २ अक्टूबर को नौखा में एक राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड खोला है, ऐसा सुनने में आया है। यह तो एक हफ्ते पहले की बात है, और इसको अगर यह समझें कि बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के लिए न्याय कर दिया तो मैं समझूंगा कि वह बात नहीं बनेगी। इसके लिए भी मैं यह निवेदन करूं कि हमने काफी योजनाएं राजस्थान सरकार को भेजीं बीकानेर की तरफ से; लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन कई थोड़ी गैरजिम्मेवरी की बातें थीं, मैं उसको कोई महत्ता नहीं देता। गलतफहमी है, हम लोगों की पोजीशन जो कि हम एम० एल० ए० वहां से चुने हुए प्रतिनिधि वापस जब अपने स्थानों पर जाते थे तो स्थिति ऑकवर्ड हो जाती थी जब कि उन गांवों के लोग हम लोगों को आकर यह कहते थे कि लाखों रुपये और करोड़ों रुपये जनता के लिए, ग्रामीणों के विकास के लिए लगाये गये हैं तो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में यह क्या बात है? क्यों नहीं आप इसकी कोशिश करते? वह अनपढ़ और अनभिज्ञ जनता यह नहीं जानती है हम लोगों की कठिनाइयां कांग्रेस दल में नहीं होने से कितनी बड़ी है। लेकिन डेमोक्रेसी चलाने के लिए विपक्ष का होना आवश्यक है। इस बात का उनको ज्ञान नहीं था। लेकिन हमारे कुछ साथी विरोध में प्रचार करके उन लोगों के दिमाग में यह बैठाते थे कि चूंकि आपने कांग्रेस के केन्डीडेट को चुनकर विधान सभा में नहीं भेजा, इसलिए आपको एक पैसा भी नहीं मिला। मैं जानता हूँ कि यह जिम्मेवर शख्स की बात नहीं हो सकती थीं, और मेरी जानकारी में जहां तक कोई मंत्री का सवाल है ऐसी बात नहीं हुई। लेकिन वहां के कांग्रेस के स्थानीय नेताओं में यह चर्चा वहां पर अवश्य हुई।

Page No.13

श्री हंसराज आर्य—ऐसा कोई स्थान तो बताएं।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—कांग्रेस एक बहुत बड़ी संस्था है। यह संकीर्ण विचार और भावनाएं न तो कोई सरकार रखे और न यह संस्था रखे। सब लोगों का सहयोग प्राप्त करें और इस प्रान्त का भला करें। हम लोगों से भी सहयोग लें। सामुदायिक योजना और राष्ट्रीय विस्तार सेवा का द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हर प्रान्त, हर तहसील, हर गांव को पूरा पूरा हिस्सा जो उसके मुताबिक होना चाहिए वह मिलेगा.....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—यह मैं कल कह चुका हूँ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—अब यह देखने की बात है। पिछला अनुभव हमारा कटु है, इसलिए कहने की आवश्यकता पड़ गई।

अब रहा सिंचाई और बिजली का सवाल। इसमें ४४ करोड़ रुपया हमारी योजना में रक्खा है। यह अच्छी धन राशि है। सिर्फ बिजली के लिए मैं यही निवेदन करूंगा कि हमारे बिजली के महकमे की जब इस प्रकार की योजना, इतने करोड़ रुपयों की योजना हम लोगों के सामने है तो जहां तक कि मैं जानकारी रख सकता हूँ कि इसमें योग्य इन्जीनियर्स, अनुभवी इन्जीनियर्स, हाई स्टेंडिंग के इन्जीनियर्स रखने की आवश्यकता है। हमारे मौजूदा इलेक्ट्रिकल एन्ड मेकेनिकल डिपार्टमेंट की स्थिति जो है उसकी मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। जहां कि चीफ इन्जीनियर हैं, उस पर इतना भरोसा सरकार नहीं कर सकती थी कि डाइरक्ट चार्ज उस महकमे का उसको देने के बजाय एक नोन टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटर के सिर पर और रख दिया गया है। मैं नहीं समझता कि एक नोन टेक्निकल को जो चीफ इन्जीनियर हैं उनके सिर पर रख दें, और हम यह आशा करें कि करोड़ों रुपये की स्कीमों को वह सफलता से पूरा कर सकता है। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से यह निवेदन करूंगा कि 'स्माल माइन्ड्स एन्ड बिग एम्पायर्स ब्रौथ गो इल टूगेदर' यह एक बहुत पुरानी कहावत है और इसको आप ध्यान में रखें और जरूरी हो तो पांच हजार तक की आमदनी (तनख्वाह) का आप इन्जीनियर रखें, तो मुझे इसमें किसी प्रकार का एतराज नहीं होगा, लेकिन इतनी बड़ी योजना के लिए ४००) रुपये ५००) रुपये या १०००) रुपये के इन्जीनियर से यह आशा करें कि वह आपका काम सफलता से कर सकेगा, ठीक है कि काम तो होगा, लेकिन काम काम के हिसाब से होगा। मारवाड़ में कहावत है कि "मंहगा रोवे एक बार सस्ता रोवे सौ बार।"

(कई सदस्य "बार बार")

कुं० श्री जसवन्तसिंह—आप यह ख्याल कर सकते हैं कि हम बचत कर लेंगे ५०० रू० या ज्यादा से ज्यादा १००० रू० तनख्वाह देकर करोड़ों रूपयों का काम करा लेंगे। इस

Page No.14

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

समय तो जरूर आपके ध्यान में आयगा कि हम सस्ता काम करा लेंगे लेकिन मैं निश्चत रूप से कहूंगा कि आपको रोना पड़ेगा। आपको रोना पड़े, मन्त्री मन्डल को रोना पड़े तब तक तो कोई बात नहीं है लेकिन आपके साथ हम लोगों को भी रोना पड़ेगा, राजस्थान को रोना पडेगा, राजस्थान के नागरिकों को रोना पडेगा। १२१ करोड़ रूपये खर्च करने के लिये आपके पास उपयुक्त आदमी नहीं है। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिपार्टमेन्ट की उन्नति करने के लिये इतनी बड़ी योजना चलाई है तो एक विशेषज्ञ इन्जीनियर की बहुत बड़ी आवश्यकता है। वह इन्जीनियर चाहे भारत का प्रसिद्ध इन्जीनियर हो या अगर यहां का नहीं हो तो बाहर के किसी योग्य इन्जीनियर की सेवा अगर आप प्राप्त कर सकते हैं तो करनी चाहिये। यदि आपको इस योजना को सफल बनाना है तो आपको बाहर से इन्जीनियर बुलाने पडेंगे। इससे यह नहीं समझें कि यहां के लोग योग्य नहीं हैं। वे लोग भी योग्य हैं लेकिन हर एक के काम करने की शक्ति की मात्रा होती है। इनका एक्सपीरियेन्स अधिक नहीं है। यहां एक मेंढक के तजुर्बे की मिसाल काम की होगी। वह समझता है कि जिस कुए में वह रहता है वही दुनियां, है उसके अलावा और कुछ नहीं है लेकिन उसको मालूम होना चाहिये कि कुए के बाहर भी दुनियां है, हमारे इन्जनियरों की भी यही दशा है। इसमें हम लोग उन इन्जीनियरों को दोष नहीं दे सकते लेकिन यह मानना पड़ेगा कि उनका अनुभव लिमिटेड है। इतनी बड़ी योजना के लिये आपके पास उपयुक्त परसनल्स नहीं हैं। लेकिन सस्ता काम कराने के लिये अंत में आपको ही नहीं बल्कि सारे राजस्थान को अफसोस करना पड़ेगा और यदि बिजली की सप्लाई पूरी नहीं हुई तो सिंचाई, इंडस्ट्रीज़ आदि कम्पलीटली डिपेन्डेन्ट हो जावेंगे और यदि बिजली बंद हो गई तो आपको महसूस हो जायगा कि सस्ता काम करानेके लिये आपने कितनी बड़ी गलती की।

इसके बाद सड़कों का सवाल आता है। सड़कों के लिये करीब ६ करोड़ रुपये द्वितीय पंच वर्षीय योजना में रखे गये हैं। इससे बहुत बड़ा काम हो सकता है और योजना के माफिक आपने बहुत बड़ी स्कीम रखी है और हजारों माइल तक सड़कें बनाने का आपने आयोजन किया है। इसके लिये भी मेरा वही कहना है और मेरे वे ही रिमार्क्स हैं जो मैंने अभी बिजली के महकमें के लिये दिये थे। इसमें भी अपने को काफी तादाद में इन्जीनियर्स और एक्सपीरियेन्स्ड इन्जीनियर्स रखने पड़ेंगे। यदि ऐसा आप नहीं करेंगे तो आपकी सड़कें पंच वर्षीय योजना में पूरी नहीं हो सकेंगी, सब रुपये लग जावेंगे उससे पहले ही टूट जावेंगी। यह हमारा अनुभव है और बिल्कुल यह सही है। आपने जो ६ करोड़ की रकम सड़कों के लिये रखो है वह निरर्थक जायगी और जबतक कि उससे लाभ नहीं होगा, जब तक कि इतने बड़े कार्य को चलाने के लिये योग्य इन्जीनियर्स भारत के या फोरिनर्स न रखे जांय। चालू काम के लिये भी एसेम्बली में सुनने में आता है कि हमारे पास ओवरसियर्स नहीं हैं, इन्जीनियर्स नहीं हैं और उधर वित्त मन्त्रीजी कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। यदि आप सस्ते में काम कराना चाहेंगे तो इस प्रान्त को इतनी बड़ी स्कीम से भी लाभ नहीं होगा। मौजूदा चालू काम चलाने के लिये भी आपके पास इन्जीनियर्स नहीं हैं और पहली पंच वर्षीय योजना के आखिरी साल में हमें धड़ाधड़ करोड़ों रुपयों का काम कराने की नौबत आई उस

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

समय किसी मन्त्री महोदय की व्हिम (whim) के कारण ६ (नौ) इन्जीनियर्स को एक दम सस्पेन्ड कर दिया; ऐसी मिसाल कहीं दुनिया में और जगह आप को मिल सकती है क्या ? आपकी व्हिम (whim) का नतीजा यह हुआ कि उधर काम ठप्प हो गया, सड़कों का काम रुक गया और जहां करोड़ों रुपये खर्च करने का सवाल आया वहां यह हुआ कि इंजीनियर्स नहीं हैं, असिस्टेन्ट इंजीनियर्स नहीं हैं, एग्जीक्युटिव इंजीनियर्स नहीं हैं; दूसरी तरफ यह हुआ कि एक मामूली गलती हुई तो एक दम ६ आदमियों को सस्पेन्ड कर दिया। यह तो वही हुआ जैसे एक भेड़िये ने बकरी के बच्चे को कहा कि तुमने मुझे गाली निकाली थी इसलिये मैं तुझे खाऊंगा। उसने पूछा कि कब गाली निकाली थी तो उसने जवाब दिया कि एक साल पहले। जब उस बकरी के बच्चे ने कहा कि एक साल पहले तो मेरा जन्म ही नहीं हुआ था, मेरा जन्म हुए केवल एक महीने हुआ है तो भेड़िये ने कहा कि तूने नहीं तो तेरी मा ने गाली दी होगी और उस समय तू उसके पेट में था इसलिये मैं तुझे खाऊंगा। इसी तरह से इन इंजीनियरों को सजा दी जा रही है। जब हमें करोड़ों रूपये खर्च करने हैं उस समय आप कहते हैं कि हमारे पास इंजीनियर्स और ओवरसियर्स नहीं हैं और दूसरी तरफ आप सात-सात इंजीनियरों को सस्पेन्ड करते हैं। अच्छा तो यह होता कि चीफ इंजीनियर से लेकर सभी इंजीनियरों को राजस्थान से निकाल देते और पंचवर्षीय योजना का काम अच्छी तरह से बड़ी खूबी के साथ चलता और दुनियां मिसाल देती कि राजस्थान बिना इंजीनियर्स के भी काम कर सकता है। " Small minds and big empirest go ill together", मंत्री महोदय इस कथन को याद रक्खें। अपने कमरे में लिखकर आंख के सामने रखें ताकि आयन्दा गैर जिम्मेदाराना स्टेप न लें।

अब उद्योग के बारे में देखने में आया है कि आपने ११ करोड़ रूपये रखे हैं। इसमें कई उद्योग धन्धे सरकार द्वारा हाथ में लिये जायेंगे उनको भी हमें देखने में मिला। इस बारे में मुझे तो सिर्फ इतना ही कहना है कि दो या तीन धंधे और ये जो इसमें नहीं आये हैं। दो-तीन धंधे ऐसे हैं जिनके बारे में इस योजना में लिखा नहीं गया है यदि उनका भी योजना में समावेश करें तो बहुत सुन्दर बात होगी। ऊन के धंधे को तरक्की देने, ऊन साफ कराने आदि के बारे में लिखा है लेकिन ऊन से जो उद्योग बन सकते हैं, कारखाने खोले जा सकते हैं, गर्म कपड़े बनाये जा सकते हैं। राजस्थान की ऊन फोरिन कंट्रीज़ में भेज कर वहां से कपड़ा बनवा कर यहां मंगाया जाता है। तो यहां पर वूलन मिल का आयोजन करना चाहिये था; या तो किसी एक-दो उद्योगपतियों की मार्फत वूलन मिल खोली जाती या सरकार खुद इमदाद देकर मिल खोलती तो ज्यादा अच्छा हो सकता था। प्लाना लिग्नाइट को भी इस योजना में रखा है लेकिन अब तक यह इंडस्ट्री निग्लेक्ट की गई थी; इससे अब तक इसको तरक्की नहीं मिली थी बल्कि हमारे पॉवर हाउस हैं उनको ६० लाख रूपये प्रति वर्ष का हरजाना इसकी वजह से होता रहा, टेक्निकल ग्राउन्ड्स पर काफी तादाद में कोयला नहीं निकलने से अब तक नुकसान होता रहा। जैसा मैंने निवेदन किया सस्ता काम करने के लिये एक ओवरसियर उसका इन्चार्ज रखा गया उसका नतीजा क्या निकला ? नतीजा यह निकला कि लिमिटेड क्वान्टिटी में लिग्नाइट कोयला प्लाना की खान से निकला और लाखों रूपये की हानि

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

राजस्थान सरकार को हुई । उसके लिये एक बड़ा इंजीनियर दो-तीन हजार रूपये माहवारी तनख्वाह वाला रखते तो इन रूपयों को खर्च करने से लाखों रूपयों की आमदनी हो सकती थी । अब इसके डेवलपमेंट के लिये आपने यह रूपये रखे हैं तो मैं आशा करता हूं कि इन रूपयों को उपयोग में लिया जायगा और इस योजना को हाथ में लिया जायगा और यह आशा रखता हूं कि वर्तमान असिस्टेन्ट इंजीनियर या फोरमेन के द्वारा यह काम करना चाहेंगे तो मैं निवेदन करूंगा कि आप हरगिज उससे काम नहीं करा सकते । आपको बड़ी तनख्वाह वाला आदमी रखना पड़ेगा । जरूरत हो तो हिन्दुस्तान का नामी इंजीनियर या जरूरत हो तो विदेशी इंजीनियर को रखें । इसको सुधारने में पैसा खर्च करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा ।

अब फर्टिलाइज़र फेक्ट्री का सवाल है । इसके लिये जो प्रयत्न सरकार ने किये उसके लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं । जहां तक फार्टिलाइज़र फेक्ट्री का सवाल है हम भी पूरे प्रयत्नशील हैं । बीकानेर के महाराजा साहब से लेकर हम लोग जो कुछ आवाज रख सकते हैं वे सब इसके लिये प्रयत्नशील हैं । क्योंकि हम बीकानेरियों के लिये यह जीवन-मरण का सवाल है । इतनी बड़ी फेक्ट्री खुलेगी तो हजारों आदमियों को रोजी कमाने का मौका मिलेगा और उनका जीवन स्तर बढ़ सकेगा । यह खुशी की बात है कि एक दफा मांग टर्न डाउन करने के बाद भी सरकार के प्रयत्न से फिर गौर किया जा रहा है और हम भी कोशिश कर रहे हैं । मैं आशा करता हूं कि मुख्य मंत्रीजी और सरकार इससे भी अधिक जोर लगाकर जहां तक हो सके वह देखें कि यह मौका हम लोगों के हाथ से न चला जाय । यदि यह मौका चला गया तो राजस्थानियों को जो नुकसान होगा वह तो होगा ही लेकिन केन्द्रीय सरकार का राजस्थानियों के साथ बड़ा अन्याय होगा ।

जो सुविधाएं और साधन राजस्थान में मौजूद हैं, ऐसी बड़ी फैक्ट्री.के लिये, वे भारतवर्ष में और कहीं नहीं मिलेंगी । राजनैतिक कारणों से या और कारणों से केन्द्रीय सरकार ऐसे कारखानों को राजस्थान में नहीं खोले तो यह राजस्थान के साथ अन्याय होगा' और अगर इसका मुकाबिला करने के लिये हमारी सरकार प्रयत्नशील होगी तो हम लोगों से जो सहायता सहयोग सरकार चाहेगी, हम विश्वास दिलाते हैं कि हमारा सहयोग होगा । इसमें हमें जोर लगाना है । दूसरे हम से बड़े प्रान्त हैं, उनमें कितना ही पुल हो, हम उसका मुकाबिला करेंगे और यह फैक्ट्री राजस्थान में नहीं खोलना राजस्थान के साथ अन्याय है । तो यहां फैक्ट्री खुलवाने के लिये प्रयत्नशील होंगे ।

अब शिक्षा के लिये १० करोड़ रुपया रखा गया है, यह भी बहुत सुन्दर धन-राशि हैं और राजस्थान में शिक्षा के सुधार में बहुत उन्नति की जा सकती है । मेरे विचार से शिक्षा मंत्री जी हैं वे ही मुख्य मंत्री जी हैं; वे भली भाँति सब बातों से परिचित हैं । इसलिये ज्यादा न कह कर इतना ही कहना आवश्यक समझूंगा कि इसमें वे बड़े विचार रखें और जिस जिस जगह, जिन जिन का जितना हक है और जितनी मदद दे सकें, संकीर्ण दृष्टि से नहीं सोचें, हर एक को अपना अपना

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

हिस्सा दें। अगर कुछ संस्थाओं को ज्यादा दे कर दूसरी संस्थाओं को उनके वाजिब हिस्से से उनके हक से वंचित रखेंगे तो दूसरों का हिस्सा लेने वाली संस्था कभी फलेगी फूलेगी नहीं। क्योंकि दूसरी संस्थाओं का श्राप लगेगा, निरर्थक लेना, बिना काम लेना किसी की फलेगा फूलेगा नहीं, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ मेरे मित्र मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इतनी बड़ी रकम द्वितीय पंच वर्षीय योजना की मिलने वाली है, उसका उचित हिस्सा सबको मिलना चाहिये। हर डिविजन, हर जिले, हर शहर, कस्बे और हर गांव को उसका सच्चा हिस्सा देवें, और मैं आशा करता हूँ कि वे देंगे। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो रकम इस मद के नीचे दी गई थी उससे हमें संतोष नहीं हुआ।

स्वास्थ्य के लिये १० करोड़ ६८ लाख रूपया मंजूर हुआ है। इस महकमें में, मेडिकल महकमें में उन्नति करने की बहुत बड़ी गुंजायश है। राजस्थान नहीं बना था, उससे पहले, कुछ रियासतों के अस्पतालों की भारतवर्ष के ऊंचे अस्पतालों में गिनती थी, हालांकि उनके पास इतने साधन नहीं थे जितने कि आज राजस्थान सरकार के पास उपलब्ध हैं, पर राजस्थान बनने के बाद उन संस्थाओं को उतनी तरक्की नहीं मिल सकी। जितनी धन राशि के रूप में परकेपिट आज उन पर खर्च होता हैं, उसे देखें तो पहले से ज्यादा धन राशि खर्च की जाती है पर स्टेन्डर्ड स्वास्थ्य और चिकित्सा के सम्बन्ध में दिन-प्रतिदिन पहले से गिरता नजर आता है। इसके कारण में हम जायं तो इसमें हम देखते है कि डाक्टरों को जो तनख्वाह, जो रेम्युनरेशन मिलना चाहिये वह नहीं दिया जाता है। पर्सनल के लिये अर्ज किया था कि आपके पास नहीं हैं। आपके पास जो योग्यता के डाक्टर होने चाहिये, वह नहीं हैं, मैं समझ सकता हूँ कि क्यों नहीं हैं? हमारी राजस्थान सरकार जो तनख्वाह, जो रेम्पूनेरेशन, जो सहूलियतें उन्हें जो दूसरी जगह मिल सकती हैं और जो उन्हें कुछ रियासतों में मिलतीं थीं, वे उन्हें आप नहीं देते हैं। मैं बीकानेर मेडिकल डिपार्टमेंट का जिक्र करते हुए यह अर्ज करूंगा कि राजस्थान बनने से पहले बीकानेर का जो पी० एम० ओ० था वह हिन्दुस्थान में ही नहीं बल्कि दुनियाँ में नामी डाक्टर समझा जाता था और उसको करीब ५,०००) रुपया रेम्पूनेरेशन माहवार दिया जाता था। शायद कई मेरे सामने बैठे हुए सदस्य इस पर एतराज उठायें इसलिये मैं पहले ही साफ करदूं; तनख्वाह तो उसको ३००० रू० मिलती थी परन्तु इन्कम टैक्स की उसको स्टेट छूट देती थी, ३०० रूपया माहवार का। उसको मकान दे रखा था, फ्री प्रेक्टिस की इजाजत दे रखी थी जिससे वह दो, तीन हजार रूपया माहवार कमाता था। तो इस तरह उसकी माहवार आमदनी, ५, ६ हजार रूपया पड़ती थी। इस तरह के विशेषज्ञों को ढूंढ ढूंढ कर, दुनियाँ से ढूंढ ढूंढ कर इंगलैंड और जर्मनी से ढूंढ २ कर लाते थे, पर आज आप बड़े से बड़े डाक्टर को जब कि राजस्थान के इतने बड़े साधन हैं, क्या देते हैं।

आप जो इस डिपार्टमेंट का हैड रखेंगे वह अगर एकेडेमिकल डिग्री में सर्वोच्च नहीं होगा, तब तक डाक्टर यह समझेंगे कि डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एन्ड हैल्थ सर्विसेज़ हमसे ज्यादा

[कु० श्री जसवन्तसिंह]

योग्यता नहीं रखता। तो वे क्या उसका रोब मानेंगे? इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स वगैर और नहीं रह सकता। तो ऐसी सूरत में इस महकमे का हैड इतना बड़ा नहीं रखेंगे कि जो एकेडेमिक डिग्री में सर्वोच्च न हो और इतना अधिक एक्पीरियंस न होगा कि सब पर कन्ट्रोल कर सके, तो इस महकमें से जिसका कि जनता से डायरेक्ट सम्बन्ध है, इससे जनता को लाभ नहीं पहुँच सकेगा।

डायरेक्टर ऑफ मैडिकल एन्ड हैल्थ का पद बहुत बड़ा है, इस पद पर सर्वोच्च एकेडेमिक डिग्री प्राप्त किया हुआ नहीं होगा और उसको किसी कारण से दूसरा काम देंगे, ऑपरेशन्स करने का और नुस्खे लिखने का काम देंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका यह महकमा दिन ब दिन गिरेगा। और हमारा मैडिकल डिपार्टमेंट है, इसमें जिस तरह के पर्सोनल्स आज हैं उनके कारण दिन पर दिन इसका स्टैन्डर्ड, इसका स्तर गिरता जा रहा है।

आज आप इस पर इतनी बड़ी रकम खर्च करना चाहते हैं उस रकम का एक बड़ा हिस्सा आपको इस महकमे में काबिल परर्सनल लाकर उन पर खर्च करना पड़ेगा। यदि आप यह खर्चा नहीं करेंगे और अच्छे अच्छे योग्य पर्सन्स नहीं रखेंगे तो राजस्थान को राजस्थान के और चिकित्सा विभाग का स्टेन्डर्ड, स्तर ऊंचा नहीं उठा सकेंगे और इससे राजस्थान को नुकसान होगा।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय, अथवा अन्य मंत्री महोदय यह नहीं समझें कि मुझे किसी व्यक्ति के प्रति निजी रूप में आक्षेप करना है, न यह बात कभी मेरे दिमाग में थी और न है क्योंकि मेरी ट्रेनिंग ऐसे महान् पुरुष के द्वारा ली गई है कि ऐसे विचार हम एन्टरटेन ही नहीं करते। पर साथ ही यह बात है कि जो बात हमें कहनी है वह बगैर किसी डर के, बगैर किसी खौफ के कहेंगे। इसी सिद्धान्त पर चलते हुए मैं अपने विचार सरकार के सामने रख रहा हूँ। ग्रह निर्माण के लिये आपने ४ करोड़ ७० लाख रुपये मद में रखे हैं और मैंने इस सम्बन्ध में डिटेल्स में क्या क्या कार्य ग्रह निर्माण के सरकार द्वारा होंगे उसकी लिस्ट भी देखी। मुझे बड़ा अफसोस है कि उसमें एक भवन का उल्लेख नहीं किया गया है। मैं समझता हूँ कि उसको माननीय चीफ मिनिस्टर को देना चाहिये था! यह हमारे राजस्थान के लिये बड़े सौभाग्य की बात है कि अभी नये राजस्थान का रूप होगा और वह रूप, और विस्तार का होगा। अजमेर और आबू जिसको कि जबरदस्ती हम लोगों से ले लिया गया था वापिस आ रहे हैं। अजमेर भी राजस्थान का भाग बन रहा है। तो इससे इस राजस्थान का विस्तार और बढ़ेगा और इससे राजस्थान की जबाबदारी और विधान सभा की जिम्मेदारियें और ज्यादा बढ़ेंगी। इस भवन निर्माण में, मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान विधान सभा भवन के निर्माण में ३०, ४० लाख रुपया लगेगा और विधान सभा का निज का भवन होगा जो होना आवश्यक है। यह भवन बहुत सुन्दर है, लेकिन बढ़ती हुई संख्या के लिये यह भवन हम लोगों के लिये छोटा भवन होगा। इस भवन में सभी मंत्रियों के काम करने के लिये बैठने के कमरों की सुविधा भी नहीं है। नये भवन में यह सब सुविधाएं हो जाएगीं। जिस प्रकार मंत्रियों के बैठने और काम करने के लिये दूसरी जगह; जैसे हाउस ऑफ पीपल्स और इंग्लैन्ड में कमरे हैं उसी प्रकार

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

के कमरे होने जरूरी हैं जिससे कि वे जिस प्रकार से सेक्रेटेरियेट में बैठ कर काम करते हैं उसी प्रकार यहां बैठ कर अपना काम कर सकें। इस वक्त के जो कमरे हैं वे स्टेबल के माफिक हैं, घोड़े के अस्तबल के माफिक हैं। हां, वहां पर टेबल पर टेलिफोन जरूर बिजली घर की महरबानी से लगा हुआ है लेकिन वे यहां पर अपनी रेस्पोन्सीबिलिटी का काम जिस तरह से सेक्रेटेरियेट में बैठ कर कर सकते हैं वह नहीं कर सकते। हरदम लोग आते-जाते रहते हैं, इसलिये वे यहां पर अपनी जिम्मेदारी का काम कर लें, यह नामुमकिन है। इसके अलावा यह हमारे प्रान्त के लिये शोभा की भी बात होगी कि हमने अपने लिये खुद ने अपना विधान सभा भवन बना लिया है। इस वक्त हम मांगे हुए भवन में काम कर रहे हैं और थोड़े समय बाद यदि राजप्रमुख का पद हट गया और राजप्रमुख नहीं रहे और जैसा कि हमें देखने में आ रहा है कि राजप्रमुख का पद हटाया जा रहा है उस समय हम एक मांगे हुए स्थान पर कार्य करें, ऐसा अच्छा नहीं दीखता। जब हम एक मांगे हुए भवन में कार्य कर रहे हैं तो क्या वे इस भवन के निर्माण की आवश्यकता को महसूस नहीं करते? वह तो हमें बनाना ही होगा। इसलिये मैं यह कहूँगा कि माननीय चीफ मिनिस्टर इसके लिये भरसक प्रयत्न करेंगे और अगर गृह निर्माण में मुमकिन हो सके तो इसको बनाने का प्रयत्न करेंगे। मैं तो उन लोगों में से हूँ जो इस बात को मानते हैं कि अगर कोई प्रयत्न करें तो कोई चीज मुश्किल नहीं हो सकती। सेक्रेटेरियेट के पास बहुत जमीन है, मैदान है जहां दूसरे भवन बन रहे हैं। वहां पर राजस्थान विधान सभा का भी मोस्ट मोडर्न भवन बने जिसमें काम करने के लिये मिनिस्टरों के अलग अलग कमरे हों जिसमें वे काम कर सकें और काम करने का आनन्द आवे। यह मेरा सुझाव गृह निर्माण के सम्बन्ध में है।

अब पंचायतों के लिये भी काफी रकम रखी गई है। इसके लिये भी हमारा जो पिछला अनुभव है वह बहुत अच्छा नहीं है। इसलिये इस पर मैं ज्यादा न कह करब ही निवेदन करूंगा कि इसमें भी संकुचित विचार न रखे जावें, छोटे विचार न रखे जावें और राजस्थान के जितने वर्ग हैं, समुदाय हैं, उन सब को एक समझ कर कार्य किया जावे।

भाकरा का काम पिछले पंच वर्षीय योजना में शुरू हुआ था। जिस तरह से यह काम चल रहा था उसको देखने का काम मुझे भी पड़ा। एक-दो दफे मुझे भी इसके काम को देखने का मौका मिला। यह एक इतना बड़ा काम है कि इसके पूर्ण होने से जनता को राहत मिलेगी। इस संबन्ध में मैंने कहा कि इतने बड़े कार्य के लिये जो पर्सोनेल्स हैं वे ठीक नहीं हैं, वे उपयुक्त नहीं हैं। अगर वे इसी तरह से जिस तरह से काम करते रहे हैं करते रहे तो मैं समझता हूँ कि सरकार को कोई फायदा नहीं होगा, छोटे अधिकारियों को सरकार ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी का काम सौंप दिया है जिन पर राजनैतिक दल द्वारा दबाव डाले जाते हैं, किसी काम के लिये और उनका होसला यह नहीं होता कि वे राजनैतिक दल द्वारा दबाव को इन्कार कर सकें। इसलिये जब तक वहां पर ऐसे योग्य अधिकारी न आवें जो इस प्रकार की कार्यवाही दबाव से न करें तो भाकरा जैसे और चम्बल जैसे काम में बड़े बड़े अधिकारी होने चाहिये जिन पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी का काम सौंपा जा सके। आपके पास

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

बिल्कुल इनएडीकेट ओफिसर्स हैं। इसलिये आपको योग्य अधिकारियों के लिये, चाहे आपको ज्याद खर्चा ही क्यों न करना पड़े, करके यदि वे आपके यहां नहीं है तो भारत सरकार से उन अधिकारि को ४ हजार या ५ हजार रुपया माहवार देकर बाहर से भी बुलाना पड़े तो उन्हें बुलावें और इसय प्रकार छोटे अधिकारियों को रख कर इस योजना के साथ खिलवाड़ न करें। पहले इन्तजाम के लिये जितने विशेषज्ञों पर खर्च करेंगे उतना ही आपको ज्यादा लाभ होगा।

इसी तरह से खनिजों का काम है, माइन्स का काम है। इनमें भी आप बहुत अच्छे अच व्यक्तियों को नियुक्त इस सम्बन्ध में विशेषज्ञों की राय लेकर करें और सब इस सम्बन्ध में जानकारों का सहयोग लेकर काम करना चाहिये। अगर ऐसा सरकार करेगी तो मैं आशा करता हूँ कि यह एक बहुत बड़ा काम हमारे राजस्थान में होने वाला है। इस तरह से हर बात पर बहुत कुछ कहा जा सकता है लेकिन, मैं अपना वक्तव्य सिर्फ इतना ही कह कर खत्म करना चाहूँगा कि जैसा मैंने डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग में निवेदन किया था और उस समय मुझे यह कहा गया था कि हमारी स्कीम में इसका प्रबन्ध किया गया है। इस सम्बन्ध में मैं नम्रता के साथ कहूँगा कि मुझे उससे संतुष्टि नहीं है। मैंने यह तजवीज रक्खी थी कि गांवों में पीने के लिये पानी का बन्दोबस्त हो। इसके लिये करोड़ों रुपयों की धन राशि रखी गई है। उसके लिये आप वहां (गांवों) की लोकल कन्डीशन्स को देखें और उनकी जानकारी करें। आप जयपुर में बैठे हुए वहां की हालत को कलेक्टर से या कमिश्नर को लिख कर मंगवा लेते है जो वास्तविक स्थिति से वाकिफ नहीं होते कि वास्तव में गांवों में क्या स्थिति है, या आप राजनैतिक कार्यकर्ताओं से पूछ लेंगे कि क्या स्थिति है; तो इससे तो आपको केवल एक ही दृष्टिकोण मिलेगा और वह गलत मिलेगा। मैं बीकानेर जिले में पानी के कष्ट का जिक्र करना चाहता हूँ। वहां एक ऐसा इलाका है जहां ईश्वर की अद्भुत लीला है जो आपको ताज्जुब समझ में नहीं आ सकती है कि वहां पर वह कैसे हुआ ? जो पानी पीने के कुओं में मिलता है, होगा कि कहीं कहीं ऐसा जहरीला पानी है कि आप पानी पीजिये, खास तौर पर गर्मी में जानवरों को पानी पिलाइये, पांच मिनिट के अन्दर अन्दर गर्मी में पानी पिलाते हैं तो वे खत्म हो जायेंगे। उस के जरिये से लोग खाना नहीं पका सकते हैं। पानी जहरीला होता है, ज्यादा पानी पीवेंगे तो मर जावेंगे, लोग पानी पी नहीं सकते; ऐसे ऐसे दृश्य देखने में आते हैं, जब गर्मी १२० डिग्री होती है,तीन तीन, चार-चार दिन पानी पीये को गये, जब पशुओं को पानी पीने के लिये लाया जाता है, जानवरों के मालिक हाथ में लकड़ी लिये हुए आते हैं, दो दो, चार चार जानवर लाते हैं, दो चार घूंट पानी पी लेने पर उनको हटा देते हैं, तीन-तीन चार-चार दिन से प्यासे जानवर पानी ज्यादा पीनेके लिए टूट पड़ते हैं और वे एक दो घूंट और अधिक लेना चाहें तो उनको लाठी से मार कर हटा दिया जाता है, क्योंकि एक दो घूं पानी को वे और ज्यादा लेंगे तो वे मर जावेंगे। कम से कम तीन चार हजार स्कूवायर माइल्स के एरिया में यह हालत है और कहीं कहीं कुओं में ऐसा है कि नीचे जाकर मीठा पानी जरूर आता है लेकिन ४०-५० फीट नीचे जाकर ऐसा श्रोत आता है, ईश्वर की लीला अद्भुत

[कु० श्री जसवन्तसिंह]

है, उसमें सिवाय जहर के कुछ आता नहीं। वह पानी नीचे जाने पर जहां मीठा पानी मिलता है उसको भी दूषित कर देता है। इसको सुधारने के लिए मैं सरकार को और इस योजना को चलाने वाले अधिकारी लोग हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे इसको प्रेक्टिकल शेप दें और इससे ही संतुष्टि नहीं कर लें कि इसका पंचवर्षीय योजना में जिक्र कर दिया है, इस बात का जिक्र इस लाल किताब में कर दिया है।

("पीली किताब है" ऐसी आवाज)

पीली कहिये, लेकिन जो फ्रेज़ है, रेड बुक, उसको ध्यान में रखते हुए रेड यूज किया है। इसको पीली किताब कहिये, यह हो जायगा लेकिन इस समस्या को अवश्य हल किया जाय। मैं कह सकता हूँ कि अगर करना चाहें तो हो सकता है। इसके लिए विशेषज्ञ बाहर से बुलावें, एक्सपेरिमेन्टल स्कीम्स बनावें, दस-पन्द्रह लाख रुपया अगर इसके लिए खर्च हो जावे तो खर्च कीजिये। लेकिन अगर आप यह चाहें कि वही योजना हाथ में लेंगे कि जिससे रिटर्न मिलता हो या जिस योजना पर गांव वालों की ओर से १।३ हिस्सा हो। अगर इसी मंशा से पंचवर्षीय योजना को चलाना चाहेंगे तो आप सफल नहीं होंगे। अगर सफल हुये इसी दृष्टि से कि खर्च किया जा रहा है, तो भले ही खर्च करते जाइये, खर्चा बेकार होगा। न ग्रामीणों की माली स्थिति ऐसी है कि वे आपको योजना में रुपया दे सकते हैं; उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने से वे कोई पैसा नहीं दे सकते हैं लेकिन अगर आप जोर देंगे कि अगर आप हिस्सा नहीं देंगे तो आप नहीं देंगे, तो सफलता प्राप्त होने वाली नहीं है। जो पानी की समस्या बीकानेर के आसपास के एरिया की है अगर उसमें सुधार होता है तो जो हमारा अमूल्य पशुधन है उसी को मदद नहीं मिलेगी बल्कि आबादी भी बढ़ जायगी और नई नहरें, राजस्थान केनाल, काफी हद तक उस एरिया में जावेगी। वहां पर निवासियों में वृद्धि होगी, यदि आप पानी की समस्या को हल कर सकेंगे। मैं इसको मुश्किल नहीं समझता। पुरानी मिसल निकलवाइयेगा। अमेरिका से, इंगलैंड से विशेषज्ञ भूतपूर्व बीकानेर स्टेट ने बुलाये थे, उनके क्या विचार हैं, एक्सपेरिमेन्ट भी किये गये एक दो कुओं पर और उसके फलस्वरूप तरक्की भी हुई। तो इस समस्या को हल करने के लिये १०, १५ लाख रुपया खर्च करके, एक्सपेरिमेन्ट्स करके, बगैर इस ध्येय कि इसका हमको कोई रिटर्न मिलेगा या गांव वालों की ओर से धन मिलेगा, अगर सरकार द्वारा यह धन लगाया जायगा तो बहुत बड़ा हित राजस्थान का कर सकेंगे। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया था कि राजस्थान एक शरीर है, जब उसके सब अंग ठीक होंगे तो तरक्की होगी। तो इन शब्दों के साथ माननीय चेयरमेन, सर, अपना स्थान ग्रहण करता हूँ और आशा करता हूं कि हमारी सरकार जो कुछ मैंने कहा है, जो कुछ सरकार के सामने, मेरे ध्यान में जो कमियाँ आईं, उनको रखा है वह इसी ध्येय से रखा है कि हम जानकारी करा सकें, इमदाद दे सकें। मैं फिर यह अर्ज कर देना चाहता हूँ कि यह अच्छी स्कीम है, इसमें बड़ी गुन्जाइश है और सरकार ने प्रयत्न किया है कि राजस्थान को जितना फायदा पहुँच सके पहुँचे। इस समय यह आवश्यक नहीं है कि अन्य पहलुओं पर और विचार व्यक्त करूं, वैसे मुझे बोलते हुए करीब एक घंटा हो गया है और फिर बोलूं तो एक घंटा और लगेगा; तो इधर के बैठे हुए साथी और उधर के बैठे हुए

[श्री कु० जसवन्तसिंह]

साथी बोलेंगे। अच्छी बातें हैं, इस योजना में उसके लिए सरकार को बधाई देता हुआ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

(करतल-ध्वनि)

श्री हरिकृष्ण व्यास—सभापति महोदय, यह बहुत संतोष का विषय है कि इस सदन में राजस्थान की द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर हम विचार कर रहे हैं। सही—ज्यादा तो यह होता कि योजना कमीशन के सामने प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पहले किसी न किसी रूप में हम उन प्रश्नों पर विचार कर पाते जिससे कि जो भी वाद-विवाद या विचार-विनमय यहां होते हैं, या सुझाव या प्रत्युत्तर यहां आवें उनका प्रभाव इस योजना पर पड़ पाते लेकिन वह न मालूम किन कारणों से संभव न हो सका। जहां तक मुझे याद पड़ता है सदन में यह कहा जरूर गया था कि योजना तैयार होने के बाद और योजना कमीशन भी प्रस्तुत करने के पहले किसी न किसी रूप में विधान सभा के सदस्यों से विचार-विनमय अवश्य किया जावेगा। यह मैं मानता हूँ कि यह कमी है कि यह सम्पर्क क्यों नहीं हुआ। खैर, जो भी हुआ हो, जिस रूप में भी योजना कमीशन ने इस योजना की मंजूरी दी उस पर भी हम यहां बैठकर विचार कर रहे हैं, तो यह हम सब लोगों के लिए, इधर बैठने वालों के लिए या उधर बैठने वालों के लिए, संतोष का विषय माना जाना चाहिए। मुझे खेद है कि कल से कुछ इस प्रकार की बातें, इस प्रकार बार बार आई हैं कि जैसे हमको कोई धनराशि मिली हो और उस धनराशि पर संतोष व्यक्त करना या न व्यक्त करने की बात हमारे सामने हो। मैं नहीं मानता कि जिस योजना पर धनराशि मिली है या नहीं मिली है उस पर विचार करना है। वास्तविक स्थिति तो यह है कि राजस्थान की जो आज हालत है उसको देखते हुए किन किन मदों पर, किन २ योजनाओं पर, किन किन चीजों पर हम कितना रूपया खर्च कर सकते हैं अपने साधनों को देखते हुये और साथ ही साथ लोगों की आवश्यकताओं को देखते हुये कितना खर्चा करना चाहिये, उन सब का समन्वय बना करके एक कार्य करने के लिए हमने एक मेनिफेस्टो तैयार किया है। अभी धनराशि मिली नहीं है, मिलने वाली है। कुछ इम्प्लीमेन्ट नहीं हुआ है आगे बढ़ने के लिए किन्तु कुछ विचार आगे बढ़ने के लिए निश्चित बने हैं और इसलिए इसको इस दृष्टिकोण से देखें। जहां हमने सही रूप से कार्य करने का उल्लेख किया है उससे इतना अवश्य संतोष करना चाहिए कि हमने निर्णय लिया है लेकिन जहां साथ साथ वह बातें ध्यान में न आई हों, कमी हो, उसके लिए जागरूकता बरतनी चाहिए जिसे सुधार सके और आने वाले वर्षों में उस काम को पूरा करके जिस ध्येय से योजना बनी है उस ध्येय को ठीक तरह से प्राप्त कर सकें।

इसलिए इसके तीन मुख्य आधार पर, इस योजना के तीन मुख्य आधार पर अपने विचार करूंगा। पहला कि हमें राजस्थान की स्थिति को देखते हुए किन चीजों पर प्रायोरिटी देनी चाहिए, कौनसी वे चीजें हैं कि जिन पर पहले ध्यान दिया जाना चाहिए। दूसरा यह कि जो कार्य हम करना चाहते हैं उसके लिये उपयुक्त साधन किस प्रकार और कहां से उपलब्ध करने चाहियें।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

तीसरा यह है कि हम उन योजनाओं के जरिये अन्त में सामाजिक दृष्टि कोण से क्या नतीजा हासिल करना चाहते हैं, कितने करोड़ रुपयों की धन राशि खर्च कर रहे हैं। तो हमारे सामने यह प्रश्न आता है कि समाज के इस ढाँचे में परिवर्तन करने की दृष्टि से किस हदतक हम लोगों के स्तर में, हमारी संस्कृति में, राजस्थान की भूगर्भ सम्पति को बढ़ाने में और लोगों की आर्थिक हालत को ठीक करने का जो फिजीकल टारगेट है कि आम लोगों के जीवन स्तर को उत्तरोत्तर उन्नत किया जाय उसमें हम कहां तक सफल होते हैं इस पंच वर्षीय योजना द्वारा, यह देखने की बात है।

जो योजना, योजना कमीशन द्वारा मन्जूर हुई है जिसका कि कल मुख्य मंत्री ने काफी विस्तार से हमारे सामने उल्लेख किया इसमें हरी के बान्ध को छोड़कर १२० करोड़ रुपये की योजना मानी जानी चाहिये और जहाँ तक मैं इसे देख पाया हूँ, बहुत बड़ा भाग, लगभग पचास प्रतिशत से ज्यादा अंश खेती में, सिंचाई के साधनों में तथा सड़कों पर खर्च किया जाना वाला है; यह इस योजना द्वारा हमारे सामने रखा गया है।

इस योजना के अनुसार एग्रीकलचर इरीगेशन और रोडवेज के लिये लगभग ६७ प्रतिशत रुपया इसमें खर्च करने का अनुमान रखा है जो पचास फीसदी से भी ज्यादा है।

दूसरा इस अंग योजना का है वह है सामाजिक सेवाओं का; जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, नेशनल एक्सटेंशन ब्लॉक्स, कम्युनिटी प्रोजेक्टस, सहकारी समितियां, पिछड़े हुए क्षेत्र की उन्नति, विशेष सहायता यह भी इस योजना का अंग है। शिक्षा के लिये लगभग १० करोड़, स्वास्थ्य के लिये लग-भग १० करोड़, इसी प्रकार अलग अलग आइटम्स हैं, जो सम्पूर्ण योजना के दस प्रतिशत से कम हैं। लेकिन सब कुल मिलाकर काफी बड़ा अंग इस योजना का बन जाता है इन चीजों से।

वास्तव में देखा जाय तो यह पंचवर्षीय योजना इन दो मुख्य स्तंभों पर आधारित है। सिंचाई के साधन और सामाजिक सेवा ये दोनों ही राजस्थान की किसी योजना के मुख्य आधार होने चाहिये, इसमें दो राय नहीं हो सकती।

इसके अलावा भी आज हमारे सामने एक विशाल क्षेत्र है जिसका ३/५ भाग रेगिस्तान है और जहाँ सिंचाई के साधन दूसरे क्षेत्र के मुकाबले कहीं ज्यादा हैं। इतने ज्यादा हैं कि मेरा अनुमान है कि इन योजनाओं के पूरा करने के बाद भी, उन्नति और तरक्की हो जाने के बाद भी हम दूसरे क्षेत्र के मुकाबले काफी पीछे रहेंगे।

जो आँकड़े इस सिलसिले में उपलब्ध हैं सन् ५१ के, उसके अनुसार राजस्थान का कुल ८।६ फीसदी सिंचित जमीन है जिनमें नहर, तालाब, कुओं आदि से सिंचीं जाने वाली जमीन का जोड़ लगाकर हिसाब लगाया गया है।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

दो फसली के आँकड़े कोई विशेष नहीं हैं और वे उपलब्ध भी नहीं हैं। इसके मुकाबले पेप्सू में १९५१ में सिंचित जमीन ४४।८, पंजाब में ४०।२ और उत्तर प्रदेश में २६।१ पोइन्ट हैं। और इन्हीं क्षेत्रों में दो फसली सिंचित भूमि क्रमशः १६।१६, और २४ परसेन्ट के आंकड़े हैं इस पर दो राय नहीं हो सकती कि जिस क्षेत्र में केवल ८, ६ या १० फी सदी सिंचाई की व्यवस्था हो उस क्षेत्र में सब से पहले सिंचाई की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये। इसके बिना यह प्रान्त अपनी उन्नति में अग्रसर नहीं हो सकता। राजस्थान में भांखरा योजना, चम्बल योजना से जो सिंचाई होने वाली हैं और जिसे हम कामयाबी का बहुत बड़ा पैमाना मानते हैं लेकिन इससे भी बड़ी और महत्वपूर्ण योजना राजस्थान के लिये है और वह है हरीके योजना। हम यह मानकर चलें कि यह मन्जूर शुदा है, अलबत्ता भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ बातों के लिये समझौता होना है शायद इस संबन्ध में आज मुख्य मंत्री कोई घोषणा न करें लेकिन मैं यह मानकर चलूंगा कि यह योजना मन्जूर है और यह राजस्थान की प्रमुख केनाल योजना है।

इस प्रकार की योजनाओं का और छोटी-मोटी योजनाओं का उल्लेख इस पंचवर्षीय योजना में किया गया है। राजस्थान की उन्नति की दृष्टि से राजस्थान के किसानों के हित की दृष्टि से यह योजना ठीक है, सन्तोषप्रद है और सही रास्ते पर चलने वाली एक चीज है। इसकी तफसील में ज्यादा न जाते हुए मैं इतना ही कहूँगा, काफी उदारता से समझ लीजिये, मैं तो यह कहूँगा कि काफी हिम्मत से कुछ धन राशि रखने के बारे में इस योजना में प्रयत्न किया गया है। उससे अधिक सीमा के अन्तर्गत होना आवश्यक है। लेकिन मैं यह मानता हूँ कि इस योजना में एक गम्भीर-स्वरूप की बुनियादी कमी है जिसे मैं दृष्टिकोण की कमी मानता हूँ। यहां आकड़ों का प्रश्न नहीं, यह दृष्टिकोण की कमी है। वह यह है कि इस पूरी की पूरी योजना के दो आधार स्तम्भ सही होते हुए भी तीसरा एक महत्वपूर्ण आधार स्तम्भ है। उसकी कमी है वह है उद्योग। मैं यह भी मानता हूँ कि आप इस योजना के जरिये नये नये सिंचाई के साधन उपलब्ध करेंगे। राजस्थान में खेती को उत्तरोत्तर वृद्धि का प्रयत्न करेंगे, खेती की उन्नति के लिये टूल्स इम्प्लीमेन्ट्स मेन्योर्स इन सब चीजों के लिये उद्योगों के बिना इस नई प्रकार की खेती का आधार निर्माण नहीं किया जा सकता।

राजस्थान की ८५ प्रतिशत आबादी इस पर आधारित है। देहातों में बड़ी सिंचाई योजना लागू करने के बावजूद भी हम जनता के बहुत बड़े हिस्से को हमारे सबल नव जवानों को उद्योगों में लगाकर नये प्रकार के आजीविका के साधन उपलब्ध नहीं करा सकेंगे तब तक हमारी बेकारी खत्म नहीं हो पायेगी। इस दृष्टिकोण से उद्योगों के महत्व को मैं बुनियादी महत्व मानता हूं। इतनी ही बात नहीं, पहले मैंने जिन बातों का जिक्र किया नई सड़कों के बन जाने के बाद भी बिजली और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर के मिलने के साथ साथ भी इन सिंचाई योजनाओं के जरिये नये मेटीरियल्स पैदा हो जाने के बाद हमारी उन्नति की ओर बढ़ने का रास्ता खुल जायगा। हमारे यहां जितने भी रॉ मेटीरियल्स होते हैं उनको प्रयोग में लायेंगे। आखिर बिजली किसके लिये काम

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

आयेगी, कहां इस्तैमाल होगी इन चीजों का समन्वय करके जब तक हम इन चीजों का उत्पादन यहां नहीं बढ़ायेंगे, इन चीजों के उद्योगों का प्रयत्न नहीं करेंगे तब तक राजस्थान की उन्नति की दृष्टि से यह योजना अधूरी योजना है।

सभापति महोदय, भारतवर्ष का जो दूसरा फाइव ईयर प्लान बना है और जो बहुत ही जल्दी मुकम्मिल रूप से हमारे सामने आने वाला है उस प्लान फ्रेम का अगर कोई आधार है तो वह उद्योग है। उसमें ५,५०० करोड़ रुपये की धनराशि इस योजना के अन्तर्गत रखी है जिसका बहुत बड़ा भाग बड़ी योजना में लगाने का इस प्लान में जिक्र है। स्टील मशीन बिल्डिंग, केबल्स, फरटीलाइजर्स, लोकेमोटिव्ज़, रोड रोलर्स आदि उद्योगों के शुरू करने का उल्लेख स्टेट सेक्टर में है। हमारी राजस्थान की द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाने वालों का ध्यान इस बुनियादी दृष्टिकोण का पालन करने में नहीं गया। हमारे पास साधन कितने हैं, कितने नहीं इसका जिक्र मैं बाद में करूंगा; लेकिन जितने भी साधन हैं उनमें से किन वस्तुओं को, किन चीजों को प्रायोरिटी देते हैं लेकिन जहां तक मैं इस योजना को देख पाया हूं उसमें उद्योगों के प्रति बहुत कम प्रायरिटी दी गई है।

छोटे छोटे उद्योगों के लिये पॉवर टेक्निकल ट्रेनिंग की सहायता; अमोनियम सल्फेट आदि चीजों का उल्लेख है। जब मैं उद्योगों के बारे में तफसील में जाउंगा तो मैं आपको बताउंगा, जिन उद्योगों का मैं उल्लेख कर रहा हूं उनका उल्लेख, यहां से जब प्लान प्लानिंग कमीशन को सबमिट की गई थी उसमें अवश्य है लेकिन मंजूरशुदा प्लान में उसका उल्लेख नहीं है। जैसी कि मुझे सूचना मिली है स्टेट सेक्टर में नहीं करने का राजस्थान ने निर्णय लिया है। इसलिये योजना कमीशन ने उसको काट दिया है जिसका नतीजा यह हुआ कि यह योजना पब्लिक सेक्टर के तौर पर होगई। दूसरा आधारभूत काम है वह, मैं यह मानता हूँ...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—क्या आपका मतलब पार्टीसिपेशन के लिये रखा गया है, उससे है क्या ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—जो प्राइवेट सेक्टर और स्टेट सेक्टर से संबन्धित है, उससे है। दूसरी योजना की जो बुनियादी खामियां हैं मैं मानता हूं कि वे यह हैं।

(१) खेती की उन्नति के लिए, कृषि की उन्नति के लिए भी केवल एक ही चीज पर जोर दिया गया है, वह है सिंचाई के साधन। कोई भी समाजसेवी अथवा अर्थशास्त्री इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि कृषि की उन्नति के लिए सिंचाई के साथ साथ और दो चीजों की आवश्यकता है। एक आवश्यकता होती है केपिटल फोर्मेशन की। खेती को उपार्जन का इस प्रकार का तरीका बनाया जाय कि जिसमें से कुछ न कुछ लगातार बचत होती रहे; वो बचत टेकनिकल

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

उन्नति के लिए प्रयोग में आ सके और दूसरी, इस प्रकार को उन्नति के लिए भूमि संबंधों में बहुत ही तात्विक और बुनियादी किस्म का सुधार हो। स्थिति यह है, सभापति महोदय, कि राजस्थान में भूमि सुधार के सिलसिले में जो कुछ भी प्रयत्न किये गये हैं उनके बारे में मेरी क्या राय है, क्या नहीं है, उस चीज़ का जिक्र नहीं करते हुए जो कुछ भी परिवर्तन किये गये हैं उसको मानते हुए अभी हमें सबसे पहला जो कदम लिये जाने की जो आवश्यकता है वह सीलिंग कृषि का तात्कालिक और तुरन्त रूप से किया जाय। यदि हम भूमि संबंधों को सुधारने के लिए प्रयत्नशील हैं तो जो खेती के टेक्निकल संबंध हैं उनमें परिवर्तन किये बगैर उन्नति का होना बहुत हद तक संभव नहीं है और तीसरी चीज यह है कि खेती में आज राजस्थान में सदियों से जो टेकनिकल बातें काम में लाई जाती थीं आज भी वे प्रयोग में लाई जा रही हैं। उनको यदि दूर करना है तो काफी मात्रा में रूरल क्रेडिट के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। इस योजना में कोआपरेशन के तहत लगभग पौने तीन करोड़ रुपये हैं। जहां तक मुझे याद है २,७२,००,०००) रु० रखे गये हैं, और मैं भी मानता हूं कि वह धनराशि कुछ अंशों में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कर्ज के रूप में उपलब्ध करा कर कई प्रकार के रूरल क्रेडिट के लिए प्रयोग में आयेगी। अलबत्ता इस धनराशि में से कुछ प्रशासनिक खर्च में काम आयेगी, लेकिन कुछ अंश उसका रूरल क्रेडिट के रूप में काम आयेगा। इसके साथ साथ इस योजना के पहले पेज में इस बात का उल्लेख है कि लगभग डेढ़ या पौने दो करोड़ जो हमें इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण होने के बाद रिजर्व बैंक से मिलेगा, रूरल क्रेडिट में उसका समावेश इस योजना में नहीं किया गया है। दोनों का यदि जोड़ लगाया जाय तो तीन, सवा तीन करोड़ की कुल धनराशि हमारे सामने आती है। राजस्थान में उद्योगों को क्रेडिट देने के लिए एक फाइनेन्स कॉरपोरेशन का निर्माण हुआ है जिसका नाम कुछ चन्द उद्योगों व उद्योगपतियों को उसमें रख देने का है। उसके लिए हमने एक करोड़ की धनराशि की पूंजी आवश्यक समझी और आगे चलकर उस पूंजी को बढ़ाने के बारे में विचार है। लेकिन करोड़ों जो इस नये उद्योग के करने वाले लोग हैं, जिन्हें कि राजस्थान का किसान कहते हैं उनके सामान को खरीदने के लिए क्रेडिट नहीं होने की वजह से समय पर बीज और खाद उपलब्ध नहीं होने की वजह से, क्रेडिट नहीं होने की वजह से खेती के तरीकों में पिछड़े हुए हैं। उसके लिए बहुत बड़ी योजना के आधार पर रूरल क्रेडिट शुरू नहीं किया जाय, देहातों के अन्दर जब तक बहुत कम ब्याज, लगभग कुछ नहीं ब्याज, पर क्रेडिट न दिया जाय, उनका सामान रखने के लिए वेयर हाउसेज़ की योजना नहीं बनाई जाय, तब तक खेती की उन्नति जल्दी से जल्दी होने की संभावना नहीं करनी चाहिए। इस वजह से इन तीन खामियों को इस योजना में मैं मानता हूँ। सबसे पहले बड़े २ उद्योगों की ओर ध्यान नहीं दिया, दूसरी खामी रूरल क्रेडिट पर कम ध्यान दिया और तीसरा इनका सामाजिक असर है, जिनमें सबसे पहला असर किसानों की जमीन स्थाई रूप से फिक्स करने का है। उसके प्रति भी कम ध्यान दिया गया है। इन तीन बातों की खामियां इस योजना में जहां तक इसके प्लान फ्रेम का सवाल है। मैंने जो अर्ज किया उसके पक्ष में एक पैराग्राफ को आपकी अनुमति से कुछ अंश में कोट करना चाहूँगा। उसके पढ़ने के बाद शायद

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

यह महसूस हो कि उस पैरेग्राफ का कहने वाला मेरे ही विचार से एकमत कोई व्यक्ति है। लेकिन शायद बाद में यह पता लगा कि यह पैराग्राफ खुद राजस्थान सरकार ने अपने सैकन्ड फाइव इयर प्लान के प्रोपोजल्स के पेज ११ में लिखा है, पहली पंचवर्षीय योजना का रिव्यु करते हुए उसमें यह लिखा है :

" Although much headway has been made under Irrigation and Roads and steps taken towards the generating of cheap power, yet at the end of the First Plan, Rajasthan still presents a grim picture of backwardness and under development. "

"With famines and scarcity conditions, there is hardly any year in which relief operations are not necessary in some part of the State. With a peasantry periodically on the verge of starvation, the cattle are stunted and impoverished. Stall-Feeding is unknown."

"Turning to public health, there is no town in the State which has got both pipe water supply and drainage in full, etc."

" Organised industries hardly exist and although the artisans have preserved their artistic talents and craftsmanship, still finance and marketing arrangements are wanting to encourage workers and prevent exploitation. "

इस प्रकार से जो नतीजा पहली पंचवर्षीय योजना के कार्यों से हमने निकाला है उन नतीजों का कुछ फायदा होता, यदि उनके आधार पर हम कुछ कदम इस दूसरी पंचवर्षीय योजना में उठाते।

मैं अन्त में केवल एक बात और अर्ज करूंगा कि इस योजना की अलग अलग तफसीलों में कुछ मेरे सुझाव, कुछ मेरी योजनाएं या कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके प्रति मैं अपना असन्तोष प्रकट करना चाहूंगा। वह यह है कि चाहे कुछ भी किया है, लेकिन हिन्दुस्तान के दूसरे राज्यों के उद्योगों की दृष्टि से राजस्थान एक बहुत ही पिछड़ा हुआ प्रदेश है। सिर्फ भारत में इन्डस्ट्रियल वर्किंग क्लास की आबादी लगभग देश की आबादी की एक फी सदी है और अभी पिछले चार साल के अन्दर उसमें तरक्की हुई है और ऐसा अनुमान है सेन्ट्रल स्टेटिस्टिकल ब्यूरो का कि वह पोने दो फी सदी तक पहुँच गया है। लेकिन राजस्थान में औद्योगिक मजदूरों की तादाद यदि हम गिनें तो एक हजार से ज्यादा जिस कारखाने में काम करने वाले मजदूर हैं ऐसे सरकारी या गैर सरकारी मिलाकर कुल १३ कारखाने राजस्थान में हैं जिनमें ३०००० से ज्यादा औद्योगिक मजदूर काम नहीं करते हैं। फेक्ट्री एक्ट जिनके अन्दर लागू होता है ऐसे औद्योगिक मजदूरों की तादाद को गिन

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

लें तो एक फी सदी से बहुत कम, लगभग आधे अन्श में उसकी स्थिति राजस्थान में औद्योगिक मजदूरों की आयेगी। जिस क्षेत्र का इतना बड़ा औद्योगिक पिछड़ापन हम चिल्ला २ कर, पुकार २ कर कह रहे हैं, हमारे सामने आ रहा है, उसके बारे में, जब कि आपने हजारों बातों के बारे में ध्यान रखा, तो उसके बारे में केवल ११ करोड़ के लगभग ऐसे रुपयों का प्रोवीजन करना जिसमें कि स्टेट सेक्टर और बड़े बड़े उद्योगों का जिक्र नहीं है, मुझे नाकाफी मालूम होता है।

प्लान फ्रेम की इन चीजों के उल्लेख करने के बाद अब मैं कुछ चन्द बातें इस योजना के अलग अलग अंश के बारे में अर्ज करना चाहूंगा। जैसा कि मैंने कहा कि सिंचाई सम्बन्धी जो भाग इस पुस्तक का है वह कृषि सिंचाई सम्बन्धी इस योजना का भाग सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अधिक ठीक भाग है। न सिर्फ बड़ी २ योजनाओं का उसमें उल्लेख है, लेकिन छोटी सिंचाई की योजनाओं का भी उसमें उल्लेख है और योजना के जो भाग हैं उस दृष्टि से मैं मानता हूं कि ध्यान देने की दृष्टि से सिंचाई की ओर कम ध्यान नहीं दिया गया, ऐसा कहा जा सकता है।

सामाजिक सेवाओं में शिक्षा के बारे में यह मानते हुए कि काफी ध्यान इसमें रखा गया है, लेकिन यदि हम वर्तमान स्थिति से तुलना करेंगे तो मैं समझूंगा कि वह अपर्याप्त गिनी जानी चाहिए। जैसा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने खुद बताया है कि राजस्थान में इस पहली योजना के शुरू होने से पहले शिक्षा की यह स्थिति थी, उस समय के आंकड़े ९ साल से १४ साल तक की एज के लड़कों के उपलब्ध थे। मुझे नहीं मालूम कि इस बीच में ११ साल तक के आंकड़ों को अलग और ११ साल से १४ साल तक के आंकड़े अलग किस कारण, किस बिना पर किये गये? लेकिन पहले ६ से १४ साल तक के आंकड़े उपलब्ध थे कि उस एज के लड़कों के स्कूल जाने के आंकड़े १४ प्रतिशत थे। उन्होंने रिजल्ट करके इस पंचवर्षीय योजना के पूरे होने तक जो स्थिति शिक्षा की होगी वह स्थिति खुद राजस्थान सरकार के अंकों के अनुसार ६ साल से ११ साल तक की उम्र के लड़के हैं उनमें ३६.५६ लड़के स्कूल जा पायेंगे और ११ साल से १४ साल तक की उम्र के लड़कों में से केवल १० परसेंट ही स्कूल जा पायेंगे और यह पूरा का पूरा कार्य पहली योजना के पूरी तरह होने के बाद दूसरी योजना के पूरे होने तक जैसा कि कल ही हमारे सामने जिक्र किया गया है ६ साल से ११ साल तक के स्कूल गोइंग एज के लड़कों में से ५५ प्रतिशत स्कूल जा पायेंगे और ११ साल से १४ साल तक की स्कूल गोइंग एज के लड़कों में से ४० प्रतिशत स्कूल जा पायेंगे। वैसे एप्रोक्सीमेट एवरेज लिया जाय तो ४५ परसेन्ट का आंकड़ा उसका मानेंगे यानी स्कूल गोइंग एज के लड़कों में से ४५ परसेन्ट स्कूल जा पायेंगे। मेरा अनुमान है उसी अरसे में दूसरे राज्यों में, मैसूर जैसे दूसरे बहुत से शिक्षा की दृष्टि से उन्नतिशील राज्य हैं उनका जिक्र शायद करने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन और भी दूसरे राज्य हैं सारे भारत में एवरेज आंकड़े, लगभग ७५ प्रतिशत स्कूल गोइंग एज के लड़के स्कूल जा पायेंगे इसकी व्यवस्था करने का है। तो मैंने केवल इस बात का इसमें उल्लेख किया है कि पहले ध्यान इसमें रखा गया है वह संतोषप्रद है, लेकिन फिर भी फ्लुसेन्सी का ध्यान नहीं है। यह मानने की कोई आवश्यकता नहीं है

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

कि बहुत बड़ी उन्नति के आधार को हमने निकाल लिया है। अभी भी आधे से ज्यादा स्कूल गोइंग एज के लड़कों के स्कूल जाने की व्यवस्था नहीं हो पायेगी इस योजना के पूरा होने के बाद भी। यह अपर्याप्तता शिक्षा जैसी सामाजिक सेवाओं के बारे में है।

इस अपर्याप्तता के अलावा और भी खामियां हैं। शिक्षा के सिलसिले में जो बहुत बड़ी खामी मानता हूं इस योजना के अन्दर, वह यह है कि इसमें एडल्ट एजुकेशन के बारे में बिल्कुल कम ध्यान दिया गया और एडल्ट एजुकेशन से मेरा तात्पर्य केवल अक्षर ज्ञान से नहीं है। अक्षर ज्ञान एडल्ट एजुकेशन में तो हो ही, लेकिन जो लोग जिस धन्धे में, उद्योग में काम कर रहे हैं, रोज़गार में हैं उनको टेक्निकल ट्रेनिंग करा के हमारे आगे की योजनाओं के लिए जो परसोनल्स चाहिए उनकी ट्रेनिंग के बारे में शिक्षा की व्यवस्था इस योजना में नहीं है। नये विद्यार्थियों के बारे में, उनकी शिक्षा की व्यवस्था के बारे में केवल जिक्र है। यह इसकी एक खामी मानी जानी चाहिए। उस आधार से इस योजना में शिक्षा के लिए जो टेक्निकल आधार को प्राथमिकता दी गई है वह भी एक ठीक काम की चीज है। उसे और तेज किया जाना चाहिए।

और अन्त में मैं कहूंगा शिक्षा के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में भी, विशेष ध्यान रखने के बारे में उल्लेख इस योजना में नहीं है। उसके बारे में कोई जिक्र, प्रोवीज़न के रूप में या और किसी रूप में हमारे सामने आया हो तो अपर्याप्तता के अलावा टेक्निकल ट्रेनिंग और एडल्ट ट्रेनिंग इनके बारे में खामियां शिक्षा की योजना में मुझे नज़र आती हैं।

जहां तक स्वास्थ्य का सम्बन्ध है उसमें यह व्यवस्था की गई है कि इतने हजार की आबादी के क्षेत्र में एक अस्पताल होगा और इतने हजार की आबादी के क्षेत्र में एक औषधालय होगा। इस दृष्टि से योजना बनाना वास्तव में ठीक चीज है जिससे कि कोई खींचातान और वहां यहां के इस प्रकार के प्रश्न जहां तक सम्भव हो आयें ही नहीं। लेकिन फिर भी स्वास्थ्य की ओर, जन स्वास्थ्य की दृष्टि से एक बहुत बड़ा अंग अब भी भुलावे के रूप में रखा गया है। मैं कहता हूँ कि राजस्थान के मौजूदा भूभाग में फैली हुई बीमारियों से लड़ने का सवाल है। कोई भी आदमी जानता है कि राजस्थान के बहुत बड़े भूभाग में मलेरिया एक एपीडेमिक डिजीज़ हो चुका है। जो इसके जानने वाले हैं वे कहते हैं कि मलेरिया को एपीडेमिक में नहीं गिना जाना चाहिये, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि ऐसी स्थिति है कि साल दर साल लगातार मलेरिया वहां होता है। लोगों के जब खेती करने का वक्त होता है तो लोग इस बीमारी के कारण, शारीरिक कमजोरी के कारण खेती के काम पर नहीं जा सकते हैं। कहीं एक–दो नहीं लेकिन हजारों, लाखों की तादाद में लोग इस बीमारी के शिकार बने हुए बैठे हैं। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि यह बीमारी ऐसी नहीं है कि जिसको इन्सान खत्म नहीं कर सकता हो। कई देशों में इसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। मलेरिया के ५, ६ यूनिट का इस प्रकार से उल्लेख करने के अलावा स्वास्थ्य के सिलसिले में इस प्रश्न पर उतना ध्यान नहीं दिया गया है। उन्हें

Page No.30

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

पूरी तरह ध्यान देना चाहिये। यह केवल बीमारी ही नहीं है लेकिन इसका सम्बन्ध हमारी आर्थिक स्थिति से है। राजस्थान में इसने लाखों लोगों को अशक्त बना दिया है। काम करने के लिए उनको बेकार बना दिया है जिसका असर हमारी खेती पर, हमारे धन धान्य पर पड़ता है; हमारे खाने पीने की चीजों पर पड़ता है।

ऐसी ही खतरनाक बीमारी मैं मानता हूं कि नहरू की है। जिस क्षेत्र का मैं जिक्र करूंगा। उसमें मैंने बराबर देखा है, मेरा खयाल है, सदन में उधर बैठे हुए कई माननीय सदस्यों ने भी देखा है कि वह बीमारी किस तरह से मनुष्य को बेकाम बना देती है। गांव के गांव में, क्षेत्र के क्षेत्र में जब बरसात शुरू होती है उसके बाद यह बीमारी शुरू होती; है उस समय ऐसी स्थिति होती है कि एक घर में ४, ६ आदमी होते हैं लेकिन इस बीमारी के कारण अशक्त होकर पड़े रहते हैं। उनके नुकसान के साथ ही हमारे क्षेत्र का, राज्य का नुकसान होता है, उसका राजस्थान से नामोनिशान मिटाने के लिए एक बड़ी भारी मात्रा में योजना बनाई जानी चाहिये। In a big way बनाई जानी चाहिए। लेकिन अफसोस है कि उस बड़े कार्य का योजना में कहीं जिक्र नहीं है।

तीसरा मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा; इस विषय पर विचार प्रस्तुत कर ही दिए हैं—उद्योग और खनिज पदार्थों को पर्याप्त रूप में काम में लाने के बारे में। मेरे माननीय मित्र विरोधी दल के नेता ने उनमें से एक चीज की ओर ध्यान दिलाया और वह है ऊन उद्योग पर। शायद सदन में से उपस्थित महोदय इस बात से परिचित नहीं हैं कि राजस्थान में जो ऊन है वह एक्सपोर्ट तो होती ही है, लेकिन यहां से यू. पी. सरकार उस ऊन को खरीद कर ले जाती है और अपने कॉटेज इन्डस्ट्रीज़ के महकमे में कम्बल बनाकर भारत सरकार के डिफेन्स डिपार्टमेंट को हर साल लगभग ६ से १० लाख का सामान सप्लाई करती है; राजस्थान से ऊन ले जाकर अपने कॉटेज इन्डस्ट्रीज़, छोटे उद्योगों के जो सेन्टर्स हैं उनमें कम्बल तैयार करवा कर भारत सरकार के डिफेन्स डिपार्टमेंट को यू. पी. सरकार देती है। यू. पी. सरकार इस प्रकार से उस कार्य से, इससे हमे कोई ईर्ष्या नहीं है लेकिन अफसोस है कि जिस भूभाग में वह ऊन पैदा होती है; आज भारत के ४।५ ऊन का प्रोडक्शन यहां होता है। वहां उस प्रोडक्शन का उस उद्योग के बारे में कोई जिक्र नहीं हो, यह हमारे और सबके लिए बहुत ही गलत तरीके की चीज है, आम लोगों को जीविका नहीं मिलने की चीज है, राजस्थान के लोगों को धन्धा नहीं मिलने की चीज है। मैं मानता हूं कि छोटे-मोटे उद्योगों के सिलसिले में इस समस्या को सोल्व किया जा सकता है। पब्लिक सेक्टर से सामने आने वाले को कर्जा देकर शुरूआत करायें या राजस्थान सरकार इस तरह की शुरूआत करे। ऊन, लेदर और लेदर टेनेरीज़, सेडलरी सब चीजें इन्क्लुड करना है।

हिन्दुस्तान में भेड़ों की जितनी तादाद है उसमें से, यदि मैं भूल नहीं करता हूं, तो लगभग तीन चौथाई भाग राजस्थान में है। इसमें लगातार कमी आ रही है, लेकिन अब भी ऊन यहां काफी

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

मात्रा में मिलती है। ऊन को काम में लाने का कोई उद्योग हमारे यहां नहीं है। इसकी बहुत कमी महसूस होती है। कम से कम ये तीन ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में राज्य सरकार को आगे आकर इनके उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिये। सांभर में जो नमक पैदा होता है उसमें प्रयोग करने की आवश्यकता है, सोडियम सल्फेट का इलाका है उसमें भी काफी तरक्की हो सकती है। हमारे यहां खनिज पदार्थों की कमी नहीं है। दुनिया में जितना अभ्रक होता है उसका ६० परसेन्ट हिन्दुस्तान में होता है और सारे हिन्दुस्तान का ६० परसेन्ट अभ्रक होता है राजस्थान में। माइका के उद्योग की यह स्थिति है कि मुख्य मंत्रीजी ने फरमाया था कि...

श्री मोहनलाल सुखाडिया—It is not sixty percent of India.

श्री हरिकृष्ण व्यास—The marketing is more developed in Bihar and Madras but the quantities of mica available in Rajasthan, as assessed by Shri Vishweshwaraiya, is near about 57 or 58 percent.

माइका जो राजस्थान में है वह सारे हिन्दुस्तान में नहीं है। तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि चाहे ६० परसेंट हो वह डिस्प्यूट नहीं, वह तो दुनियां की ६० फी सदी से हिन्दुस्तान के ६० फी सदी के आंकड़े मिलाने चाहे थे।

इस उद्योग की स्थिति यह है कि आज यह उद्योग कम पड़ रहा है और इसके कम पड़ने के कारण बेकारी बढ़ रही है और एक बहुत बड़ी सम्पत्ति राजस्थान की बेकार है। वह क्यों? इसलिए कि सारे भारतवर्ष ने जो इतने वर्षों तक खोया है, वह राजस्थान आज खो रहा है।

पिछले ६ वर्षों से भारत बड़े उद्योगों के लिए, मशीनों के लिए, कारखानों के लिए इंग्लैंड और अमेरिका की ओर ताकता रहा है। पर अब भारत ने उद्योगों की दृष्टि से समझा है कि जिन देशों के साथ भारत बराबरी का नाता जोड़ सकता है उनके साथ ही व्यवहार करना चाहिए और कम कर्ज पर हिन्दुस्तान की पूरी मिल्कियत के आधार पर सामान लेने का भारत ने सोवियट यूनियन के साथ कन्ट्रेक्ट किया है। ऐसा करके भारत ने सोवियट यूनियन पर और सोवियट यूनियन ने भारत पर कोई अहसान किया हो, ऐसी बात नहीं है।

माइका ऐसी वस्तु है जिसके उद्योग का गला घोंटने के इरादे से इंग्लैंड और अमेरिका एंग्लो अमेरिकन मार्केट की आज कीमतें दबा कर बैठे हैं। भारत तो एक बाहर भेजने वाला देश है, ऐसी सूरत में एक्सपोर्ट में पूरी कीमतें नहीं मिलती हैं; तो यह सारा का सारा उद्योग चौपट हो जाता है।

मेरी राय है कि ऐसे उद्योगों के बारे में चाहे वह माइका हो या और कोई भूगर्भ सम्पत्ति हो, राजस्थान सरकार को इनके लिए एक स्टेट बिल्डिंग कॉरपोरेशन खोलना चाहिए और सोचना

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

चाहिये कि अंग्रेज और अमेरिका हमारी ये चीजें कम कीमतों पर खरीदना चाहते हैं तो दूसरे भी ऐसे देश हैं कि नहीं कि जो हमारा यह माल खरीद सकते हैं, माइका खरीद सकते हैं और इस तरह जो दूसरे देश हमारी माइका खरीद सकते हैं, उनके साथ एक दूसरे के सहयोग के आधार पर सम्बन्ध स्थापित करने चाहिये; फिर वे देश चाहे चीन हों, या जेकोस्लावाकिया हो या सोवियट यूनियन हो, उनमें हमें समान व्यवहार के आधार पर सम्बन्ध स्थापित करने चाहिए। हमारे माल की हमें जिस देश से अच्छी कीमतें मिल सकें उन देशों को हमें अपना माल देना चाहिए और इस तरह स्टेट ट्रेडिंग कोरपोरेशन के जरिये राजस्थान का हित हो सकता है।

हमारे यहां हाथी दांत के छोटे छोटे उद्योग हों, अथवा तरह तरह के कलरफुल डिज़ाइन्स की चीजों के उद्योग हों, उन छोटे छोटे उद्योग धन्धों की स्टेट ट्रेडिंग कोरपोरेशन के जरिये बहुत उन्नति की जा सकती है। जो एम्पोरियम दिल्ली में खोला है, वह इस बात का सबूत है कि न सिर्फ हिन्दुस्तान में, बल्कि हिन्दुस्तान से कहीं ज्यादा और दूसरे देशों में, फोरिन कन्ट्रीज़ में क्लब्स के लिए, और क्युरियोसिटीज़ के लिए मार्केट है।

ऐसा स्टेट ट्रेडिंग कोरपोरेशन का अगर कदम उठाया जाय तो इन चीजों को मार्केट के रूप में अन्य देशों के अलग अलग हिस्सों में ले जा सकते हैं और इस तरह एक अच्छा आधार हो सकता है हमारे राजस्थान के लोगों को जीविका देने का और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का।

कहा यह गया माननीय मित्रों द्वारा और विरोधी दल के नेता ने कहा कि करोड़ों उद्योग ऐसे हैं जिनको बढ़ायें तो आय बढ़ेगी, यह तभी बढ़ेगी जब कि स्टेट सेक्टर की नींव डालेंगे और सरकार मार्ग निर्देशित कर देगी। राजस्थान में जब तक स्टेट सेक्टर क्रियेट नहीं किया जाता तब तक बड़े उद्योगों की कल्पना करना कोरी कल्पना मात्र है, कोरा स्वप्न है। पिछली पंचवर्षीय योजना में जो २ करोड़ रुपया इस पर खर्च किया गया, इतनी बड़ी पूंजी लगाने पर भी जो जो पूरा हुआ है वह हमारे सामने है, २ करोड़ रुपया राजस्थान सरकार ने लगाया पर उसका जो नतीजा है वह आज हमारे सामने है। ७५०००० रुपया तो ऐसे सज्जन के हाथों में है जिसने कि इन्श्योरेंस की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का दो करोड़ रुपया हड़प कर लिया और इसके लिए गिरफ्तार किये गए, राजस्थान सरकार को भी अपना यह ७५०००० रुपया निकलवाने के लिए कुछ न कुछ प्रयत्न करना चाहिए। दफा १४४ प्रोसीजर की अथवा ३४ पुलिस एक्ट में सेल्स टैक्स में गिरफ़तार करावें, एक बार मौका आये तो डालमियां से ७५०००० का कुछ इन्तजाम किया जाय और आयन्दा के के लिए सबक लिया जाय कि इस प्रकार उद्योग पनप नहीं सकते।

स्टेट सेक्टर के निर्माण से ही उद्योग बढ़ेंगे। स्टेट ट्रेडिंग कोरपोरेशन के बारे में नहीं सोचने की ही खामी है। स्टेट ट्रेडिंग कोरपोरेशन से हमारे उद्योग धंधे बढ़ेंगे।

Page No.33

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

अन्त में जहां तक इस योजना को ठीक करने के बारे में सुझाव का प्रश्न है वह यह है कि टेक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी का बार बार जिक्र किया गया है। लोगों के संतोष की दृष्टि से समझ लीजिये, हमें अपनी योजना में इकोनोमी बरतनी पड़ेगी। आज भी यह स्थिति है कि बहुत बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार के कारण और बदहजमी के कारण हमारी योजनायें सफल नहीं हो पा रही हैं।

टेक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट के पेज एक पर उल्लेख किया है :

"We are ourselves impressed by the need for a thorough and careful enquiry both in the Central Government and the States into the whole question of public expenditure, and suggest that such enquiries should be undertaken by sufficiently high-powered bodies and at a fairly early date."

इसलिये कि कमीशन की राय है कि :

"Public expenditure in India has been moving increasingly towards beneficent expenditure but it cannot be said with equal certainty that is moving also towards economy and efficiency."

तो जैसा कमीशन ने उल्लेख किया है एफिशियेंसी और इकोनोमी का, मैं मानता हूं यह सबसे बड़ा काम इस योजना में मिलेगा। पहली योजना के आधार पर इसके बारे में तफसील में जिक्र करना ठीक नहीं। लेकिन मैं यह अवश्य मानता हूं कि इस बारे में सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर सरकार ने इस बारे में ध्यान दिया तो अवश्य बहुत कुछ बचत हो सकती है। और दूसरी रेवेन्यू का उल्लेख मैं काश्तकारों के उल्लेख के साथ करूंगा। इस योजना के बारे में जो सुझाव रखे गये हैं उसके बाद हम कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रश्न पर आते हैं।

माननीय मुख्य मंत्री ने पहली पंचवर्षीय योजना को अपर्याप्त बताया और उसका नतीजा यह हुआ कि आज जो इस योजना में कार्य होंगे उससे ३३ प्रतिशत भी काम नहीं हो पाया। कल चीफ मिनिस्टर बतला रहे थे कि इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस प्रकार से काम होगा और निधि का किस प्रकार प्रयोग किया जावेगा ? हम मानते हैं कि राजस्थान की मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए बिलाड़ा कस्बे को भी योजना में कुछ दिया जाना चाहिये। मैं आबादी के लिहाज से अर्ज करूंगा। आप यह कहेंगे कि परिवर्तन नहीं हो सकता तो मैं यह निवेदन करूंगा कि परिभाषा में परिवर्तन किये जा सकते हैं। यह सही है कि बजट के जानकारों ने आंकड़े देख कर ऐसा कार्य किया होगा लेकिन हम सदन के लोग भी इस बारे में काफी जागरूक हैं। उनको आंकड़ों की जानकारी हो लेकिन बहुत बड़े पैमाने में उन्नति के साधनों के बारे में जानकारी नहीं हो। मै कहूंगा, सिद्धान्त के तौर पर मेरे माननीय मित्र कुछ भी राय रखते हों और मैं कुछ भी राय रखता हूं, आखिर देश और कांग्रेस ने सोचा कि राजप्रमुख की प्रणाली नहीं रहनी चाहिये। इस

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

राज प्रमुख की प्रणाली को हटाने के लिये पांच वर्षों से हम कहते आ रहे थे कि यह नहीं रहनी चाहिये। उस समय आप कह रहे थे कि हम इसको कैसे छोड़ सकते हैं, यह हमारे विधान में रखी हुई है। मैं यह कहूँगा कि विधान में भी परिवर्तन होते हैं और किये गये हैं। इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण हो गया है और जो सोने की खानें हैं उनका भी राष्ट्रीयकरण हो गया और कई नये नये कदम सरकार द्वारा उठाये जा रहे हैं और उठाने पड़ेंगे। आज हमें उन सब पर विचार करना होगा। मैं केवल मेरे सिद्धान्त की बातों के बारे में मान सकता हूं। मुमकिन है दूसरे उधर बैठने वालों की मान्यता कुछ और हो। डेवलपमेंट के आधार बनाने के लिये केवल आमदनी दे दें या उसमें से कुछ दें, जो उनको मिल रहा है यह काफी नहीं। इसलिये मैं यह कहूंगा कि राजप्रमुख के लिये आप भारत सरकार से प्रार्थना करें कि जो करोड़ों रुपया आज इस पद पर खर्च हो रहा है उसको आप दें और इसके साथ साथ, मैं यह भी कहूंगा कि यदि राजस्थान की उन्नति की दृष्टि से आप चलना चाहते हैं तो इस पर विचार किया जावे कि आया राजप्रमुख को मुआवजा दिया जाना चाहिये या नहीं। इसके अलावा मेरा यह कहना है कि बड़े बड़े राजा हैं उनके मुआवजे में से क्रेडिट को ५ साल के लिये, मसलन जिसको १५ लाख रुपया सालाना मिलता है उसको १० लाख ही दिये जावें और ५ लाख रुपये इसके लिये लिये जावें और उनके इस मुआवजे को तीन चार साल तक के लिये पोस्टपोन कर दिया जाना चाहिये और वह रुपया देश के हित के लिये लगाया जाना चाहिये। अगर ऐसा किया जाए तो यह भी एक बहुत अच्छा जरिया है और इससे देश की बहुत उन्नति हो सकती है।

इसके अलावा मेरे माननीय मित्र, विरोधी दल के नेता ने अभी अपने विचार व्यक्त किये उससे मेरा मौलिक विरोध है। उन्होंने कहा कि अच्छे अच्छे ऑफिसर चम्बल और भाखरा के लिये रखे जावें और उन्हें यदि ५-५ हजार या इससे भी अधिक वेतन माहवार देकर बाहर से भी बुलाना पड़े तो भी बुलाये जाने चाहिये। इसके लिये जहां तक अच्छे और योग्य अफसरों का सम्बन्ध है, मैं मानता हूं कि अच्छे और योग्य ऑफिसर रखे जावें? लेकिन ज्यादा तनख्वाह देने के सम्बन्ध में मेरी यह मान्यता है कि अफसरों को तनख्वाह उनकी योग्यता पर निर्भर है और सबसे बड़ी काबलियत उनकी क्वालीफिकेशन से आंकी जाती है, न कि निधि से। इसके अलावा उनमें देश प्रेम की भावना भी होनी चाहिये। इसलिये पांच हजार या दस हजार रुपये माहवार देने की जरूरत नहीं है। मैं तो यह कहता हूं कि बड़ी २ तनख्वाह कट करके देश प्रेम से जो काम करने वाले आवेंगे वे सही काम करने वाले लोग होंगे और हमें उन्हीं लोगों के बारे में सिफारिश करनी चाहिये। इससे कुछ बचत हो सकती है और मेरा यह कहना है कि अगले ५ वर्ष में ज्यादा नहीं तो कम से कम कुछ लाख रुपया या एक १ करोड़ रुपया बचाया जा सकता है। काम करने वाले चाहे चपरासी हों, चाहे दूसरा कर्मचारी हों या चाहे मिनिस्टर हों मगर उनको अपने काम से संतोष होना चाहिये और देश प्रेम होना चाहिये।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

शिक्षा की योजना के साथ साथ मैं यह कहूंगा कि इसमें मास्टरों की तनख्वाह संतोषजनक नहीं है। इसमें भारत सरकार के आदेशानुसार नहीं हुआ। आज भी ऐसे बहुत से तबके के लोग हैं जिनकी स्थिति आज बहुत चिन्ताजनक हो रही है। इसलिये बड़ी बड़ी तनख्वाह कम की जाएं और उन लोगों को मिलनी चाहिये जिनको कम मिलती है। इसके अलावा राष्ट्रीय योजनाओं को कामयाब करने के लिये लाखों और करोड़ों लोगों का सहयोग मिलना चाहिये और वह तभी आपको मिलेगा जब प्रत्येक शख्स को कम से कम यह कहा जावे कि भाकरा और चम्बल की योजना के लिये श्रमदान दे। अगर आपको डाक्टर चाहिये और जब तक आप किसी से नहीं कहेंगे तब तक उसको कैसे पता लगेगा कि आपको देश सेवा के लिये इस प्रकार के आदमी की आवश्यकता है। इसके अलावा गांव में श्रमदान देने के लिये, श्रमदान देने की दलालें देने वालों को चाहिये कि पहले दूसरों के सामने खुद श्रमदान देकर मिसालें पेश करें, न केवल मिसालें ही पेश करें लेकिन सेवाओं के रूप में काम करें। इसके साथ साथ जैसा मैंने बताया कि अगर सरकार को १० करोड़ रुपये की जरूरत है, सबसीडोअरी (अश्रव्य) ५० प्रतिशत भारत सरकार से रिबेट ले लें इस तरह ५ साल में लगभग ५ करोड़ रुपया (अश्रव्य) इसके अलावा मैं समझता हूं कि बहुत बड़े साधनों का जरिया नोन टैक्स रेवेन्यूज का है। इसका जिक्र टेक्सेशन इन्क्वायरी रिपोर्ट में किया गया है। इस सम्बन्ध में ज्यादा समय न लेते हुए सिर्फ रिपोर्ट का उल्लेख करके छोड़ दूंगा। टैक्स के जरिये जो रेवेन्यू होती है उसके अलावा नोन टैक्स के बारे में उनका यह कहना है :

"Non tax revenues, however, from an important element in tho public finance of the country, both at the Central and the State levels."

उन्होंने दुनियां के अलग अलग देशों की स्थिति के बारे में विचार किया :

"In the countries with collectivist economies, of course, a predominant or larger part of publtic revenues is derived from non-tax sources; thus, normally only about ten percent of the public revenue in U.S.S.R. is derived from general taxation and loans, and the remainder, from the profits of national enterprises and the turnover tax on the products of public enterprises. State trading has often provided significant amounts of revenue. In most non-collectivist countries, however non-tax revenues still remain relatively unimportant, though such State activities in the economic sphere as give rise to non-tax incomes have, speaking generally, increased in recent years."

भारत में भी उसी सिलसिले में उन्नति हुई। जो जो कदम लिये गये उनके मुकाबले में, मैं समझता हूं, राजस्थान में तो नहीं के बराबर है। वैसे तो राजस्थान में इन्डस्ट्रियल अन्डरटेकिंग

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

नाम की चीज़ है लेकिन वह केवल है। बिजलीघरों के सिलसिले में हालत यह है, कि अब तक आमदनी उनके जरिये नहीं हो रही है। यह भी एक गंभीर विषय सोचने का सरकार के लिए होना चाहिए। मैं मानता हूं कि कुछ टेक्निकल साधनों के जरिये, कुछ ठीक बातों के जरिये और कुछ आवश्यकता पड़ने पर वहां पर काम करने वाले मुलाजिमों के जरिये यह मुनासिब है कि बिजलीघर हमको मुनाफा दें; मुनाफा ही नहीं, वे सरकार की रेवेन्यू का आधार बन जांय। इस प्रकार मैंने स्टेट्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के लिए निवेदन किया, वह भी पब्लिक सेक्टर का उद्योग है, रेवेन्यू का आधार बने। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इन साधनों के जरिये नोन टेक्सेशन की स्थिति पर आजांय, अगर पूरा नहीं आ सकें तो आधा आ जांय और आधा नहीं तो १।४ तक राजस्थान को नोन टैक्स पर आधारित कर पायें। यह चूंकि नहीं किया गया है इसलिए इस पूरी योजना में कमी रह गई, और वह कमी रहने की वजह से प्लानिंग कमीशन जितना उसको काट सकता था, उतना उसने काटा है। मैं नहीं मानता कि प्लानिंग कमीशन ने इस बिना पर काटा है कि राजस्थान को आवश्यकता नहीं है, प्लानिंग कमीशन ने इस बिना पर काटा है कि आपके पास साधन कहां, बगैर साधनों के कैसे चलेगा ? १० करोड़ की धनराशि की आवश्यकता थी वह पहले ही प्रोपोजल में कट गई। जितना डेफिसिट रखा था, उस डेफिसिट के अनुमान से, और प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की बात कही थी उतनी योजना को काट दिया। मैं कहता हूं कि यदि साधन उपलब्ध कर पायें और नई योजना कार्यान्वित कर पायें तो काटने की बात तो दूर रही इसको मान्यता मिलेगी। और उस अपर्याप्तता की कमी उन साधनों को इकट्ठा न करने की वजह से है बल्कि और भी खतरनाक चीज़ है और वह यह है कि साधनों के बारे में देखने में कुछ वक्रता आ गई है। इन पांच करोड़ रुपयों को नये टेक्सेज़ से वसूल करने के बारे में कल उल्लेख किया गया था माननीय मुख्य मन्त्रीजी द्वारा। जिसमें यह कहा गया था कि खेती पर लगान बढ़ा कर, टैक्स बढ़ावेंगे, कॉमर्शियल क्रोप पर बढ़ावेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, इसमें कहीं जिक्र नहीं है। बेटरमेंट लेवी लगावेंगे, उससे आमदनी होगी। तो इस प्रकार से पांच करोड़ रुपया राजस्थान सरकार टैक्स लगा कर वसूल करना चाहती है। ऐसी स्थिति हुई है कि जहां तक साधन उपलब्ध हो सके हैं उन साधनों को छोड़ा न जाय; इस दृष्टि से जहां कहां भी साधन उपलब्ध हों उन पर दौड़ दौड़ कर हाथ डालने की कोशिश करते हैं। मैं उल्लेख करूंगा अभी हाल ही में जयपुर शहर में चुंगी बढ़ाने की घोषणा की गई कि यह चुंगी टैक्स लगाया गया है। तात्विक दृष्टि से यह कहां तक सही है मैं इस समय सदन में उसके लिए निवेदन नहीं करना चाहूंगा, किन्तु इतना तो जरूर कहूंगा कि इतनी जल्दबाजी में यह चुंगी लगायी गई है; इस सिलसिले में टेक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट भी नहीं पढ़ी है। पेज ४०६ वोल्यूम ३ पैराग्राफ ११ में साफ साफ लिखा है कि "Octroi should ordinarily be levied on the basis of weight and not ad valorem since the latter adds to delay and harassment." लेकिन अभी जो घोषणा

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

की गई है वह चुंगी लगाने के बारे में है। इस कमीशन ने इस ऑक्ट्राय पर जो रिपोर्ट की है उसकी शुरूआत ही इस बात से की है कि यह ओब्नोक्षियस है। तो यह क्यों होता है? यह इसलिए होता है है कि साधनों के बारे में जो दृष्टिकोण है वह विपरीत है और इसीलिए योजना कमशीन ने इसको काटा है। योजना की दिशा ठीक है, आधार के विषय में सुझाव दिये वे पुराने हैं, साधनों का जहां तक प्रश्न है उसके लिए दूसरा दृष्टिकोण है। इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा यह होता है कि एक ओर तो हम चाहेंगे कि योजना को कार्यान्वित करने के लिए सहयोग मिलेगा लेकिन दूसरी ओर साधारण जनता, साधारण जनसंख्या की स्थिति यह है कि वह तात्कालिक फायदा उठाना चाहती है, हम कहेंगे इस योजना से जनसाधारण के जीवन स्तर की उन्नति होगी, जीवन स्तर ऊंचा उठेगा, लेकिन तात्कालिक नहीं। तो वह उसको उससे फायदा तात्कालिक नहीं होने वाला है, इसलिए सहयोग नहीं देगा और आप उसको ऐसा करने से रोकेंगे, उसको छेड़ेंगे और कहेंगे कि इसके द्वारा मिठाई तैयार हो रही है, तुम्हारे लिए मिठाई है, आगे से सहयोग करो। तो वह आगे की मिठाई के बारे में उनके सोचने की स्थिति नहीं है। मैं यह साफ कह दूं कि स्वभावत: योजना के बारे में कोई दृष्टिकोण है, जो उसके उन्नतिशील अंग हैं, राजस्थान की तरक्की करने वाले अंग हैं, कोई आदमी ऐसा नहीं होगा कि जो सहयोग नहीं करेगा, सरकार से कई माने में मौलिक मतभेद हो सकते हैं; मैं और मेरे साथी निश्चित रूप से सहयोग करेंगे लेकिन जो साधनों के प्रति दृष्टिकोण है वहां विरोध जरूर है। इस योजना के अमली तौर पर पूरा होने में विरोध है अगर आवश्यकता पड़ेगी तो उसका विरोध किया जायगा और विरोध ही नहीं किया जायगा वह विरोध योजना को कामयाब बनाने में मददगार होगा। इसलिए मैंने यह चीजें रखी हैं और मैं आशा करता हूं कि उनके बारे में गंभीरता-पूर्वक सोचा जायगा कि वह कैसे अमल में लाया जाय। अन्त में मैं आपसे तीन मुख्य बातों को फिर दोहरा कर आपसे इजाजत चाहूंगा।

पहली बात जो है वह है एक्सेस डिमान्ड। १२१ करोड़ रुपयों की धन राशि है उसको बढ़ाया जाय, इसको बढ़ाया जाय खास करके उद्योगों के लिए, पब्लिक सेक्टर में बढ़ाया जाय, रेलों में, स्टेट्स ट्रेडिंग कोर्पोरेशन में बढ़ाया जाय। ये तीन मुख्य मैं मानता हूं और उनमें बढ़ाया जाय।

दूसरा मेरा कहना यह है कि साधनों के बारे में जो दृष्टिकोण है उसको बदला जाय और जब इसको बढ़ाया जायगा तो आम लोगों की जेब में हाथ डालने की आवश्यकता नहीं होगी।

तीसरा है कि इस पर अमल कराने के लिये जनसंपर्क बढ़ाया जाय। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का निर्माण करने वाले प्रो० भार्गव ने तीन महीने पहले कलकत्ते में भाषण दिया था और उन्होंने कहा था कि जो योजना बनाई है और जिससे मेरे जी जान का सम्बन्ध है उस योजना बारे में मैं कम से कम ऐसा निश्चित तौर पर नहीं कह सकता कि उसको अमली जामा पहनाने में कामयाब हुए।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

"I cannot predict its success if it is executed in a bureaucratic manner."

तो यह बहुत बड़ा अंग है और मै इतना ही कहना चाहूंगा कि राजस्थान में तो न सिर्फ नौकरशाही तरीकों को खत्म करने की आवश्यकता है, सभापति महोदय, मुझे क्षमा कर दिया जाय मैं यह कहूं कि इसमें जो सेक्रेटेरियट है उसको खत्म करने की आवश्यकता है। इधर बैठने वाले माननीय सदस्य हों या उधर बैठने वाले माननीय सदस्य हों, मैं कह रहा हूं कि योजना के प्रति कार्यान्वित करने वाले लोगों का यह दृष्टिकोण होगा कि हमें इसको कार्यान्वित करना है; चाहे जैसे हो इसको कार्यान्वित करना है और अगर हम नहीं कर पाये तो जनता खुश नहीं होगी, तो यह गलत होगा। हमें कार्यान्वित करना है इसलिए हमारी और सब की उन्नति का यह आधार हो और वह जब ही होगी जब कि सारी ओर से सहयोग लेने के लिए एक नहीं बीसियों बार आप सहयोग का हाथ बढ़ावेंगे। इसलिए योजना के बारे में प्लनिंग कमीशन को रिपोर्ट पेश करने के पहले यदि उस पर बहस नहीं हो सकी है तो मैं उसको केवल टेक्निकल गलती नहीं हीं मानता बल्कि मैं तो यह मानता हूं कि यह दृष्टिकोण की गलती है। हम सुझाव देते, वे ज्यादा ठीक हो सकते थे या राज्य सरकार के अनुभवी लोगों ने बैठ कर जो तय कर दिये वे ज्यादा उपयुक्त हैं। अब इस बारे में मैं ज्यादा विवेचन में नहीं जाना चाहता। लेकिन सारे राजस्थान को संतोष होगा इस योजना के बनने से, कुछ ऊंची से ऊंची बातों के विषय में खिलाफत है। भाखरा के लिए सूचना मिली, सूचना आती है कि कोपरमाइन्स का जिक्र नहीं है। इस योजना के बारे में लोगों को पूरी कोई जानकारी नहीं, इतनी बड़ी योजना बनी और उसकी जनता की जानकारी नहीं, इसके बारे में पूरी पूरी लगातार जानकारी देने की आवश्यकता थी न कि केवल एक सर्कलर के जरिये लेकिन आम लोगों के कार्यकर्ताओं के साथ जनसम्पर्क कायम किया जाना चाहिए था। अच्छी योजना होने के बावजूद भी कामयाबी का बहुत बड़ा अंश पूरा न हो पाया। इसलिए सभापति महोदय मैं, अर्ज करूंगा कि जो भी सुझाव रखे जावेंगे उन पर पूरी तरह से गम्भीरतापूर्वक विचार किया जायगा। मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूं कि चाहे राजनैतिक प्रश्नों पर, तात्विक प्रश्नों पर इधर बैठने वाले और उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों, और हमारे बीच कठोर मतभेद क्यों न हो लेकिन इस योजना पर, ऐसी आशा है जिसका मैंने उल्लेख किया था कि जो राजस्थान की उन्नति की कदम बढ़ाने वाली है, पूरे २ सहयोग का जिम्मा हमारे ऊपर होगा ; यह निश्चित है।

मेरी इसके साथ साथ यह भी दरख्वास्त है इन बातों पर जिनका कि मैंने अपने भाषण में उल्लेख किया है उसको प्रेक्टिकल रूप में देखें और जो योजना की कामयाबी के लिये साधन उपलब्ध हैं उनका प्रयोग करें। और साथ साथ मेरा यह भी मानना है कि सरकार इसकी कामयाबी के लिये अपने दृष्टिकोण में भी परिवर्तन करे और सारे सदन का सहयोग प्राप्त करे। जब तक वे हर व्यक्ति का हर सदस्य का, सहयोग नहीं लेंगे तो उनको आखिर तक कठिनाई होगी, विरोध होगा; और विरोध करना भी पड़ेगा। मैं इन शब्दों के साथ अपने भाषण को समाप्त करता हूँ।

श्री किशनलाल शाह—माननीय सभापति महोदय, सदन के सामने दो दिनों से प्रस्तुत द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर बहस हो रही है। किसी भी कार्य को, किसी भी कर्म को, किसी भी योजना को या उसके औचित्य को, अनौचित्य को, समानता को, असमानता को, पवित्रता या अपवित्रता को देखकर तय करना ही सच्ची कसोटी होती है, यही सही माप दंड है, हमारे सामने प्रस्तुत द्वितीय पंचवर्षीय योजना को मापने का। इसी मापदंड से मापने पर इसके सही या बुरे परिणाम सदन के सामने आ सकते है।

सदन में प्रस्तुत द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये यह कहा जा सकता है कि राजनैतिक षडयंत्रकारियों का बनाया हुआ विवरण है जिसे सदन के सामने एक अच्छा रूप बनाकर रखा गया है। जब हम इस दृष्टिकोण से और ऊपर बताये हुए मापदंड से इस योजना को देखते हैं तो मैं समझता हूँ राजनैतिक अर्थ में इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमने क्या पाया है? यह एक अर्थ में राजनैतिक षडयंत्रकारियों का और सत्ताधारियों का सम्मिलित रूप से अभियान है कुछ लोगों को नीचे दिखाने का। अभी मैं ज्यादा दूर न जाकर सदन में विरोधी दल के माननीय नेता ने जो बातें कहीं उन्हीं के बारे में अर्ज करना चाहूंगा। उन्होने कहा कि नागौर जिले को बहुत धन राशि दी गई और बेशक नावां की तहसील भी नागौर जिले का हिस्सा है और उस नावाँ की नागौर जिले में क्या स्थिति है यह देखने की बात है। माननीय सभापति महोदय, मेरी आत्मा यह अभिव्यक्ति करने को बाध्य करती है। आज जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना हमारे सामने है वह न तो केवल हमारे समाजवाद की या समाजवाद के ढांचे के लक्ष्य की पूर्ति का परिणाम स्वरूप है बल्कि वह एक भ्रष्ट साधनों द्वारा भ्रष्ट आचरण से हथियायी हुई सत्ता को कायम रखने का एक राजनैतिक षडयंत्र मात्र है। इस बात को मैं आपके समक्ष साबित करूंगा। इसमें मैं दूसरों के उदाहरण नहीं दूंगा बल्कि मेरे व्यक्तिगत जीवन में जिसका संबंध रहा है वही उदाहरण आपके समक्ष पेश करूंगा। जब कि सदन के भूतपूर्व नेता के समय जब कि वर्तमान नेता का चुनाव नहीं हुआ था उससे पहले माननीय अध्यक्ष के विरुद्ध एक अविश्वास के प्रस्ताव.......

श्री सभापति—ऐसे उदाहरण आप न रखें।

श्री किशनलाल शाह—(अपना भाषण जारी रखते हुए) माननीय सभापतिजी, मैं यह साबित करना चाहता हूँ कि यहां क्षेत्रीय भावना कितनी कूट कूट कर भरी हुई है। मैं अपने व्यक्तिगत भाव आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ, उस भावना को प्रमाणित करने के लिये मुझे कुछ उदाहरण देना आवश्यक है। उस समय चन्द साथियों ने, अविश्वास के प्रस्ताव को तैयार करके, उस पर हस्ताक्षर कराने की कार्यवाही चलाई थी....

श्री सभापति—मैं फिर आपको सूचित करना चाहता हूं कि आप कभी ऐसी बातों का जिक्र न करें।

श्री किशनलाल शाह—It is necessary to prove the mentality, what has happened and the feeling about this Five Year Plan.

श्री सभापति—यह तो आपने कहा ठीक है।

श्री किशनलाल शाह—अच्छी बात है, उसके बाद में जब इसके बारे में मुझसे पूछा गया आप क्या चाहते हैं; यह सिद्धान्तों का प्रश्न था, मैंने उसे आवश्यक नहीं समझा और उसके बाद मेरे साथ यह बर्ताव किया गया कि मेरे उस इन्कारी से उन लोगों ने मेरे साथ में यह व्यवहार किया और मेरे क्षेत्र की तरफ उदासीनता बरती जाने लगी।

श्री सभापति—फिर से मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि आप अपनी पर्सनल बातें यहां न कहें और अगर आप इन्सिस्ट करेंगे तो मैं बोलने से आपको रोकूंगा।

श्री किशनलाल शाह—(जारी) मैं नहीं समझ पाया माननीय सभापतिजी, जब कि पंचवर्षीय योजना का संबन्ध हर क्षेत्र से है तो हर क्षेत्र के प्रतिनिधि का कर्तव्य है कि वह अपने अपने क्षेत्र की बातें रखे ताकि; जिस प्रकार प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रति उदासीनता बरती गई उसी प्रकार इस योजना में भी न बरती जाय। मैं समझ नहीं पाता जब कि मैं फेक्टस आपके सामने रख रहा हूं और आप मुझे उनको रखने से मना कर रहे हैं, यह मेरे साथ एक प्रकार से अन्याय है ऐसा मैं मानता हूं। सभापति महोदय, मैंने जो बातें रखी उस पर आप विचार करें व अपनी राय दें।

श्री टीकाराम पालीवाल—सभापति महोदय, मेरा ख्याल है कि सदन के माननीय सदस्य जो कहना चाहते हैं वे यह कहना चाहते हैं कि उनके क्षेत्र के प्रति क्या रूख अपनाया गया। उसको कहते हुए वे कारणों पर कहने लग गये। माननीय सदस्य जो कहना चाहते हैं कि क्या रूख अपनाया गया उनके क्षेत्र के प्रति, उनके क्षेत्र की क्यों अवहेलना की गई इस बारे में वे कह रहे हैं। उनके लिये ज्यादा उचित था कारणों पर पहले प्रकाश न डालकर यह कहते कि रुख क्या अपनाया गया, क्या अवहेलना हुई; तो इस तरह से कहते हुए जो चीज सदन के सामने आती उसको सदन सुनने के लिये तैयार रहता।

श्री सभापति—मैंने स्पष्ट कर दिया कि उनको क्या बोलना चाहिये, बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं।

श्री किशनलाल शाह—(जारी रखते हुए) सामुदायिक योजना राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड जो आये दिन खुलते रहते हैं उनके संबन्ध में जो प्रतिदिन प्रश्नोत्तर सदन में होते हैं उनसे स्पष्ट हो जाता है कि यह किन क्षेत्रों में खोले गये और किन क्षेत्रोंमें नहीं उनके न खोले जाने के क्या कारण हैं? मैं नहीं समझता कि उपेक्षा किन किन क्षेत्रों की की गई। क्या कारण है कि उन क्षेत्रों की उपेक्षा की गई जब कि मैं उन कारणों को बता रहा हूं तो मेरी समझ में नहीं आता माननीय सभापति, मुझे क्यों मना कर रहे हैं। यह किस प्रकार संगत नहीं?

श्री टीकाराम पालीवाल—कारणों में गये बिना भी यह बता सकते हैं कि आपके क्षेत्र की उपेक्षा क्यों की गई ? सदन में आप बिना कारण बताये भी बता सकते हैं।

(श्री किशनलाल शाह के पुनः खड़े होने पर)

श्री सभापति—Order pleese ! यहां पर हम राजस्थान की द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर विचार कर रहे हैं; एक संकुचित क्षेत्र की बाबत विचार नहीं कर रहे हैं। इसलिये विशाल दृष्टिकोण से अगर हम इस पर विचार करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। आपको क्यों सहायता नहीं मिल पाई, आप क्यों सहायता प्राप्त करने में सफल नहीं हुए, यहां उनका उल्लेख करना ठीक नहीं। आप अपने विचारों को फाइव इयर प्लान तक ही सीमित रखेंगे। आपको सहायता क्यों नहीं मिली, उनके कारणों मे यहां इस समय जाने की जरूरत नहीं।

श्री किशनलाल शाह—अध्यक्ष महोदय, फिर मेरा एक एतराज है। अभी एक माननीय वक्ता ने कहा कि इसमें क्षेत्र की बात उपस्थित की गई, इसमें स्पष्टतः क्षेत्रीय भाव का जिक्र किया है। मैं उदाहरण दूंगा कि उनको अध्यक्ष महोदय ने बोलने की इजाजत दी है तो मुझे क्यों नहीं देते ?

श्री सभापति(श्री हिम्मतसिंह)—मैं उचित नहीं समझता इसलिये नहीं देता।

श्री किशनलाल शाह—आपके इस निर्णय और एतराज के प्रोटेस्ट में मैं भी मेरा वक्तव्य बन्द करता हूं।

श्री कंवरलाल जेलिया—माननीय चेयरमेन, दूसरी पंचवर्षीय योजना के संबंध में अपने अपने दृष्टिकोण से विचार व्यक्त किये जा रहे हैं। मैं भी इस पंचवर्षीय योजना पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य—आवाज नहीं आ रही है

श्री कंवरलाल जेलिया—अध्यक्ष महोदय, दूसरी पंचवर्षीय योजना पर विचार करने के साथ साथ हमें पहली पंच वर्षीय योजना के पहलुओं पर देखना होगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना को हम राजस्थान की परिस्थिति के आधार पर देखते हैं तो हमें स्पष्ट मालूम हो जाता है कि राजस्थान की परिस्थिति को देखते हुए पहली पंचवर्षीय योजना में सरकार ने कृषि की उन्नति की ओर अधिक ध्यान दिया, सिंचाई के साधनों पर ध्यान दिया गया और यातायात के साधनों पर ध्यान दिया गया। अब हमारे सामने यह प्रश्न पैदा होता है कि राजस्थान की जनता को राहत पहुंचाने के लिये राजस्थान में पंचवर्षीय योजना का निर्माण करने के लिये निर्माण कर्त्ताओं ने हमारे सामने जो उद्देश्य रखे हैं उनमें यह बताया है कि किन पहलुओं पर जोर दिया

[श्री कंवरलाल जेलिया]

जायगा । वास्तव में इन पहलुओं पर इस योजना में ध्यान दिया गया है या नहीं, इस दृष्टिकोण से देखना जरूरी है ।

पहली पंच वर्षीय योजना के सिंचाई और खेती के साधनों को बढ़ाने की ओर मैं आवश्यक समझता हूं, उस पर ध्यान दिया गया । दूसरी योजना को यदि सबसे बड़ी खूबी मानता हूं और उस पर हम को संतोष करना चाहिये, वह है भाखरा और चंबल की नदी घाटी योजना को पूरा करना और उसके द्वारा सिंचाई और विद्युत की कमी को पूरा करना । राजस्थान में विद्युत की बड़ी भारी आवश्यकता है, उद्योग धंधों को पनपाने और इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिये सस्ती बिजली हमको मिलनी चाहिये और वह हमें मिल जायगी भाखरा बांध से । इसके साथ ही गांधी सागर और राणा प्रतापसागर बांध का काम भी शुरू किया जायगा और साथ ही चंबल से सिंचाई योजना का काम भी पूरा होता है तो हमें इससे काफी लाभ होता है । मैं आंकड़ों से बताऊंगा कि चंबल भाखरा की स्कीम में करीब ८ करोड़ रुपये चंबल में हमारे खर्च होंगे और राणा प्रतापसागर बांध पर करीब ४ करोड रुपये खर्च होंगे, इसी तरह भाखरा पर जो खर्चा होगा उसका १४ प्रतिशत अपने आंकड़ों के अनुसार अपना हिस्सा आता है ।

मुझसे पूर्व वक्ता ने आलोचना करते हुए बताया कि राजस्थान के योजना निर्माताओं ने योजना में मूल भूत कमियें रख दी हैं । हो सकता है अपने दृष्टिकोण से उन्होंने विचार किया हो, लेकिन उनके विचार से मैं सहमत नहीं हूं । मैं राजस्थान की परिस्थिति को देखते हुए मानूंगा कि हमारे राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र बहुत हैं और ग्रामीण जनता के लिये प्रोविजन करना आवश्यक है । मैं यह मानता हूं कि राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय विस्तार खंड को एक चौथाई भाग से और अधिक बढ़ाने के सिद्धान्त को स्वीकार किया है । इसमें संदेह नहीं कि राष्ट्रीय विस्तार योजना को बढ़ाने से कुछ ग्रामीण क्षेत्रों को सहायता मिलेगी लेकिन जहां तक घरेलू उद्योगों का सवाल आता है वहां तक इन उद्योगों को सरकार की ओर से कितनी मदद मिलेगी, इसको इस वक्त इस नजर से देखने की आवश्यकता हो जाती है । मैं इन आंकड़ों की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा । उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये घरेलू इंडस्ट्री को जो धन राशि दी गई है वह ८ करोड़ से ऊपर है और ५.१८. प्रतिशत रखा है । एक तरफ भारत सरकार के प्लानिंग विभाग की ओर से इस दूसरे पंच वर्षीय योजना के लिये कहा गया है कि हमारा मूल आधार माना जायगा घरेलू उद्योग और इंडस्ट्रीज को पनपाना । एक तरह से देखा जाय तो हमारे यहां खनिज पदार्थ काफी पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं और इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिये बिजली की योजना भी साथ ही साथ ली जा रही है लेकिन इसके लिये पर्याप्त अनुसंधान और सर्वे की आवश्यकता है । इसके लिये पहली योजना में सरकार ने कतई ध्यान नहीं दिया था । अब दूसरी योजना में ध्यान देने की आवश्यकता महसूस की जा रही है । मैं खास तौर से घरेलू उद्योग-धंधों की ओर जोर दूंगा । इस योजना में घरेलू उद्योग धंधों की बात कही गई है लेकिन इसके लिये जो धन-राशि रखी गई है वह कम है । राजस्थान की परिस्थित, यहां

[श्री कंवरलाल जेलिया]

की आवश्यकता, यहां के उत्पति के साधन आदि को देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि जो धन-राशि इसके लिये रखी गई है वह कम है।

जिन चीजों को प्रोत्साहन देना आवश्यक है उनमें जो कमी मानता हूं उनमें है ऊन का धंधा, दूसरे धंधों के लिये सरकार ने कुछ ट्रेनिंग सेन्टर्स रखे हैं लेकिन मैं आप का ध्यान दिलाऊंगा कि सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि सरकार की ओर से ट्रेनिंग दी जानी चाहिये। इसके लिये एक या दो सेन्टर खोले हैं, उनसे काम चलने वाला नहीं है। हमें इन की संख्या अधिक बढ़ानी होगी। अब तक उद्योग-धंधों पर कोई खास ध्यान नहीं दिया गया है।

आज की स्थिति में लोगों को राज्य सरकार से क्या चाहिये, इस बारे में मैं बताऊंगा कि शिक्षा चाहिये, धंधा चाहिये, कपड़ा चाहिये। जहां तक पेट का सवाल आता है नागरिक हमसे पूछ सकते हैं कि आपने हमारे लिये क्या किया? योजना में यहां तक देखा जाता है कि दूसरी बड़ी इंडस्ट्रीज के लिये करोड़ों रुपयों की राशि रखी जाती है लेकिन छोटे छोटे उद्योगों को कर्जा देने के लिये राजस्थान सरकार ने क्या प्रोविजन रखा है? यदि राजस्थान इंडस्ट्रियल फाइनेन्स कोरपोरेशन को करोड़ों रुपये दिये जाते है तो छोटे उद्योगों के लिये भी तो कुछ होना चाहिये। अब तक जो जो सवाल पूछे गए कि कितनी धन राशि किन-किन उद्योगों के लिए दी गई उनके उत्तर में जो आंकड़े बताये गए उनको देखते हुए मैं मानता हूं कि छोटे उद्योगों को अधिक धन-राशि नहीं दी गई। मैं चाहता हूं कि माननीय उद्योग मन्त्री हमें विश्वास दिलावें कि इन्डस्ट्रियल फाइनेन्स कॉरपोरेशन को कर्जा देता है वह छोटे घरेलू धंधेवालों का भी ध्यान रखेगा। रिज़र्व बैंक के द्वारा सहकारी समितियों की मार्फत कर्जा मिलने वाला है, वह कर्जा भी छोटे धंधेवालों को मिलना चाहिए। जिस तरह कृषि के लिए प्रोत्साहन देने के लिए सहकारी कृषि समितियों की मार्फत कर्जा मिलता है, उसके अलावा बैलों के लिए, कुओं की खुदाई के लिए, सिंचाई के साधनों के लिए, तकावी कर्जा दिया जाता है। उसी तरह से घरेलू उद्योगों के लिए ऐसी ही सुविधा लोगों को देनी चाहिये ताकि वे कर्जा लेकर कुछ आवश्यक सुधार कर सकें। जब हम देखते हैं कि भारत सरकार टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए अपने लोगों को जापान भेजती है और वहां उनकी ट्रेनिंग के साधन उपलब्ध करती है तो राजस्थान सरकार क्यों नहीं यहां के लोगों को टेक्निकल शिक्षा दिलाने और घरेलू धंधों को अच्छी तरह से चलाने के लिए बाहर भेजती है? जैसा जापान में घरेलू उद्योग हैं उसी तरह के उद्योग राजस्थान में पनपाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। जहां तक लोगों को बाहर भेजकर टेक्निकल ट्रेनिंग दिलाने का सवाल है मैं उसमें कमी पाता हूं। राजस्थान में बड़ी बड़ी फेक्टरीज़ चलाने के साधन मौजूद है लेकिन उनको चलाने के लिए प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है।

इसके साथ ही साथ मैं यह अर्ज करूंगा कि चमड़ा हमारे यहां काफी अधिक मात्रा में मौजूद है। (हियर-हियर) माननीय सदस्यों को इससे आश्चर्य होगा, लेकिन जिस वर्ग से मैं आया हूं

[श्री कंवरलाल जेलिया]

उसका यह धन्धा है। उसकी उन्नति करना मैं आवश्यक समझता हूं। मैं यह मानता हूं कि राजस्थान में चमड़े के उद्योग की उन्नति करने की काफी गुंजायश है। यहां से बम्बई, मद्रास, कानपुर आदि स्थानों को कच्चा चमड़ा भेजा जाता है, इसके लिए भी यहां पर बड़ी इन्डस्ट्री संचालित करने की योजना होनी चाहिए। एक बात मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि आज की परिस्थिति को देखते हुए राजस्थान की परिस्थिति को देखते हुए हमारा उद्देश्य यह होना चाहिये कि इतने बड़े उद्योग धंधों को एक या दो करोड़ पतियों या लखपतियों के हाथ में सौंपने की आवश्यकता नहीं है। सरकार को ही अपनी ओर से इनके कार्य का संचालन करना चाहिए, ऐसा इन्तजाम करना चाहिए जिससे कच्चा माल बाहर न जावे और यहीं पर उसकी खपत हो जावे और यहां के लोगों को रोजी मिल सके। राजस्थान सरकार ने कल कहा था कि टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए कुछ सेन्टर्स यहां खोले गये हैं। मैं मन्त्री महोदय से जानकारी चाहूंगा कि वे कहां खोले गये है ?

श्री भोगीलाल पंड्या---धौलपुर में।

श्री कंवरलाल जेलिया---इसके साथ ही राष्ट्रीय विस्तार योजना क्षेत्र खोलने के लिये बताया है कि सारे राजस्थान में राष्ट्रीय विस्तार योजना क्षेत्र खोलने की बात आती है। राष्ट्रीय विस्तार योजना क्षेत्र से मैं मानता हूं कि काश्तकारों को और दूसरे लोगों को कुछ सहायता मिल सकती है लेकिन जहां तक कम्युनिटी प्रोजेक्ट ब्लोक्स को जितनी गुंजायश है जितने पर्याप्त साधनों की कम्युनिटि क्षेत्र में गुंजायश है वह राष्ट्रीय विस्तार योजना क्षेत्र में नहीं मिलती है इसलिये राष्ट्रीय विस्तार योजना के साथ कम्युनिटि विस्तार खंड और दिये जांय।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय सभापति,.........

श्री सभापति—इन्होंने अभी अपना भाषण समाप्त नहीं किया है।

श्री कंवरलाल जेलिया—(जारी) इसके साथ ही मैं यह बताऊंगा कि जो भूमि सुधार का सुझाव दिया गया है उस बारे में राजस्थान सरकार का ध्यान दिलाऊंगा कि भूमि सुधार के लिये खास तौर से नदियों की वजह से भूमि में कटाव आता है, उसको और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। सरकार की ओर से इसके लिये जितनी धन-राशि रखी गई है वह पर्याप्त मात्रा में नजर नहीं आती। हो सकता है कि मैं देख नहीं पाया होऊं, लेकिन भूमि सुधार की आवश्यकता को महसूस करना चाहिये। सिंचाई के साधनों को बढ़ाने के लिए भाखरा और चम्बल की जो योजना कार्यान्वित करने जा रहे हैं उसके कारण यहां पर खाद की बड़ी आवश्यकता पड़ेगी। राजस्थान सरकार ने खाद के कारखाने के लिये जोर दिया है, उसमें संतोष करना चाहिये। हम भारत सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि खाद का कारखाना राजस्थान में संचालित किया जाय।

[श्री कंवरलाल जेलिया]

मैं इसके साथ पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिये सरकार ने कितनी धन राशि रखी है उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। (करतल ध्वनि) पहली पंचवर्षीय योजना में जो धन राशि रखी थी उस आंकड़े को देखा जाय तो शिड्यूल ट्राइब्स को देखते हुए कुछ परसेन्टेज आ जाता है, लेकिन आप देखेंगे तो पता चलेगा कि शिड्यूल ट्राइब्स के लिए निश्चित एक डूंगापुर जिले में कुछ सहायता पहुंची है। राजस्थान सरकार रियासत के दूसरे जिलों में रहने वालों का भी भला चाहती है। दूसरे क्षेत्रों को भी सुविधा देनी चाहिये, शिड्यूल ट्राइब्स के एरिया में आने पर उन लोगों को भी सुविधा मिलनी चाहिये। राजस्थान में दूसरी शिड्यूल कास्ट्स या अनुसूचित जातियों के लोग हैं जिनकी संख्या को देखते हुए धन राशि जो रखी गई है वह कम पड़ती है। दूसरे माने में जो सुविधा दी गई है उसको मैं कुछ कम मानता हूं और जो खर्चा होना चाहिये पर्याप्त रूप से खर्च होने की आवश्यकता मानता हूं।

हमारे मुख्य मन्त्रीजी ने शिक्षा की ओर ध्यान दिलाते हुए बतलाया था कि यहां पर ६ साल से लेकर ११ साल की आयु के बच्चों में से ४५ प्रतिशत बच्चों को शिक्षा दी जा सकेगी। शिक्षा के लिए जो कुछ रखा गया है उसे मैं काफी सुधार समझता हूं। कुल मिलाकर सारी बातों की ओर देखें तो सरकार को धन्यवाद देना चाहिये। सिंचाई के लिए भाखरा चंबल की योजना को कार्यान्वित किया जाना और अन्य नदी घाटी योजनाओं को कार्यान्वित किया जाना बहुत बड़ा काम है। हमारे राजस्थान की आज की स्थिति को देखते हुए हमें संतोष प्रकट करना चाहिये। उद्योग धंधों के लिए जो कुछ रखा गया है उसे मैं कम मानता हूं लेकिन जो क्रियात्मक सुझाव सदन के सामने रखा है उस पर ध्यान देना आवश्यक है। जो योजना भारत सरकार के योजना कमीशन द्वारा मंजूर हुई है वह हो चुकी है, उसको कार्यरूप में परिणत करने में हमको लग जाना चाहिये।

(श्री मुक्तिलाल मोदी और श्री खेतसिंह दोनों ही के बोलने के लिए एक साथ खड़े होने पर)

श्री सभापति—श्री मुक्तिलाल मोदी।

श्री खेतसिंह—मैं पहले भी खड़ा हुआ था।

श्री सभापति—इनको बोलने के लिए मैंने कह दिया है, आपको भी मौका मिलेगा।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय चेयरमेन, यह जो दूसरी पंचवर्षीय योजना का विषय चल रहा है उस योजना के लिए जितने रुपये भारत सरकार ने मंजूर किये हैं, करीब १२० करोड़ रुपये जो भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को देने की स्वीकृति दी है वह बहुत ही कम दिखाई देती है जबकि दूसरे प्रान्तों को इससे भी ज्यादा रुपये भारत सरकार ने दिये हैं। राजस्थान एक गरीब प्रान्त है। राजस्थान में जितनी असुविधायें हैं उतनी बहुत कम जगह है, जितनी यहां पर कमी है

Page No.46

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

उसके बावजूद भी हमको बहुत कम रुपये दिये गये हैं। राजस्थान ने शिड्यूल्ड कास्ट को लिया जाय तो उसकी आबादी काफी है और उसके लिए भारत सरकार ने पहली योजना में भी काफी कम रुपये दिये थे उससे भी अब कम दिये गये हैं।

दूसरी बात यह है कि राजस्थान में पानी बहुत कम है। उस कमी के कारण भी भारत सरकार ने बहुत कम रुपये दिये हैं। पहली पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें जो काम हुए वे जिस तरह से होने चाहिये थे उस तरह से नहीं हुए और मैं माननीय मंत्रीजी को बताऊंगा कि जिस तरह से इस पंचवर्षीय योजना में रुपये मिले हैं आज बजट में वही रुपये आते हैं। आज स्कीम बनती है लेकिन जब साल खत्म होता है उससे २ महीने पहले या १ महीना पहले नीचे के डिपार्टमेंट के पास वह पहुँचती है और वह रुपये इस तरह से खर्च किये जाते हैं कि जिस तरह से नहीं होने चाहिये। उन रुपयों का बहुत बुरी तरह से दुरुपयोग होता है। एक पैसे की जगह दो पैसे खर्च किये......

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष पदासीन)

जाते हैं न कि आधा या पूर्ण पैसा खर्च हो। जिस तरह से रुपये खर्च किये जाने चाहिये उस तरह से खर्च नहीं किये जाते हैं। माननीय उपाध्याय, मैं बताना चाहता हूँ कि दूसरे देशों में जब पंचवर्षीय योजनायें बनती हैं तो पंचायतों के द्वारा सारा एस्टीमेट बनाकर आगे की योजना के आधार पर खर्च किया जाता है। वे रुपये तब दिये जाते हैं जब बजट अधिवेशन आता है; उस वक्त वे रुपये मंजूर करके एक या डेढ़ माह में सारे डिपार्टमेंट्स के पास स्वीकृति पहुँच जाती है और सारे डिपार्टमेंट्स द्वारा योजना लागू हो जाती है।

श्री मोतीलाल—कौन से देश की बात कर रहे हैं आप ?

श्री मुक्तिलाल मोदी—कौनसा देश बताऊं आपको ; चाहे आप रूस ले लीजिये, फिनलेन्ड ले लीजिये, जेकोस्लेवाकिया ले लीजिये। माननीय चेयरमेन, नहीं माननीय उपाध्यक्ष, और मैंने खुद ने देखा है, मैंने खुद ने प्रयत्न किया है; फिर भी राजस्थान सेक्रेटेरियेट से, योजना के अन्दर, या किसी राहत के काम के अन्दर, या बजट के अन्दर या बिजली पानी आदि के लिये जो रुपया दिया जाता है, सरकार की तरफ से और उनका काम आज शुरू होना चाहिए पर छः-छः महीने, सात-सात महीने और आठ-आठ महीने तक वे कागज सेक्रेटेरियेट से अफसरों तक नहीं पहुँचते हैं। मुख्य मन्त्रीजी भी इसको देख सकते हैं, जो मैंने कहा है कि जितनी सड़कें, बांध और दूसरी योजनायें हैं उनके कागज डिपार्टमेंट तक नहीं पहुँचते हैं, और बाद में धीरे-धीरे पहुँचता भी है तो जो रुपया आज खर्च होना चाहिए वह दो महीनों में खर्च होता है जिससे जैसा काम होना चाहिए वैसा नहीं होता है। इसलिए डिपार्टमेंट का तरीका बदल देना चाहिए, डिपार्टमेंट के

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

सेक्रेटरी हैं, डिप्टी सेक्रेटरी हैं, एसिस्टेन्ट सेक्रेटरी हैं वे डिपार्टमेंट का तरीका नहीं जानते हैं। मेडिकल के जो सेक्रटरी हैं वे मेडिकल का काम जानने वाले होवे, जैसा कि बंगाल में मैंने देखा है, बम्बई में मैंने देखा है, और और जगहों में देखा है वे मेडिकल के जानकार होंगे; पर राजस्थान में ऐसा नहीं है। राजस्थान में भी ऐसा कर दिया जाय कि मेडिकल और डॉक्टरों के बारे में वह सेक्रेटरी जानते हों तो यह गलती नहीं हो सकती। पर यहां आइ. सी. एस. अफसरों को बैठा दिया जाता है, एक रुपए की जगह दो रुपया खर्च हो तो कोई बात नहीं। इन सेक्रेटरियों और मन्त्रियों से पूछा जाय कि घर में से दो रुपया खर्च हो तो कैसा दुःख होता है।

तो मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि पी. डब्लू. डी. का सेक्रेटरी हो तो वह इन्जीनियर होना चाहिये। ऐसा होने से वह उन कागजों को जल्दी निकालेंगे और जानकारी भी रखेंगे।

माइन्स को जो इसमें पैसा दिया गया है, उसके बारे में मैं अब कुछ निवेदन करना चाहूँगा। मैं श्री वाडिया से जो कि डाइरेक्टर जियोलोजिकल सर्वे, गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया हैं उनसे मिला और उनसे राजस्थान की माइन्स के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे यह बताया कि हिन्दुस्तान में राजस्थान का माइन्स के बारे में दूसरा नम्बर है। परन्तु आज यह बड़े दुःख की बात है कि न तो राजस्थान का फाइनेन्स विभाग, न उद्योग विभाग और न दूसरे विभाग या लोग यह सोच पाते हैं कि इस मामले में किस तरह जांच करके राजस्थान की उन्नति की जा सकती है। उनके ये वर्ड्स थे, जो मैंने राजस्थान के फाइनेन्स सेक्रेटरी और इन्डस्ट्री सेक्रेटरी को भी बताये कि राजस्थान की आज उद्योगों के बारे में कोई उन्नति नहीं हो रही है; तो ऐसी सूरत में जो इसके बारे में सरकार ने पैसा रखा है वह बहुत ही कम रखा है। अगर भारत सरकार राजस्थान के उद्योगों की तरक्की के बारे में नहीं सोचती है तो राजस्थान सरकार को चाहिये कि वह बाहर के देशों से, फोरिन कन्ट्रीज़ जो हैं, उनसे पत्र व्यवहार करके उनसे कोई इस प्रकार की एसोसियेशन बना कर, बाहर की फोरेन कन्ट्रीज़ हैं उनसे मदद लेकर अपने उद्योग धन्धों को बढ़ावें न कि सब कुछ भारत सरकार पर ही छोड़ दें।

कहना तो नहीं चाहिये था पर फिर भी मैं बता दूं, मैं रशिया के कोमर्शियल एडवाइज़र से मिला तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर हमसे कोई कन्ट्रेक्ट करना चाहे तो हम करने के लिये तैयार हैं, जिस चीज की हमें जरूरत है वह चीज हम लोग बाहर के देशों से मंगाने के लिये तैयार हैं। ब्रिटेन और अमेरिका खरीदते हैं उसी तरह रशिया भी राजस्थान सरकार से खरीदने के लिये तैयार हो सकता है। वह कहता है कि जो चीज हमारे यहां नहीं है वह हम अगर कोई रुपया चाहे तो रुपया देकर और अगर बदले में कोई दूसरा सामान, मशीनरी आदि लेना चाहे तो वह देने को तैयार हैं। राजस्थान सरकार यदि यह सोचे तो राजस्थान की काफी उन्नति हो सकती है और इसके अन्दर कई चीजें ऐसी हैं जो हिन्दुस्तान के दूसरे प्रान्तों में नहीं हैं। पर यहां

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

इस चीज पर ध्यान नहीं दिया जाता है और अगर दिया भी जाता है तो, जितना दिया जाता है वह बहुत कम है ।

दूसरी बात यह है कि राजस्थान में कभी राजस्थान सरकार ने यह नहीं सोचा कि राजस्थान में जितने सारे कस्बे हैं, गांव हैं उनकी फ्लड के मामले में सर्वे कराई जाय । जयपुर में फ्लड आया था पर यह नहीं सोच सके कि केनाल बनाई जाय, इस बार भी बहुत नुकसान हुआ, मिनिस्टरों से मिले, पर इसकी जिम्मेदारी लेने को राजस्थान सरकार तैयार नहीं । यह काम इरिगेशन का है, या पी० डब्लू० डी० का है, या म्युनिसिपेलिटी का है, पर कोई जिम्मेदारी लेने के लिये तैयार नहीं । केनाल टूट गई थी, घर बह गये थे, लोगों को बहुत नुकसान हुआ; पर आज तक इसकी जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है । इसलिये राजस्थान सरकार को चाहिये कि हर गांव, शहर और कस्बे की सर्वे होनी चाहिये । जब तक सर्वे नहीं करेंगे तब तक राजस्थान सरकार को और दूसरे अफसरों को जानकारी नहीं होगी कि यहां क्या खामियां हैं जिनकी वजह से फ्लड आते हैं और इन खामियों को दूर करना चाहिये ।

राजस्थान सरकार आज जो बड़े बड़े शहरों और कस्बों में तरह तरह की घातक बीमारियां फैलाने वाले आदमी हैं, जो चौराहों पर दूसरी जाहों पर बुरी हालत में अपनी बीमारियों का प्रदर्शन करते हैं और बीमारियां फैलाते हैं; पर इनके लिये राजस्थान सरकार कुछ भी नहीं कर रही है । मैं देख रहा हूँ कि भारत सरकार भी नहीं सोच पा रही है इन भिखमंगों के लिये जो कितने गंदे कपड़े रखते हैं, गंदी बीमारियों का प्रदर्शन करते हैं और गंदी बीमारियां फैलाते हैं । यदि कोई एक प्रान्त की सरकार कदम उठाये तो जनता का भी भला हो सकता है, और ये बीमारियां फैलने से रुक सकती हैं ।

पी० डब्लू० डी० और बिजलीघरों के बारे में जो रुपया रखा गया है वह ४४ करोड़ रुपया बिजली के लिये रखा है । पर इस ४४ करोड़ रुपये के लिये मेरा तो यह मान कर चलना है जैसा कि हम सोचते तो यह हैं कि इस ४४ करोड़ रुपये की बदौलत ५० करोड़ रुपयों का काम करके बतायें, पर ऐसा न होकर आज इससे उल्टा काम होगा, ४४ करोड रुपये में से केवल ३० करोड़ रुपये का ही काम होगा क्योंकि बात दरअसल यह है कि अगर हमारा पैसा सवाये पैसे में चलता है तो सरकार का पैसा केवल आधे पैसे में ही चलता है और जब तक यह चीज दूर नहीं होगी, जितने एम० एल० एज़० हैं उनके दिमाग में, जितने मिनिस्टर हैं, उनके दिमाग में, और जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनके दिमाग में यह बात पैदा नहीं होगी, जनता में जब तक सहानुभूति पैदा नहीं करेंगे, यह चीजें नहीं होंगी तब तक देश की उन्नति नहीं हो सकती ।

एक माननीय सदस्य की तरफ से यह कहा गया कि बड़े बड़े, ऊंची तनख्वाह पाने वाले इन्जीनियर हमारे राजस्थान में आ जायें और काम करें तो राजस्थान की उन्नति हो सकती है । नहीं,

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

इससे कुछ नहीं होगा, छोटे इन्जीनियरों को आज राजस्थान सरकार की ओर से पूरा प्रोत्साहन दिया जाय तो वे लोग राजस्थान की तरक्की कर सकते हैं·· (घंटी)

५ मिनिट और ।

श्री उपाध्यक्ष—जनरल भाषण नहीं होना चाहिये, जो खामी रह गई है वही बातें कहनी चाहिये ।

पंचायतों के बारे में १० लाख रुपया सरकार ने रखा है जो बहुत कम है क्योंकि पंचायतों को सरकार को ज्यादा रुपया देना चाहिये। छोटे छोटे गांवों में पंचायतों को रुपया नहीं दिया जावेगा तो उनके लिये काम चलाना बहुत मुश्किल होगा। बड़े बड़े गांवों में तो बिजली और पानी की व्यवस्था है, मगर छोटे गांवों में बिजली और पानी की व्यवस्था नहीं है; वहां बिजली नहीं जावेगी, न पानी के नल जावेंगे। वहां तो कूए होंगे, उन्हीं से काम लिया जावेगा, वहां पर न सड़के होंगी। तो सरकार को यह चाहिये कि कम से कम जहां पंचायतें हैं, म्युनिसिपेल्टीज़ का जिक्र तो मैंने यहां कहीं देखा नहीं, कहीं होगा तो होगा ; वहां पर रकम ज्यादा सरकार की तरफ से रखी जानी जाहिये क्योंकि अब सरकार उनको अधिकार दे रही है। जब उनको अधिकार दे रही है तो उनके ज्यादा अधिकारों के साथ साथ उनके लिये ज्यादा रुपया रखना ज्यादा अच्छा होगा।

दूसरी बात यह है कि सरकार से जो बात हमें बार बार कहनी है कि हम लोग विरोधी दल के सदस्य हैं, क्या उधर के और क्या इधर के दोनों ही ट्रेज़री बेंच की बुराई करते हैं, इसलिये सबसे ज्यादा अच्छा तो यह होगा कि उन सबको राय में सम्मलित किया जावे, नहीं तो बुराई करते रहते हैं। जब दोनों पार्टी के लोग मिल कर कोई चीज करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा और सरकार की पंचवर्षीय योजना है वह ज्यादा सफल होगी। आप सब सरकार की बुराई करते हैं। आप सब स्वार्थी लोग हैं, यह इमानदारी की बात है। सब लोगों को सरकार को सहयोग देना चाहिये। सब ऊंचे बन कर पब्लिक को नीचे देखते हैं और इसलिये सब चलते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिये। यदि आप इस बात को मान कर चलेंगे कि इधर और उधर के बैठने वाले यदि इस तरह का वातावरण हो तो उन्हें उसे दूर करना चाहिये और अगर इसको दूर करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा और वह रुपया पब्लिक के काम में अच्छी तरह से आवेगा, नहीं तो बड़े बड़े पूंजीपति इसका नाजायज फायदा उठाएंगे और यह रुपया फजूल में खर्च होगा।

श्री खेतसिंह—यह जो हमारे चीफ मिनिस्टर ने...

श्री मोतीलाल चौधरी—माननीय उपाध्यक्ष, मैंने पहले आपकी आई केच (eye catch) की है।

श्री उपाध्यक्ष—श्री मोतीलाल चौधरी।

श्री जवानसिंह—रूस का दृष्टिकोण तो हमने सुना ही नहीं।

श्री मोतीलाल चौधरी—माननीय उपाध्यक्ष, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो हमारे सामने है।

श्री मानसिंह महार—क्या इनको दुबारा बोलने की इजाजत है ? ये पहले बोल चुके हैं।...

श्री उपाध्यक्ष—क्या आप पहले बोल चुके है ?

श्री मोतीलाल चौधरी—कल नहीं बोला था।

श्री खेतसिंह—कल आप बोले नहीं, तो बके तो थे।

श्री मोतीलाल चौधरी—कल मुझे बोलने का अधिकार दिया गया था।

श्री मानसिंह महार—इसलिये आज इनको पहले ही बोलना चाहिये था। इन्होंने अपने अधिकार को फोर्फीट कर दिया है।

श्री उपाध्यक्ष—आप संक्षेप में ही बोलें।

श्री मोतीलाल चौधरी—वे रूस के है और मैं यहीं का हूं।

माननीय उपाध्यक्ष, द्वितीय पंच वर्षीय योजना में जो हमारे सामने है उसकी धन राशि प्रथम पंचवर्षीय योजना के बाद किस तरह से बढ़ी है और उसी कारण से हमारी सरकार के माननीय चीफ मिनिस्टर ने जो यह योजना के सम्बन्ध में किस तरह से यह बनाई है इसके लिये हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं और उनको वास्तविक धन्यवाद देते हैं। लेकिन इसके बाद में जब हम इस पंचवर्षीय योजना की ओर देखते हैं तो इसमें बहुत कमियें रह गई हैं। चाहे तो वह इस वजह से हुई हों कि बहुत सी चीजें रेकर्ड नहीं हुई हों या यह हो सकता है कि प्लानिंग वालों को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं हो। चाहे यह कारण हो सकता है कि उनका दृष्टिकोण दूसरा हो और मैं जो दृष्टिकोण लेकर चलता हूँ वह दूसरा हो। मैं यह दृष्टिकोण लेकर चलता हूँ कि एक करोड़ ५५ लाख की आबादी के अन्दर १ करोड़ २६ लाख पब्लिक है, वह गांवों में रहती है और बाकी की जनता शहरों में लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसमें ग्रामीण जनता को उदासीन रखा गया है। गांवों का जितना दृष्टिकोण होना चाहिये नहीं लिया गया है। गांवों की

[श्री मोतीलाल चौधरी]

पोपुलेशन से १।५ हिस्सा शहरों में पोपुलेशन का रहता है, लेकिन फिर भी उनके डेवलपमेंट के लिये ज्यादा पैसा खर्च करने के लिये रखा गया है। माननीय उपाध्यक्ष, मैं उदाहरण दूंगा। आप जैसे ड्रिंकिंग वाटर को ही लीजिये। पानी की व्यवस्था के लिये चीफ मिनिस्टर ने बहुत जोरों से कहा था कि पानी की मुसीबत पहले दूर करनी है। हर एक सरकार का प्रथम कर्तव्य है कि वह इस पानी की समस्या को हल करे। मगर इस सम्बन्ध में भी कितनी उदासीनता दिखाई गई है? गांवों में कुल रकम इस कार्य के लिये जो रखी गई है वह है दो करोड़ रुपया और चीफ मिनिस्टर ने अपने भाषण में कहा था कि १।। करोड़ रुपया हर ब्लोक के मारफत खर्च अलग किया जावेगा। इस पंचवर्षीय योजना के सिलसिले में तो सिर्फ १० जगह काम होगा और इसके अलावा ४ बड़े शहरों में काम पूरे होंगे : जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और (अश्रव्य) में वह रुपया ३ करोड़ ७८ लाख होगा और एक करोड़ २२ लाख और होगा; कुल मिला कर ५ करोड़ रुपया है। इसके अलावा जो जोधपुर के लिये पानी का रखा गया है उसके अलावा ५ करोड़ रुपया खर्च होगा।

माननीय उपाध्यक्ष, शहरों में जहां आबादी कम है वहां पर ५ करोड़ का खर्चा होगा और गांवों के अन्दर सिर्फ ३ करोड़ रुपया खर्च होगा। शहरों की आबादी ५,४८,३६६ है और गांवों की आबादी एक करोड़ २६ लाख है। इसके साथ साथ में एक चीज और आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि गांवों में जो मनुष्य रहते हैं वे पानी पीते हैं। साथ में राजस्थान के किसानों के पास पशुधन भी रहता है जो उनके रात-दिन प्रयोग में आते हैं उसको बिल्कुल आप भूल गये। पशुधन की संख्या मनुष्यों से चौगुनी है और एक आदमी से वे १० गुना ज्यादा पानी पीते हैं। इसके लिये बात इस प्लानिंग में नहीं रखी गई। कहां यह ३।। करोड़ गांव के पशुधन और मनुष्यों के लिये और कहां शहरों के रहने वालों के लिये ५ करोड़। जहां २६ लाख की पब्लिक है उसके लिये ५ करोड़ और जहां ५ करोड़ के लिये ३ या ३।। लाख रुपया रखा गया हैं।

(श्री अध्यक्ष पुनः ११.३० बजे पदासीन)

इस दृष्टिकोण से मैं इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि इस तरह का इन्टेंशन हो सकता है, मैं नहीं कहता कि जानबूझ कर रखा हो, प्लान करते समय सरकार पशुधन के दृष्टिकोण को भूल गई होगी, पशुओं की आवाज उनके कानों में पड़ी नहीं होगी, वैसे पशुओं की आवाज उनके कानों में कम ही आती है, गांवों के लोगों को तकलीफ भोगनी पड़ती है।

उसके अलावा माननीय अध्यक्ष, एक और चीज मेरे सामने आई है और उसे दूसरे उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करता हूँ, हेल्थ के दृष्टिकोण को देखते हुए। हेल्थ में रखा है कि कहां क्या

[श्री मोतीलाल चौधरी]

बनने वाला है, क्या बनेगा, कहां डिस्पेन्सरी होगी, कहां टी. बी. सेनिटोरियम होगा। मैं कहता हूँ कि आज राजस्थान में जो खाद्य और अखाद्य हो रहा है उसके लिए क्या किया? माननीय अध्यक्ष, मेरे कहने का विषय यह है कि राजस्थान के अन्दर सेल्स टैक्स बिल पास होने के पहले से आज तक वेजिटेबल घी का प्रवेश नहीं हुआ और जबसे प्रवेश हुआ है सरकार खुद मानती है, सरकार के मंत्रीगण खुद मानते हैं कि राजस्थान में बड़ी मुश्किलें पैदा हो गई शुद्ध घी मिलने में। राजस्थान ऐसा प्रांत है, हिन्दुस्तान में पहला प्रांत है जहां सबसे ज्यादा पशु हैं, अच्छा घी मिल सकता है, वेजीटेबल घी यहां लाने की आवश्यकता नहीं है, वेजीटेबिल घी को रोकने की आवश्यकता है लेकिन वेजीटेबिल घी में मिश्रण करके जब यहां पर पहुँचता था उसको रोकने के लिए भी कुछ नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष, यदि मैं इससे भी आगे कहूं तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। प्योर घी उपलब्ध करने के लिए राजस्थान सरकार के पास कोई प्रोग्राम नहीं। बल्कि राजस्थान पहला हिन्दुस्तान का प्रान्त है जहां १,६६ लाख जनसंख्या है, ज्यादा वेजिटेरियन हैं, जो मांस नहीं खाती है, अंडे नहीं खाती है लेकिन प्लान में मांस, अंडे और मछलियों की व्यवस्था की गई है; घी और दूध की नहीं। मैं आपको आंकड़े दूं कि मछलियों के डेवलपमेंट के लिए ६ लाख रुपये रखे गये हैं और साथ ही साथ डेरी डेवलेपमेंट के लिए दूध बटर वगैरा के लिए सिर्फ ६ लाख रुपये रखे हैं और उसके अलावा मुर्गियों के पालन के लिए, एक अचम्भा होता है, वास्तव में एक अचम्भा होता है कि मुर्गी के अंडे खाने वाले मिलेंगे राजस्थान में एक प्रतिशत या दो प्रतिशत।

श्री अध्यक्ष—Mr. Motilal is Jain.

श्री मोतीलाल चौधरी—इस सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष, इस दृष्टिकोण से नहीं कह रहा हूँ कि मैं जैनी हूं, बल्कि धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मैं यह कह रहा था। राजस्थान की बहुसंख्यक जन संख्या वेजिटेरियन है और यहां की जनता कमती खाती है। तो अंडों के लिए व्यवस्था ४ लाख रुपयों की की गई है, मछलियों के लिए ११ लाख रुपया; कुल १५ लाख रुपया रखा है और दूध के लिए और वह भी गौशाला को सुधारने के लिए ६ लाख रुपये रखे हैं। शुरू में रखा था पांच लाख, पता नहीं बाद में क्या प्रभाव पड़ा कि ६ लाख कर दिया। माननीय अध्यक्ष, इस दृष्टिकोण से इस प्रश्न को देखता हूं, तो स्वास्थ्य सम्बन्धी कोई व्यवस्था नहीं रखी है। आयुर्वेद के सम्बन्ध में जब मैं देखता हूं तो यह कहने में कोई अत्युक्ति नहीं होगी कि गांवों में बीस बीस और तीस तीस माइल के फासले पर औषधालय का प्रबन्ध नहीं है। अगर कहीं हैं भी तो छोटा सा आयुर्वेद पोस्ट है, चारों तरफ के लोग दवा लेने वहां आते हैं। प्लान को देखते हैं तो मालूम होता है और मिनिस्टर साहब और सरकार भी मानती है कि शहरों के अन्दर बड़े २ होस्पिटल्स हैं और शहरों में दवाई-दारु के लिए, इलाज के लिये आने पर ग्रामीण जनता को डबल खर्चा करना पड़ता है; जितना सरकार करती है उससे डबल खर्चा करना पड़ता है, लेकिन फिर भी उनके लिए इलाज की पूरी व्यवस्था नहीं है। यदि गांवों में उनको आयुर्वेदिक दवाई मिल जाय तो

[श्री मोतीलाल चौधरी]

उसको ग्रहण करने के लिए वे तैयार रहते हैं। इस सम्बन्ध में इक चौथाई रकम की व्यवस्था हो सकी है यानी ५३ लाख रुपये आयुर्वेद के लिए रखे हैं; कुल १ करोड़ २६ लाख रुपयों में से जो स्वास्थ्य के लिए रखे गये हैं। इस हिसाब से जन-संख्या की दृष्टि से आयुर्वेद में जो ५६ लाख रुपये की रकम रखी गई है वह प्रत्येक आठ आना पड़ती है। मैं आपको एक बड़ी प्रोबलम के बारे में बताऊं जिसके लिए या तो अधिकारीगण समझते नहीं होंगे, दवाई नहीं होगी या उनकी बुद्धि चलती नहीं होगी। राजस्थान के अन्दर सबसे ज्यादा प्रोबलम है और जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है वह है गिनीवोर्म का जिसे बाला कहते हैं। गांव से आने वाले प्रत्येक मंत्री गण, प्रत्येक अधिकारी सब जानते हैं कि किसानों को उस बीमारी से कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है

कुं० श्री जसवन्तसिंह—आप तो शहरी हो।

श्री मोतीलाल चौधरी—मैं शहरी नहीं हूं, बिल्कुल गांव का किसान हूं; आप भ्रम में हैं। मेरे लिए नहीं, मैं देश की जनता की बात कर रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष, अगर एक किसान के नेरू निकल जाता है, वह हाथ में निकल जाता है, जीभ में, शरीर के किसी भाग में निकल जाता है; तो उसकी स्थिति क्या होती होगी, उसकी स्थिति यह होती है कि अगर तीन आदमी परिवार में काम करने वाले हैं; खेत में फसल खड़ी की खड़ी रह जाती है, इससे साथ ही साथ देश की पैदावार और खाद्य भंडार को तो नुकसान पहुँचता ही है जो कि एक तरह से नेशनल लोस है, लेकिन उस गिनीवोर्म के इलाज के लिए एक पैसा भी नहीं रखा है। असेम्बली जब से शुरु हुई थी, बजट की चर्चा के समय इस पर भी चर्चा की गई थी और उस पर कहा गया था कि डा० चोपडा की रिपोर्ट आ रही है, रिसर्च हो रही है, तो क्या अब तक कोई मेडिसिन निकली नहीं है, न आगे पंचवर्षीय योजना में ही इसके लिए कुछ रखा गया है। सरकार ने सोचा होगा कि यह समस्या सुलझने की स्थिति में नहीं है और इसलिए बजट में नहीं रखा होगा। माननीय अध्यक्ष, मैं विनम्र शब्दों के साथ अर्ज करूंगा कि डिस्पेन्सरीज़ खोलेंगे मकान बनावेंगे और उसके लिए २० लाख रुपया रखा है, हमें कोई जरूरत नही है, जहां डिस्पेन्सरीज़ खुलेंगी गांवों में, वहां we are ready to give the buildings, होस्पिटल्स खुलेंगे हम मकान देंगे, रुपया देंगे, डोनेट करके देंगे, आप तो गांवों के अन्दर डिस्पेन्सरीज़ खोलिये। शहरों के अन्दर बीस लाख के मकान बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, शहरों के अन्दर बीस-बीस लाख के मकान बनाकर खोलते हैं तो वहां न खोलकर गांवों की जनता जो कि बिना इलाज के रहती है उनके लिए दवाइयों की व्यवस्था करिये। जो प्रोग्राम बनता है वह शहरों की जनता के लिए है और गांवों की जनता के लिए दवाई तक का प्रोविजन नहीं किया है, १.२ जनता नहीं १ करोड़ बीस लाख जनता उस गिनीवार्म की पीड से पीड़ित हैं, उसके लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इस तरह अध्यक्ष महोदय, बाकी की योजना में एक सौतेली भावना है, मैं सौतेली तो नहीं कहूंगा; लेकिन दूसरे दृष्टिकोण की भावना कह सकता हूं।

[श्री मोतीलाल चौधरी]

प्लान बनाने वाले अधिकारियों और माननीय मन्त्री महोदय के यह ध्यान में नहीं आया; ओवर साइट हो सकती है, मालूम नहीं यह कैसे हुआ ? यह सत्य है कि यह प्लान हमारे सामने आया । गांवों के दृष्टिकोण से जनता के हित की दृष्टि से, आप कहेंगे कि खेती के लिए हमने इतना किया है, हमने तकावी के लिए इतना किया है, हमने नहरों के लिए इतना किया है ।

आप जहां नहरों और तालाबों का प्रोवीज़न करते हैं तो यह हमारे पर एहसान नहीं, यह देश की उन्नति के लिए करते हैं । देश के डेवलपमेंट्स के लिए आप ये सब कर रहे हैं । देश में जो बसने वाली जनता है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना भी आपका कर्तव्य है उनको शुद्ध पानी पीने को मिले, यह भी व्यवस्था सरकार द्वारा ही होनी चाहिए । एक तरफ शहरों के अन्दर वाटर वर्क्स बनते हैं, पाइप लगते हैं और उनको पीने के लिए प्युरीफाइड पानी देते हैं और दूसरी ओर गांवों के अन्दर जो लोग कुओं की मांग करते हैं उन कुओं की व्यवस्था के लिये रुपयों की कमी करते हैं ।

अब मैं इसके बाद इस प्लान का एक्ज़ीक्युशन किस प्रकार होगा इसके बारे में निवेदन करना चाहता हूँ । मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखूं; प्रथम पंचवर्षीय योजना का इसमें किस तरह का कार्य हुआ ; मैं खुद ऐसे १२ जिलों में फिरा हूँ और मेरे पास एक से एक दिलचस्प उदाहरण मौजूद हैं जिनको सुन कर आपको ताज्जुब होगा, क्या स्थिति है । एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट है, जिस कम्युनिटी प्रोजेक्ट के अन्दर १० महीनों तक एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ । जब हमने वहां पर काम करने वाले अफसरों से पूछा कि आप क्या करते हैं तो वे कहते हैं कि हम बैठे हैं, हमारे पास इत्तला नहीं । इसकी इत्तला मैंने अपने साथियों से और माननीय मन्त्री महोदय को भी दी । मैं उसका नाम भी ले लूं तो कोई बेजा बात नहीं होगी । उस कम्युनिटी प्रोजेक्ट का नाम है रायसिंह नगर करणपुर । वहां पर कोई भी चेक कर ले, वहां के काम को देख ले, हरेक को प्रतीत होगा कि वहां किस तरह का काम चालू है ? अगर उसी तरह का काम इस प्लान में चलायेंगे तो फिर ईश्वर ही मालिक है । इस तरह के एक नहीं सैकड़ों उदाहरण एक्जीक्युशन प्लान के करते समय किस तरह की भावनायें और किस तरह का काम अधिकारीगण लेते हैं ? इतना ही नहीं प्रत्येक कम्युनिटी प्रोजेक्ट को देखा जाय तो आपको पता चलेगा जो एडवाइजरी कमेटी इनके लिए बनाई हुई है उनको किसी प्रकार के अधिकार न देने से अधिकारीगण मनमानी करते हैं । कमेटी को अधिकार नहीं देने के कारण ही गलतियां हो रही हैं ।

माननीय अध्यक्ष, ऑल इन्डिया फार्मर्स की मीटिंग दिल्ली में हुई थी उस समय माननीय मि० डे ने कहा था फाइव इयर प्लान के लिए कि यह जनता के लिए है, जनता द्वारा बनाई हुई है और जनता की राय से ही चलने वाली है । मैंने उसी वक्त इस बात का खन्डन किया कि यह बिल्कुल सही नहीं । मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वहां तो मैंने खंडन किया इसलिए कि वहां गलत भावना थी, उसको दूर करना था । यहां भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो एडवा-

[श्री मोतीलाल चौधरी]

इज़री कमेटी इन कामों के लिये बनाई जाती है उनके हाथ में किसी तरह के पावर न होने से वहां जो काम चलता है वह कम्युनिटी-प्रोजेक्ट के इन्चार्ज के कहने के मुताबिक काम चलता है। वहां न तो अकाउन्ट ही ठीक तरह से मेन्टेन होता है, न मालूम उसको ऑडिट विभाग किस प्रकार से चेक करते होंगे, विभागीय जांच उन हिसाबों की किस प्रकार होती होगी हमें पता नहीं। आप एक प्रोजेक्ट के जीप का ही हिसाब ले लीजिये; जीप कहां कहां काम आती है क्या क्या काम आई उससे ही आपको साफ जाहिर हो जायगा कि कितना सरकारी पैसों का मिस यूज़ किया जाता है ? इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो कमेटी बनाई जाय उसको कुछ न कुछ पॉवर अवश्य मिलने चाहिये।

अब मैं एक उद्योग के बारे में जिक्र करूंगा। हैन्डलूम के लिये ३॥ लाख रुपये रखे गये थे, चार वर्ष बीत जाने के बाद उन रुपयों को मांगा गया। उसके लिये आखिर में जाकर यह कहा गया कि रुपया हम देते हैं; तीन महीने के अन्दर अन्दर इस रुपये को लगा दो। नागौर जिले के अन्दर हैन्डलूम फैक्टरी कायम की गई। रुपया उसमें लग चुका लेकिन अभी तक एक गज भी कपड़ा उस फैक्टरी से पैदा नहीं हुआ। बस सिर्फ यह मान बैठे हैं कि रुपया खर्च हो गया और हैन्डलूम का कार्य हो गया, यह मान बैठे हैं। वहां सेल्समेन भेज दिये गए, वे क्या काम करते हैं मालूम नहीं। जबकि वहां दो महीने से एक इंच भी कपड़ा पैदा नहीं हुआ तो उन सेल्समैनों के भेजने से क्या फायदा ? जब मैंने इस बारे में मंत्री जी को भी कहा था। इस प्रकार साढ़े तीन लाख रुपये के अन्दर जहां हैंन्डलूम को प्रोत्साहन देने के लिये रखा था उस पूरी स्कीम को चालू न करके पहले से ही सेल्समैन आदि को भेज दिया गया। इसी प्रकार सारी स्कीम के लिए जो ३॥ लाख रुपया रखा गया था, उसमें से करीब दो लाख रुपया पदाधिकारीगण की नियुक्ति आदि में ही खर्च हो गया। अगर इसी तरह से हमने इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी किया तो सारा पैसा स्टाफ के अपोइन्टमेंट्स, अधिकारीगणों की नियुक्ति आदि में खर्च हो जायगा। मैंने इस बारे में उद्योग मंत्री और उस समय के डाइरेक्टर महोदय को भी कहा था कि जब तक फैक्ट्री अच्छी तरह से एस्टेब्लिश न हो जाय तब तक किसी प्रकार का स्टाफ अपोइन्ट न किया जाय।

इसी तरह बेकवर्ड क्लास के सम्बन्ध में भी हुआ है.......

श्री खेतसिंह—माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य को १५ मिनिट से भी ज्यादा समय बोलते हुए हो गया। मुझे समय दिया जाय, मैं अपना वक्तव्य दो ही मिनिट में पूरा कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष— I was thinking whether they are discussing on the Rajpramukh's Address.

श्री मोतीलाल— I am speaking on the execution of the Plan: how this Plan is going to be executed.

[श्री मोतीलाल चौधरी]

अब मैं बेकवर्ड क्लास को छोड़ देता हूं क्योंकि बेकवर्ड आखिर बेकवर्ड ही हैं। सड़कों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। सड़कों संबन्धी जो आइटम्स हैं, उसमें यह है कि पांच हजार को एरिया की आबादी का प्रत्येक गांव बड़ी सड़क से मिला दिया जायगा। इसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह किस दृष्टिकोण के आधार पर आपने क्राइटेरिया बनाया है। राजस्थान ज्यादा गांवों के अन्दर बसा हुआ है, ऐसे गांव जो समूह में से हुए हों वे बहुत कम हैं; जिनकी जनसंख्या २०, ३० लाख से ज्यादा नहीं होगी। बाकी १ करोड़ बीस लाख जनता छोटे छोटे गांवों में बसी हुई है। इसके अन्दर मेरा यह सुझाव है कि जनसंख्या की जगह बाई माईलेज, इतने मिल के अन्दर जो भी डिस्टेन्स होगा यह बड़ी सड़कों से जोड़ दिया जायगा; इस प्रकार का आधार होना चाहिये। हाउस जनसंख्या का दृष्टिकोण न रखे; within a radius of two miles or three miles or five miles: ऐसी व्यवस्था की जाय तो अच्छा होगा।

अन्त में मैं एक बात और निवेदन कर बैठ जाऊंगा सरकार से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि जिस तरह का यह प्लान बना है बड़ा सी सुन्दर है, लेकिन हमें इसके एक्जीक्युशन की ओर काफी ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ इलाके ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुके हैं; जहां चंबल, भाखरा और भी तरह तरह के प्रोजेक्टस चल रहे हैं लेकिन उन स्थानों के अन्दर जहां इन प्रोजेक्ट्स का कोई असर नहीं हो सकता उन बेकवर्ड एरियाज़ के लिये भी रुपया अधिक रखना चाहिये। जैसा कि मुख्य मंत्री महोदय ने कहा इसमें चेन्ज भी हो सकते हैं। मैंने जिस प्रकार कहा बेकवर्ड एरियाज़ के लिये कुछ धनराशि बढ़ाई जानी चाहिये।

अन्त में मैं पानी की व्यवस्था के संबन्ध में कुछ अर्ज करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष—There will be so many occasions for bringing these things to the notice of the House...

श्री मोतीलाल चोधरी—पानी की व्यवस्था के लिये जो योजना रखी है वह सुन्दर है पंम्पिंग सेट के संबन्ध में। मैं यही सरकार से निवेदन करूंगा।

श्री अध्यक्ष—Order ! I will like to ascertain as to how many member will like to speak on the Five Year Plan.

(कुछ माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

So we will meet this afternoon also .

श्री खेतसिंह—मैं तीन मिनिट ही लूंगा।

श्री अध्यक्ष—Shri Khetsingh, I will give priority to those who will take three minutes.

श्री खेतसिंह—माननीय अध्यक्ष, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना हमारे सामने आई है वह अत्यन्त सुन्दर बनी है और बहुत परिश्रम के साथ बनाई गई है । उसके लिए में राजस्थान सरकार और प्लानिंग विभाग से ताल्लुक रखने वाले अधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ ।

इसमें कोई शक नहीं; इस योजना में ग्रामीण जनता का काफी खयाल रखा गया है इसलिए इरीगेशन, एग्रीकलचर रोड आदि के लिए ६५ प्रतिशत खर्च किया जा रहा है इस योजना के मातहत । साथ में कई कल्याणकारी कार्यों में काफी खर्च किया जा रहा है, फिर भी मैं अर्ज करूंगा इसमें बहुत सी कमियां है जिनको मैं आपके सम्मुख रखना चाहूँगा ।

श्री अध्यक्ष—That is a self-imposed restriction.

श्री खेतसिंह— इसमें बतायी हुई मैंने सारी योजनाओं को पढ़ा मुझे ऐसा मालूम हुआ यह योजना महज ३।४ (तीन चौथाई) हिस्से के लिये बनी है । इसमें एक चौथाई हिस्से को बिल्कुल छोड़ दिया गया है ।

श्री जसवन्तसिंह—You are in good company with me.

श्री मोतीलाल चौधरी— उसके लिए मैं फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा । कल मैंने माननीय मुख्य मन्त्रीजी का भाषण सुना । मुझे यह मालूम हुआ, जो भी इस पंचवर्षीय योजना में पैसा प्राप्त होगा वह सारा पोपूलेशन बेसिस पर खर्च किया जायगा । इसके लिए जिस गांव की आबादी पांच हजार होगी वह गांव सड़कों से जोड़ दिया जायगा. जिस गांव की आबादी पांच हजार होगी वहां अस्पताल होगा । इससे यह साफ जाहिर है कि राजस्थान में ऐसा भी हिस्सा है जहां की आबादी स्केटर्ड है; जहां पर पांच—पांच हजार की आबादी वाले बहुत कम गांव हैं, जिनमें २००—३०० गांव हैं । इस प्रकार से जैसलमेर का पूरा इलाका, शेरगढ़, शिव—बाड़मेर और बीकानेर का काफी हिस्सा.........

श्री जसवन्तसिंह—Hear, Hear.

श्री खेतसिंह—ज्यों के ज्यों बचे रहेंगे; जैसे कि पहली पंचवर्षीयव योजना में बचे रहे । इसलिए में यह निवेदन करूंगा कि जो पॉपुलेशन के बेसिस को ध्यान में रखकर सारी योजना तैयार की गई है उसके साथ साथ यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, उस एरिया में वास्तव में कितनी आवश्यकता है । जैसा कि हमारे वहां पर महज एक डिस्पेन्सरी है हालांकि उस एरिया की आबादी १,०६,००० की है । उसमें कोई ऐसा गांव नहीं है जिसकी आबादी ५ हजार हो । ऐसी परिस्थिती में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी कोई अस्पताल वहां पर नहीं खोल सकते हैं । इसलिए जहां थे वहीं के वहीं रहेंगे । रियासती वक्त का वहां एक अस्पताल है । हमें क्या मालूम होगा कि हमारे लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना तैयार हुई है और वह क्रियान्वित हो रही है ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—अपने हाथ में यह पुस्तक रखिये।

श्री खेतसिंह—किसी पुस्तक से सेटिस्फेक्शन नहीं होता है।

उस इलाके के लिए यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि १५ मील के एरिया में एक अस्पताल नसीब होना चाहिए। लेकिन वहां ४०,४० मील के एरिया में कोई अस्पताल नसीब नहीं होता है। यह हमारे साथ में घोर अन्याय होगा अगर आप पापुलेशन बेसिस पर रखेंगे तो। अगर पोपुलेशन बढ़ायें और इसका प्रयत्न करें तो भी यह इतनी जल्दी कैसे हो सकती है?

(हंसी)

इसी प्रकार से सड़कों का मामला है। सड़कों के लिए यह निवेदन करूंगा कि जहां पर रेलवे लाइन नहीं है, जहां कि कोई रोड नहीं हैं, जहां के लोग अपने यातायात के साधन रखें, महज ऊंट, जिस पर कि हमारे बाप दादे चढ़ते आये है, उसी को लेकर बैठे रहेंगे तो हमें क्या मालूम होगा कि हम आजाद हुए हैं। हमारे यहां पंचवर्षीय योजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि वैसे एरिया का ध्यान रखा जाय कि कम से कम १० मील की दूरी पर एक सड़क होना आवश्यक है। इसलिए एरियाज़ को बेसिस रख कर जैसलमेर और रेगिस्तान का जितना इलाका है उसमें यह कार्य किये जाय।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करूंगा कि इरिगेशन के लिए एग्रिकलचर के लिए हमारे सामने ६५ परसेन्ट रखा गया है। लेकिन उसमें से हमको एक पैसा भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए नहीं है कि वहां पर कोई इरिगेशन की फेसिलिटीज़ नहीं कर सकते हैं. वह एक फसली इलाके हैं जिनमें कि अगर भगवान भेजता है, अगर बारिश हो जाती है तो काम हो जाता है, कुछ पैदा हो जाता है, नहीं तो जैसा कि इस वर्ष जहां कि और जगह बाढ़ें आ रही हैं, हिन्दुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि १०० वर्षों से ऐसा कोई वर्ष नहीं हुआ जिसमें कि इतनी बारिश हुई हो, लेकिन हम बदनसीब हैं कि हमें एक बारिश की जरूरत है; अगर वह बारिश नहीं होती है, तो अभी भी वहां घोर अकाल होगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि उस एक्स्ट्राऑर्डीनरी इलाके में भगवान की भी कभी महरबानी नहीं रहती है तो कम से कम आपसे यह निवेदन करूंगा, माननीय अध्यक्ष, आपकी मारफत सरकार से निवेदन करूंगा कि कम से कम कुछ रियायत वहां के लिए एरिया के बेसिस पर इस योजना में करें।

इसके साथ साथ जब हमारा पंचायत एक्ट बना, उसके अन्दर ऐसा मालूम होता है कि दूसरे राज्यों के हिसाब से इन पंचायतों पर व्यय करने के लिए खर्चा बहुत कम किया जा रहा है। और पंचायत एक ऐसा महकमा है कि जो आजाद भारत में अपना महत्व रखता है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि जो राजस्थान में ३२ लाख की धनराशि पंचायतों को प्रोत्साहन देने के लिए रखी गई है वह कम है। राजस्थान एक बहुत बड़ा देश है इसलिए यहां यह रकम करोड़ों की

Page No.59

[श्री खेतसिंह]

होनी चाहिये। मैंने यह देखा कि इसी योजना में ढाई करोड़ रुपया हैदराबाद में पंचायतों पर खर्च किया जा रहा है। जब कि वहां पंचायतों का नम्बर अधिक से अधिक २ हजार तक का है और यहां ३ हजार से अधिक पंचायतें हैं; तो मुझे यह नहीं मालूम हुआ कि इतना कम रुपया क्यों रखा गया, और किसकी गलती से रखा गया है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस हैड को वापिस ध्यान में लें और पंचायतों के लिये अधिक से अधिक खर्च करना होगा यदि पंचायतों को बढ़ावा देना है तो।

इसके अलावा यह भी निवेदन करूंगा कि रेगिस्तानी इलाके के लिए एक कमेटी नियुक्त करनी चाहिये। वहां का सर्वे होना चाहिये। कल ही एक सदस्य महोदय ने यह निवेदन किया कि जेसलमेर में पेट्रोलियम निकलता है। वहां पर अभी एक अमेरिकन एक्सपर्ट भी गये थे, मैं भी उस वक्त वहां पर था, तो उन्होंने वहां की रोक को देखकर कहा था कि वह रोक ईरान और ईराक की रोक से मिलती है। हो सकता है कि यहां पर पेट्रोल है। ऐसी परिस्थिति में हमें भारत सरकार से निवेदन करके एक्सपेरीमेंट करवाना चाहिए और हो सकता है कि वहां पेट्रोल निकले।

इसके साथ में मैं यह निवेदन करूंगा कि शिव में जोधपुर रियासत के जमाने में कोयले के लिए काफी प्रयत्न किये गये हैं। वहां पर काला पत्थर निकला है, लेकिन अभी तक खनिज विभाग की ओर से कोई आदमी नहीं गया है, और किसी ने कोई प्रयत्न नहीं किया। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि दुबारा वापिस सर्वे होनी चाहिए और उस पत्थर को देखना चाहिए और खुदाई करवानी चाहिए, और यदि ऐसा कोई वहां खनिज निकल जाय तो हमारा अहोभाग्य है। शेरगढ़ में एक स्थान है जहां पर खड़िया मिट्टी बहुत अच्छी होती है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उन्हें रेगिस्तान के इलाके का टूर करना चाहिये। वहां पर लूएं चलती हैं। वे तो सरसब्ज़ इलाके में ही जाना चाहते हैं। वहां पर हेड ऑफ दी डिपार्टमेंट को भेजकर दिखाया जाय। हो सकता है कि इससे हमें काफी फायदा मिल सकता है।

श्री विशम्भरनाथ जोशी—Mr. Speaker, Sir, I wish to make a few observations on the proposals of the Second Five Year Plan.

("हिन्दी, हिन्दी" ऐसी आवाज)

At the outset, Sir, I wish to say...

('हिन्दी में बोलिए' ऐसी आवाज)

I submit, Sir, that according to the Rules of procedure and...

श्री अध्यक्ष--Don't get disturbed.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी (जारी)—At the outset, Sir, I wish to state that these proposals have been submitted before this House at rether a very late stage. Only the other day when the proposals were being discussed in the meeting of the Rajasthan Planning Board, it was stated by the Hon'ble Chief Minister that since the Proposals have now been submitted to and accepted by the Planning Commission, Government of India, it is not now possible to effect any material alterations therein. That being so, the House has been presented with a virtual 'fait accompli,' and I cannot very well appreciate the purpose of these discussions which are taking place in the House. If the proposals are to remain in the present stage and if it is not possible for the Government to effect any alteration therein, then the entire purpose of discussing these proposals in this House is lost.

This, Sir, is supposed to be the People's Plan. It was stated by the Prime Minister of this country, as well as all those responsible for putting up the proposals that the public and the residents of the villages and those living in the farthest and remotest hamlet will be associated in the formulation of the Proposals, and it was decided that the various proposals should emanate from the people themselves. As far as Rajasthan is concerned, I am constrained to observe that this purpose has been entirely lost. If the proposals now cannot be altered, it was incumbent on the Government to lay these proposa's before submission to the Government of India, before this House. Perhaps the Government feared that these proposals may not be adopted fully and that the may not stand the searching scrutiny of this s House. Therefore, a very strange procedure was followed whereby even the representatives of the people, what to say of the people themselves, were deprived of having their say or having a proper participation in the formulation of these Proposals. When instead of the public, even the public's elected representatives, on whose voice and on whose opinion the existence of the Government itself depends, cannot havet heir say in the preparation and formulation of the proposals, I cannot understand in what sense of the word this can be called a people's plan. Therfore, I would very earnestly appeal to the Government through you, Sir, that the Government, in the light of the discussions that are taking Place, should consider the proposals, and as was stated by the Hon'ble Prime Minister and the Members of the Planning Commission, since the Plan is flexible, it should be modified and altered in the light of the discussions which are taking place in the House.

As regards the Plan itself, I would like to say a few words. As far as allotment for irrigation and power is concerned, the increase in the Second

[श्री विश्वम्भरनाथ जोशी]

Plan as compared with the figures of the First Plan is very poor, In the first instance, the amount sanctioned was 39.36 lacs, whereas in the present Plan, it is only 44 crores. Now the total amount under the First Plan is some what in the vicinity of 25 crores and the present plan amount is five times the amont under the First Plan whereas the head power and irrigation has registered an increase of about 12% only which is very poor. This province, as we all know, is a Province with a predominantly agricultural economy. Need for irrigation also is realised by every body and inspite of the irrigation facilities which have been available during the First Plan there is vast scope for irrigatton. Large tracts of land are still lying barren without availability of water Inspite of this the amount sanctioned for irrigation is grossly inadequate.

Regarding electricity, I have to state that in the frirst place, provision for rural electrification, which is only 80 lacs, is grossly inadequate in view of the fact that at present the cost of electrification is very high, and in a smallest village it will come to about Rs. 50,000. Thus with the total allotment of Rs. 80 lacs, only 160 villages can be electrified throughout the entire period of the Second Five Year plan. Now ordinarily one Tehsil comprises 160 to 200 villages. It would, therefore, meet the needs of only one out of 211 Tehsils at the most which is 1/200th of the rural population of Rajasthan can be served out of the very poor grant that has been made under the Second Plan.

Besides, Sir, I have to say something about the Panchayats also. Finance has always been a weak point of these Panchayats and it is a matter of common observation that Panchayats are not able to function as effectively as otherwise they should do if they had not been dependent on the State Government for their finances. The total amount sanctioned for Panchayats is 37 lacs which has to be spread over a period of five years. With about 4,000 Panchayats in Rajasthan it would work out to something like Rs. 300 per Panchayat per year or Rs. 25/- per Panchayat per month. I need hardly say that this would suffice only to defray the salary of a peon in the Panchayat Board.

We want to make the villages self-sufficient. We want to make these Panchayats small autonomous republics of Free India. But I am constrained to observe that there is something fundamentally and basically wrong in the Panchayat Raj conception of the Government. Otherwise this poor pittance of a grant would not have been there.

[श्री विश्वम्भरनाथ जोशी]

A very large section of our population resides in the villages. 'Back to the villages' is the slogan resounding in the Free India today. Mahatma Gandhi, the Father of the Nation, also never tired of exhorting that the Soul of India resides in villages. We also profess loud sympathies with the backward villagers and peasants. In spite of this, the extremely inadequate grant of Rs. 37 lacs for the 4,000 Panchayats is a matter which passes comprehension.

Besides, Sir, I have to say that in the figures which have been placed before us there is no mention, as far as I can see, for the local development works, regarding which it has been stated that the Central Government should allot some amount for local Development works. I have to submit and it is my personal experience that under this head a good deal of rural service can be rendered to the backward rural areas. Incidentally, I happen to be a member both of the Rajasthan Planning Board and the District Development Committee, and I must frankly confess that I have not been able to contribute anythinge ffectively as a member of the Rajasthan Planning Board whereas in my capacity as a member of the District Development Committee, I feel that I have contributed something at least towards the redress of local grievances. For instance, we are able to have double utility of the amount there. In the local work one rupee is granted to the villager, provided one rupee, either in the shape of cash or honorary work is contributed by him. Therefore, for every rupee spent by the Government we are able to have work done worth Rs. 2/-. In the seco-place, a great deal of delay which otherwise occurs in the work undertaken by the dilatory departmental mechinery is obviated, and in the district development committees, local needs are more effectively and more speedily redresed, and what is said to be people's participation is achieved there. So the local development works reach the people to a far greater extent than this Plan at the State level and at the national level. Now it is very much to be regretted that in spite of this utility of the local development works, the Government has omitted to make any provision whatsoever for this which is a very necessary part of development programme.

Besides, Sir, I wish to make some mention about education also. The increment in the provision under education does not appear In resemblance to the ratio to the increment between the First Plan and the Second Plan. The Second thing which I wish to stress is that although we have brought about a large number of primary schools, raised primary schools to the status of middle schools and opened high schools we have been able to progress only quantitively in the field of education. I feel that there is very much to be desired as far as quality is concered. In education, as in all fields of life, quality counts in the end. I wish there should be something

Page No.63

[श्री विश्वम्भरनाथ जोशी]

done and more provision made to improve the quality of the present education, which is accepted by all standards and sections to be lacking and to be deficient.

Surely there is some provision for a Special College and as far as College and University education is concerned, it must be guided by the skilled opinion and provision must be made whereby it cannot be concluded that Government is not thinking in terms of the qualitative improvement of education.

One thing more I have to state regarding education and it is this. I feel that in the fieed of education, during the First Plan as well as in the Second Plan we have been treading along the beaten path, We want to satisfy ourselves by giving aid to a number of existing institutions and by making some sort of provision for giving a vocational bias to education. What I feel is that all this will never suffice and what is needed is a clear cut provision regarding education, regarding the type of education that is tode given and which should be given.

Education is a provincial subject and therefore we cannot always expect a lead from the Government of India, and one day or the other the provinces will have to take the initiative and they will have their own necessities as far as educational objective are concerned. A very responsible Minister of the Central Government had once stated that the Central Government has nothing to do regarding formulation of educational policy, education being a provincial subject in spite of this, what have we done in Rajasthan to give a new trend to education and to harmonise education with the needs of the society. We are continuing the same stereotyped system of education which was intended for producing clerks during the past British Raj and nowhere we are showing any signs of change in the type of education. I would have welcomed any provision for the institution of a commission to explore the entire field of education. A very basic thing has yet to be decided. After all, we have got to take a decision whether we are going to build our schools and tcolleges on the model of Cambridge, oxford or Harrow or on the model of Taksh-shila and Nalanda. It is a basic question and those who are responsible for formulating the educational policy seem to be highly confused regarding this and as far as the present Plan goes there appears to be no attempt to get out of this confusion.

Besides, Sir, regarding power I have to ray one thing more. At present important towns are going without electricity and their long standing grievances, persistently followed, are not met by Government. Though I am seldom influen

[श्री विश्वम्भरनाथ जोशी]

ced by parochial considerations and local loyalties, I am constralned to observe that !mportant ploces like Baswa and Bandiqui have failed to get thelr electric supply inspite of repeated representations to the Government, and in spite of this the provision during the Second Five Year Plan for electrification appears to be grossly inadequate, and with expectations for electric supply all the areas have been demanding this but since last many years their demands cannot be met.

In view of this, I would submit, Sir, through you to those who have formulated the Proposals that in the light of these discussions these Proposals are grossly lacking and without a formal and proper participation of people's representatives wbo are present in this House, these proposals require wholesale changes and drastic modifications and the same should be done in accordance with the suggestions which the Government must have received during this debate.

श्री राधाकृष्ण मारू—माननीय अध्यक्ष,....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, इन्टर्फियरेंस के लिये माफ करें। क्या शाम को भी हम मिल रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—That was the wish of the House.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—पूछ लीजिये एक बार।

श्री अध्यक्ष—क्या शाम को भी मिलेंगे ?....

एक माननीय सदस्य—बोलने वालों को २०-२० मिनट तो दिये जायं।

श्री अध्यक्ष—बीस-बीस मिनट बोलें, पर शाम को बैठने को तैयार हैं ?

श्री दिलीपसिंह—सोमवार को बैठक रखी जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—ऐसा है माननीय अध्यक्ष महोदय, कि सोमवार को मिलने के मामले में मुझे एतराज नहीं है पर बहुत से माननीय सदस्य यहां से जाना चाहते हैं, इसलिए नवरात्रि की वजह से कई सदस्य यहां से चले जायेंगे। १७ को मिलने से बहुत से व्यक्ति यहां होंगे नहीं। मुझे कोई इन्सिस्टेन्स नहीं है; चाहे अभी खत्म कर दीजिये, चाहे शाम को खत्म कर दीजिये, १७ को बहुत से यहां होंगे नहीं।

श्री दिलीपसिंह—जिन्हें बोलना होगा और सुनना होगा तो यहां रहेंगे। कोरम होगा तो अपने आप काम चलेगा।

श्री खेतसिंह—अगर आज शाम को रख कर खतम कर दें तो ठीक है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मेरा खयाल है कि दूसरे लोगों को एकोमोडेट करने के लिए आज शाम को दुबारा मिल लें।

श्री अध्यक्ष—शाम को दुबारा मीट करके फिर एड्जोर्न करेंगे ? But the time factor should be taken into consideration.

श्री राधाकृष्ण मारू—माननीय अध्यक्ष, माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने अपने भाषण में जो सदन को जानकारी कराई है और इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रथम पंचवर्षीय योजना से जो ज्यादा धन राशि दी गई है और इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने प्रयास करके बहुत बड़ी धन राशि मंजूर करवाई है, इसके लिए मैं समझता हूं कि हमारे सदन के माननीय सदस्य उनका आभार प्रदर्शन करेंगे। ऐसा भी आभास हो रहा है कि राजस्थान के प्लानिंग डिपार्टमेंट के अफसरों ने जो इसका प्लानिंग का नक्शा प्रोड्यूस किया है वह वास्तव में बहुत ही प्रशंसनीय है।

यह मैं मान कर चलता हूं कि राजस्थान भी इन्डस्ट्रियल प्रगति में बहुत कुछ पिछड़ा हुआ है और अभी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। हालांकि राजस्थान में रॉ मेटिरियल बहुत हैं और इसके मिनरल रिसोर्सेज़ भी बहुत ज्यादा हैं। मैं राजस्थान के मिनरल रिसोर्सेज़ की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करूं तो मुझे निवेदन करना पड़ेगा कि अभी हमारे यहां का जिओलोजिकल सर्वे पूरा नहीं हुआ है। मैं आशा करूंगा कि हमारे मुख्य मन्त्री महोदय इस ओर विशेष ध्यान देंगे और केन्द्रीय सरकार से इस बात की कोशिश करेंगे कि हमारे यहां के मिनरल रिसोर्सेज़ का सर्वे कराया जाय।

राजस्थान रॉ मेटिरियल्स में, वूल, जिप्सम, कोल, लाइम स्टोन; इन सब चीजों में काफी पोटेन्शियलिटी रखता है और यदि इन सारी चीजों से पनपने वाली इन्डस्ट्रीज़ हमारे यहां कायम की जायं तो राजस्थान का जीवन स्तर ऊंचा उठ सकता है और हमारे यहां की बेकारी दूर हो सकती है।

मैं माननीय मुख्य मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि केन्द्रीय सरकार से यहां के लिए शीघ्र इन्डस्ट्रीज़ को पनपाने के लिये सिफारिश करें।•••

Page No.66

[श्री राधाकृष्ण मारू]

आप उनके लिये कोटा एलोट करावें और जहां तक राजस्थान के अन्दर उसके प्रयोग का सम्बन्ध है मैं विश्वास दिला सकता हूँ कि उसके लिये उनका पूरा सहयोग मिलता रहेगा। हमारे यहां बहुत से खनिज पदार्थ हैं। इतना सब कुछ होते हुए भी हमारे यहां का जीवन-स्तर गिरा हुआ है और हमारे यहां बेकारी फैली हुई है। हम यह चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से हमारी बेकारी दूर हो और जनता का स्तर जो नीचे गिरा हुआ है किसी न किसी तरह से ऊंचा हो। हमारे सामने इस पंचवर्षीय योजना को रखा और माननीय सदस्यों ने इस पर विचार करते समय इसमें बहुत सी कमियें बताईं और उन्होंने किसी न किसी बात में इस प्लनिंग के अन्तर्गत कमी बताई। मैं समझता हूँ कि इतने बड़े प्लानिंग में कमियों का रह जाना कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन जो कुछ धन राशि एलोट हुई है उसको बहुत कम बताते हैं लेकिन इस कमी को बताते हुए वे इस बात को महसूस नहीं करते कि राजस्थान सरकार को भी इसमें अपना हिस्सा देना होगा और लगाना पड़ेगा और इस हिस्से को अदा करने में वे किस तरह से राजस्थान सरकार की सहायता करेंगे।

मैं समझता हूं कि सरकार अपने हिस्से को बाई लोन्स प्राप्त कर सकती है, (२) कुछ ऐसे टैक्स लगा कर जो किसी खास चीजों पर न लगे हों लगावें और ऐसी चीजों पर लगावें जिसका आम जनता पर असर न पड़ता हो और तीसरी स्माल सेविंग के जरिये से पैसा इकट्ठा किया जा सकता है। स्माल सेविंग स्कीम हमारे यहां मौजूदा समय में चल रही है। मुझे मालूम नहीं कि उसकी प्रगति कैसी है? अगर माननीय सदस्य जो अपने अपने क्षेत्र से आये हैं, अपने क्षेत्र में अगर सहयोग स्माल सेविंग को प्रोत्साहन देने के लिये देंगे तो इसमें काफी तरक्की हो सकती है और सरकार को रुपया मिल सकता है। बस इतना ही कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री भैरूसिंह (बरकाना)—माननीय अध्यक्ष, सदन के सामने द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर दो दिनों से बहस हो रही है। इसके लिये मैं सबसे पहले माननीय चीफ मिनिस्टर को धन्यवाद दिये बगैर नहीं रह सकता। (करतल-ध्वनि) मगर इसके साथ साथ मैं यह जरूर कहूंगा कि जब तक वे ऐसी रकम को राजस्थान के कोने कोने में, राजस्थान के गांव गांव में न बांट देंगे, इस धन राशि को सारे राजस्थान में नहीं बांट देंगे तब तक वे इस बधाई के पात्र नहीं हो सकते। मैं उनसे यह प्रार्थना करूंगा कि वे राजस्थान के सभी हिस्सों को बिना किसी भेद भाव के और पक्षपात के उचित रकम देने का प्रयत्न करेंगे।

मैंने आपको पहली पंचवर्षीय योजना में कई सुझाव दिये थे और आज भी थोड़े शब्दों में जितने सुझाव दे सकता हूं देने का प्रयत्न करूंगा।

[श्री भैरूंसिंह (बरकाना)]

पहला सुझाव मेरा शिक्षा के सम्बन्ध में है और वह इस प्रकार है कि आज की शिक्षा में आचारहीनता जगह जगह दिखाई देती है। इसलिये ऐसा कोई रास्ता निकाला जावे ताकि इसका कोई इन्तजाम हो सके और बच्चों के आचरण अच्छे हो सकें। इसके अलावा जो शिक्षा प्रणाली है वह ठीक नहीं है। इसको ठीक ढंग से बिठाने की कोशिश करें ताकि जब लड़के पढ़-लिख कर निकलें तब यह न कहें कि हमें नौकरी चाहिये। उनको ग्रामों में काम करना है, यह भी उनको सिखाया जाना चाहिये। इसलिये सरकार से मेरा अनुरोध है कि इसकी तरफ सरकार ध्यान दे और आशा करता हूं कि आगे इस पर अवश्य ध्यान दिया जावेगा।

इसके अलावा मेरा यह सरकार से अनुरोध है कि वह राजस्थानी भाषा को भी प्राथमिक शिक्षा में शामिल कर दें ताकि हर एक गांव के लोग प्रान्तीय भाषा को समझने की कोशिश करें। अन्धे, गूंगे तथा बहरों की शिक्षा का प्रबन्ध भी आवश्यक है।

अब थोड़ा सा मैं आपको अपनी कोन्स्टीट्यूएन्सी के बारे में अर्ज करूंगा और खास तौर से यातायात के सम्बन्ध में, देसूरी से राणी तक सड़क का कई वर्षों से प्रश्न चलता, है मगर वह सड़क देसूरी से राणी तक नहीं बनाई जाती। जोधपुर रियासत थी उस समय भी नहीं बनी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भी रह गई। अब आप लोग इसके मुतल्लिक क्या कर रहे हैं? मैं आशा करता हूँ कि अब इस पंचवर्षीय योजना में आप इसको अवश्य लेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस सड़क को इसमें जरूर शामिल कर लेंगें। दूसरा सुझाव यह है कि राणकपुर ऐसी जगह है जहां बहुत यात्री आते हैं और सिर्फ तीन मील का टुकड़ा पड़ता है। आशा करता हूँ वह भी इस पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया जावेगा।

अब कुछ मैं किसानों के बारे में भी अर्ज करना चाहता हूँ। काश्तकारों का कम से कम मुझे तीस सालों का अनुभव है कि आज के काश्तकार की क्या हालत है और वे सरकार से क्या चाहते हैं, क्या राहत चाहते हैं? शायद उनको क्या राहत देनी चाहिये उसको आपने समझा नहीं, हालांकि समझाने का प्रयत्न किया गया और हो सकता है कि समझ पाते भी हुए भी आपने उसको जान बूझ कर एवोइड किया हो। आज के किसान आपसे राहत चाहते है। आप जिस प्रकार की राहत काश्तकार आपसे चाहते हैं उसी प्रकार की राहत उनको दें। आप उनके उत्साह को न घटायें, उनकी ठीक बातों को मान कर उनको उत्साह दिया जावे तो ठीक होगा। इसके साथ साथ पशुपालन भी किसानों के खास धन्धे हैं। खेती के अलावा उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है, इसलिये यह पशुपालन उनको प्रेक्टिकल नहीं हो सकता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि पशुपालन पर भी सरकार को अधिक ध्यान देना चाहिये। मैंने सरकार से निवेदन किया था कि पाली जिले में पशु मेला होना चाहिये मगर सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आशा है इस पंचवर्षीय योजना में शामिल कर दिया जावेगा।

[श्री भैरूंसिंह (बरकाना)]

अब मैं थोड़ा बहुत दवाइयों और स्वास्थ्य के सम्बन्ध में निवेदन करूंगा।

आज हमें गांवों में अमूमन यह शिकायत मिलती है कि यह बीमारी हो गई और यह हो गया। दर असल बात यह है कि सरकार पैसे खर्च करती है मगर पैसे खर्च करने पर भी दवाइयें लोगों को सुचारू रूप से नहीं मिलती हैं। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि थोड़े से सचेत होकर कार्य करें तो इस प्रकार की शिकायत की आवश्यकता नहीं पड़े। और बड़ी बड़ी मोटरें दौड़ाने की आवश्यकता नहीं पडे। बड़ी बड़ी मोटरें दौड़ा कर हजारों रुपया खर्च किया जाता है और इसका नतीजा कुछ नहीं होता है। सरकार ऐसा प्रयत्न करे जिससे बीमारियां न होवें और न उनकी व्यवस्था करना पड़े। अतः औषधियों पर खर्च करने के बजाय पूर्व सावधानी पर विशेष ध्यान दे।

अंत में मैं आपके सामने यह कहूंगा कि जगह जगह आपने पंचायतें कायम कर दी हैं। मगर पंचायतों के लिये कई जगह किसी बात की असुविधा है तो कहीं किसी बात की। कई जगह पंचायतों के लिये मकान नहीं हैं। अगर छोटी छोटी पंचायतों के मकान बना दिये जावें इस योजना में, तो उनकी तकलीफ मिट सकती हैं।

श्री भैरूंसिंह—मैं आपको बी कीपिंग (bee Keeping) के सम्बन्ध में भी निवेदन करना चाहूंगा। बी कीपिंग के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। यह एक कोटेज इन्डस्ट्री है और जब सरकार कोटेज इन्डस्ट्रीज़ को सफल बनाना चाहती है तो मैं आशा करता हूं कि सरकार 'बी कीपिंग' के लिए कोई न कोई प्रयत्न करेगी।

(श्री नाथूसिंह बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष—इनको पूरा कर लेने दीजिये।

श्री भैरूंसिंह (बरकाना)—पूरा कर लिया।

श्री नाथूसिंह—अध्यक्ष महोदय, पहली पंचवर्षीय योजना में कुछ नहीं हुआ, रेगिस्तान के इलाकों के लिए कुछ नहीं हुआ। इस योजना में तो इस इलाके को अच्छी तरह से देखा भाला जाय। न तो डाक्टर है, दुनिया मर रही है, वहां कुछ व्यवस्था नहीं है। मवेशी के लिए तो कोई सुधार नहीं हैं। पानी पीने के लिए कुएं कतई नहीं हैं, न ही सड़कों का बन्दोबस्त है। सरकार को चाहिए कि इस रेगिस्तानी इलाके की, जो पाकिस्तान की सरहद पर है, और ध्यान दे। ध्यान सरकार को जरूर रखना चाहिए।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—माननीय अध्यक्ष

श्री अध्यक्ष— If we are prepared to sit for longer period today and conclude the debate we sit, otherwise we adjourn.

श्री खेतसिंह— Let us sit.

श्री अध्यक्ष—अगर अभी बैठ कर सारा वादविवाद समाप्त करते हैं, मुख्य मंत्रीजी जो कुछ कहते हैं उनको सुनने के लिए तैयार हों तो मैं समझता हूं, दो बजे तक बैठना पड़ेगा।

("शाम को मीट किया जाय" ऐसी आवाज)

श्री मथुरादास माथुर—शाम को आना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष—४ बजे सायंकाल के लिए इस सदन को स्थगित करता हूं।

(तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही आज सायंकाल चार बजे तक के लिए, १२. ४५ बजे मध्यान्ह पर स्थगित हुई।

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक १५ अक्टूबर, १९५५।

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

राजस्थान विधान सभा

१६ वीं बैठक, शनिवार, दिनांक–१५ अक्टूबर, सन् १६५५ ई०

(सयंकालीन बैठक)

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में ४–२० बजे सायं प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तम लाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सुझावों पर वाद-विवाद

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—माननीय अध्यक्ष, अभी जो सदन के सामने द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर बहस हो रही है उसी के सम्बन्ध में मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं।

यह जो योजना हमारे सामने पेश हुई यह कोई नई योजना नहीं है। हमारे सामने इसी प्रकार की पहली पंचवर्षीय योजना आई थी उसका हमें काफी अनुभव है। पहली पंचवर्षीय योजना के मुतल्लिक मैं इतना ही अर्ज करना चाहूंगा कि इस योजना के अन्तर्गत कोई काम जोधपुर डिवीजन में नहीं हुआ। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो आंकड़े बड़े बड़े नजर आते हैं इसमें बहुत वजनदार चीज हरेक विभाग के लिए रखी गई है। लेकिन इसमें थोड़ी शंका मुझे यह होती है कि यह कहां तक पूरी हो सकेगी, किस तरह होगी? इसी प्रकार की शंका विरोधी दल के नेता ने भी की है।

इस पंचवर्षीय योजना को पूरा करने का श्रेय है तो वह निर्माण विभाग पर है। उस निर्माण विभाग के लिए यह शंका प्रगट की गई कि इसमें दक्ष आदमी नहीं, होशियार इन्जीनियर नहीं जिसके जरिये इतनी बड़ी बड़ी योजनायें पूरी कर सकें। उनका खयाल है कि ये अधूरी रह जायेंगी। यह विरोधी दल के नेता के विचार थे। मेरे विचार इससे भिन्न हैं क्योंकि मैं थोड़ा बहुत सम्पर्क निर्माण विभाग से रखता हूं मैं यह समझता हूं कि यहां के इन्जीनियर कैसे दक्ष और होशियार हैं। ये हो वे इन्जीनियर हैं जिन्होंने राजाओं के जमाने में कार्य किया। बीकानेर, जयपुर, जोधपुर के समय जो इन्जीनियर थे वे ही आज निर्माण विभाग में काम कर रहे हैं। अभी कुछ नये भी आये हैं। यह साफ मालूम होता है कि राजाओं के वक्त में जो इन्जीनियर थे उस वक्त जो काम उन्होंने किया उससे उनको हल्का नहीं कहा जा सकता। उन्होंने राजाओं के वक्त में बड़े बड़े काम किये। जोधपुर का छीतर पेलेस इन्हीं इन्जीनियरों द्वारा बनाया गया है जो आजकल उम्मेद भवन के नाम से मशहूर है। महात्मा गांधी अस्पताल, विन्डम होस्पीटल आदि इन्हीं इन्जीनियरों द्वारा बनाये गये हैं। जयपुर के अन्दर भी आज से दस वर्ष पहले काफी बिल्डिंग आदि के

[श्री संतोषसिंह कछवाहा]

काम होते थे। पहले राजाओं में यह होड़ चलती थी कि कौन अपने राज्य में बड़ी से बड़ी बिल्डिंग बनाता है। ऐसी हालत में राजाओं के पास अच्छे से अच्छे इन्जीनियर्स आते थे। विरोधी दल के नेता ने जो शंका की है कि वे दक्ष नहीं हैं, इसलिए मुझे इतना कहना पड़ा। इन लोगों के लिए पंचवर्षीय योजना के अन्दर काम करना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। जोधपुर के इन्जीनियर पाली से हेमावास तक नहर तीन चार महीने में ही ले आये, इस प्रकार बांध भी बांध दिया गया। जहां तक मैं समझता हूं ये इन्जीनियर्स हमारे बहुत योग्य हैं। लेकिन इसके साथ साथ मुझे फिर शंका पैदा होती है, कि जैसे विरोधी दल के नेता को शंका थी, वैसे कहीं यह पंचवर्षीय योजना भी ठप्प न हो जावे। इसका कारण यह है कि अभी कुछ ही महीने पहले का जिक्र है कि कुछ इन्जीनियरों को ससपेन्ड कर दिया। किसी ने इस बात पर विचार नहीं किया कि कितनी पुरानी बिल्डिंग थी, एक छः वर्ष पुरानी बिल्डिंग का पलस्तर उखड़ने लग गया, इसके अन्दर एक ठेकेदार को भी ब्लैक लिस्ट में कर दिया गया। इस सम्बन्ध में यह जरूरी था कि सोच, समझ कर कुछ कार्य किया जाय किन्तु ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जो कुछ भी उसका नुकसान राजस्थान गवर्नमेन्ट को ही भुगतना पड़ा।

श्री अध्यक्ष—यह पंचवर्षीय योजना पर बोल रहे हैं क्या ?

श्री सन्तोषसिंह—यह पंचवर्षीय योजना की भूमिका है। पंचवर्षीय योजना किस तरह से पूरी नहीं होगी, इस पर मैं बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—आप तो दो मिनट लेने वाले थे ?

श्री सन्तोषसिंह—दो मिनट लेने वाले तो चले गये. अध्यक्ष महोदय। मुझको बुखार था फिर भी मुझे अर्ज करना था इसलिये मैं यहां आया।

तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मुझे शंका है कि जिस पंचवर्षीय योजना में करोड़ों रुपया रखा गया है राजस्थान के निर्माण के लिए, जिसे पिछले दस वर्षों में राजाओं ने अपनी स्टेटों की काया पलट कर दी उसी प्रकार आज कांग्रेसी सरकार भी हिन्दुस्तान की काया पलट कर रही है। जोधपुर जो ऊबड़-खाबड़ पड़ा था आज वहां स्टेडियम बना दिया गया। स्टेडियम सिनेमा है, पब्लिक पार्क आदि सुन्दर सुन्दर जगह हैं, जहां सूर पड़े रहते थे वहां पब्लिक पार्क बना दिया गया। मुझे इस बात की शंका है कि इतने बड़े आंकड़े किस प्रकार पूरे होंगे ? विरोधी दल के नेता ने जो कहा है कि इन्जीनियर दक्ष नहीं हैं, अध्यक्ष महोदय, वास्तव में जिन्होंने पिछले राजाओं के वक्त में काम किया वे तो दक्ष हैं और मेरा विचार है वे काम भी पूरा कर सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय, आज की सरकार थोड़ी थोड़ी शंका पर बड़े बड़े काम कर बैठती है। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, उसी तरह से इस योजना में भी किया गया तो जो निर्माण हम करने जा रहे हैं वह नहीं हो सकेगा, ऐसी मुझे शंका है।

[श्री सन्तोषसिंह कछवाहा]

अब मैं शिक्षा के मुतल्लिक कुछ कहूंगा। शिक्षा के लिए हमारी सरकार काफी रुपया खर्च कर रही है। इस पंचवर्षीय योजना में करीब दस करोड़ रुपया रखा गया है लेकिन शिक्षा के मुतल्लिक डिटेल्स इसमें नहीं दिये हुए हैं। इसमें लड़कियों की शिक्षा के लिए कितना खर्च होगा यह नहीं बताया गया है। जहां तक मैं देख पाया हूं शहरों में इसका ७५ प्रतिशत खर्च होगा। इससे पता चलता है कि हमारी सरकार लड़कियों की शिक्षा के लिए तवज्जुह नहीं देती। बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां प्राइमरी स्कूल्स खोलने की आवश्यकता है।

श्री हरिराम—सरकार तो समझ पाई है किन्तु, आप नहीं समझ पाये।

श्री सन्तोषसिंह—(अपना भाषण जारी रखते हुए) शिक्षा के लिए सरकार ने काफी अच्छा रुपया अलोट किया है। इसके लिए मुझे इतना ही कहना है कि कन्याओं के लिए कुछ नहीं किया। बड़े बड़े शहर जैसे जोधपुर में पांच-सात प्राइमरी स्कूलें होंगी। जोधपुर में दो मिडिल स्कूलें हैं, एक इन्टरमीजियेट कॉलेज है जिसको अभी बड़ी मुश्किल से फुल फ्लेज्ड के आर्डर करवाये गये। वहां लड़कियों के बैठने के लिए फरनीचर नहीं है। अध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन भी ऐसा था आलमारियों की सेल्स में लड़कियां बैठकर पढ़ती हैं। यह जो दस करोड़ रुपया रखा गया है उसमें से लड़कियों की शिक्षा पर कितना खर्च होगा यह मैं नहीं समझ पाया।

दूसरा हमारे यहां पर महाराज कुमार कॉलेज और जसवन्त कॉलेज दो, कॉलेज हैं। इनकी बोर्डिंग के लिए दो मकान तो किराये पर हैं और एक बोडिंग हाउस बना हुआ है, जिसमें एक हजार रुपया माहवार किराया लगता है। अतः इनके लिए एक बोर्डिंग हाउस और बना दिया जाय तो बहुत सुविधा हो सकती है और सरकार का रुपया भी बच सकता है। इसी तरह जसवन्त कॉलेज के लिए एक बोर्डिंग तो बना हुआ है, तीन मकान किराये पर ले रखे हैं जिसका ६७५ रुपया किराया लगता है। इसमें १८५ लड़के हैं...

श्री मथुरादास माथुर—आप बजट या राजप्रमुख के भाषण के समय बोलना।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—और जो हमारी सरकार ने हमारे यहां मल्टी पर्पज़ स्कूल्स खोले हैं इस पंचवर्षीय योजना के मुताल्लिक, वहां पर भी सामान की व्यवस्था नहीं है और न आगे दिखाई देता है कि कोई व्यवस्था हो जायगी।

[श्री सन्तोषसिंह कछवाहा]

और इसके बाद इसी में बताया है कि सिंचाई की योजना के मुताल्लिक बहुत काफी कारण हैं। सिंचाई के लिए, माननीय अध्यक्ष, जोधपुर में नेचुरल सोर्सेज़ बालोतरा के अन्दर तीन जगह हैं। अगर उनको सरकार उसके अन्दर ले लेती है और एक ही जगह पम्प लगा दे तो एक बड़े बन्ध जैसी बहुत अच्छी सिंचाई की योजना उसमें हो सकती है। यह उसमें है या नहीं, मुझे मालूम नहीं।

और पशु-पालन के लिए भी जो सरकार ने भेड़ बकरियों पर १५० हजार रुपये और गायों के लिए ६६ हजार रुपये रखे हैं तो गायों से तो बकरियां ही अच्छी रहीं। लेकिन इतने आंकड़े देते हुए भी हम देखते हैं कि भेड़ों की चराई के लिए कोई व्यवस्था नहीं रखी है। इसके मुताल्लिक सवाल असेम्बली में आये हैं। फिर पशुपालन किस तरह से होगा? चरागाह का हिसाब ही नहीं है। आपने बड़ी बड़ी बातें दे रखी हैं इस पंचवर्षीय योजना में, वे कहां तक चलेंगी, कुछ समझ में नहीं आता।

(करतल-ध्वनि)

श्री **मथुरादास माथुर**---माननीय अध्यक्ष, द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर सदन में दो दिन से विचार हो रहा है और सदन के कई प्रमुख सदस्यों ने इस पर प्रकाश डाला है।

सबसे पहले मैं राजस्थान सरकार और उन सब अधिकारी वर्ग को जिन्होंने इस योजना को बनाने में हिस्सा लिया है उनको मेरी तरफ से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने प्रयत्न करके एक बहुत सफल योजना बनाई है। सफलता इस मायने में कि जो प्रथम योजना हमारे सामने पेश हुई उसको हमने देखा; उसके मुकाबले में जो द्वितीय योजना है वह काफी बड़ी चढ़ी है, काफी अच्छी है, और इसका आधार समझना चाहिये इससे कि ऐसी ही हिन्दुस्तान के दूसरे और प्रान्तों में जो योजनायें बनी हैं उनके मुकाबले में हमारी योजना जो राजस्थान में बनी है वह काफी ठीक है और तीसरी सफलता इस मायने में कि प्लानिंग कमीशन से हमारी सरकार के अधिकारियों और राजस्थान सरकार ने कोशिश करके १ करोड़ २१ लाख रुपया हासिल किया है। इन सब बातों को देखते हुए वे हमारे धन्यवाद के पात्र हैं।

मैं माननीय अध्यक्ष, इस योजना पर प्रकाश डालते हुए दो-तीन बातें अर्ज कर देना चाहता हूँ। आज इस योजना को अमल में लाने के लिए सार्वजनिक प्रयत्न की जरूरत है। हम सब सरकारी वर्ग और गैर सरकारी वर्ग का इस योजना को सफल बनाने में, दोनों का सहयोग अत्यन्त आवश्यक रहेगा। फर्स्ट प्लान हमारे सामने गुजरी है, प्रथम योजना जिसको कि हमने देखा, और उसके अमल को भी देखा। मैं एक सुझाव राजस्थान सरकार को देना चाहता हूँ कि प्रथम योजना में जिन जिन चीजों में रुपया लेप्स हुआ, जिस योजना को अमल में लाने की कामयाबी नहीं

[श्री मथुरादास माथुर]

मिली और वह वापिस चला गया उसकी जांच के लिए एक बहुत ऊंचे अफसरों का, अगर हो सके तो उसमें इस सदन के सदस्यों का भी योग लिया जाय, एक कमीशन बनाया जाना चाहिये क्योंकि मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ और सदन के और साथी भी जानते हैं कि हमारे यहां कई सीगों का एलोटेड रुपया लेप्स हुआ है। इस तरह से जो रुपया लेप्स हुआ है उनके क्या वजुहात हैं, क्या कारण हैं? और उन कारणों को रोकने के लिए कि दुबारा द्वितीय योजना में इस तरह के कारण दुबारा नहीं हों, उसकी ओर हमें कदम उठाना चाहिये........

श्री संतोषसिंह कछवाहा—एक कारण मैंने बताया भी है।

श्री मथुरादास माथुर—वह समझ में नहीं आया।

मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि बड़े बड़े मुद्दों के कारण हो सकते हैं। किसी सरकारी अफसर की अफलता के और कई कारण हो सकते हैं। उसकी जांच करनी चाहिए। यह कहना बहुत आसान है, और इस सदन में और बहुत से मेरे साथियों ने कहा भी है कि जब तक ब्युरोकेसी जिन्दा रहेगी ब्युरोक्रेट तरीके से काम होगा, हमारी योजनायें सफल नहीं हो सकती हैं। मैं इस राय से इत्तिफाक नहीं रखता। इस देश में हमें प्रजातन्त्र चलाना है तो ब्युरोक्रेसी के जरिये ही प्रजातन्त्र में सारे काम होते हैं। ब्युरोक्रेसी से पूरा कसकर काम कराना चाहिए। यह नामुमकिन नहीं है कि ब्युरोक्रेसी में सब बुरे नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमें इस बात के लिए जांच करने की आवश्यकता है, इस बात की जांच करनी होगी कि जिन महकमों में बहुत बड़ी तादाद में रुपया लेप्स हुआ है, १० परसेन्ट, ५ परसेन्ट या २० परसेन्ट को बरदाश्त किया जा सकता है, लेकिन जहां काफी तादाद में लेप्स हुआ है उनकी जांच करें कि क्या वजह हुई? सरकारी अफसरों की इन्कम्पीटेन्स से लेप्स हुआ है, उसका नेक इरादा नहीं था जिससे लेप्स हुआ है, क्योंकि एक चीज मानकर चलना पड़ता है और हम और हमारी सरकारी वर्ग और राजस्थान के रहने वाले नागरिक एक सामन्ती युग में गुजरे हैं। उस सामन्ती युग के गुजरने के बाद प्लानिंग को अमल में लाने के लिए एक दिमागी वातावरण होना चाहिए हमारे देश में और खास तौर से वह राजस्थान में नहीं बन पाया है। दूसरी योजना सोशलिस्टिक पेटर्न को आधार भूत मानकर बनाई गई है जिससे बेकारी नहीं हो, ज्यादा से ज्यादा आदमी इसके अन्दर उद्योग धन्धों में लगें, काम में लगें। शिक्षा का प्रचार हो। देश के अन्दर एक ऐसी स्टेट बनाना है जिसको सोशलिस्टिक पेटर्न कह सकते हैं। जब तक हम उस सोशलिस्टिक पेटर्न को अमल में लाने के लिए जो अधिकारी वर्ग हैं उनके दिमाग में सोशलिस्टिक पेटर्न की श्रद्धा नहीं होगी तो वे सही तरीके से उसको अमल में नहीं ला सकते। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हमारे सरकारी अधिकारियों की इस भावना को रखा जाय। हमारे बड़े बड़े अधिकारियों से लेकर छोटे छोटे अधिकारियों तक, क्योंकि यह योजना ऊपर से जाकर तहसील लेवल पर अमल में आती है, तो उनके लिए इस तरह का वातावरण जरूरी है इसलिए मेरा यह सुझाव है कि इस तरह का एक कमीशन एन्क्वायरी करे, उसकी साइकोलाजी की

[श्री मथुरादास माथुर]

इन्क्वायरी करे और उसके बोटम में जाकर रिपोर्ट गवर्नमेंट के सामने पेश हो, और उसके रिपोर्ट के आधार पर जो कमियां रहें उन्हें विश्वास के साथ और हिम्मत के साथ दूर करके आगे बढ़ें तो यह योजना पूरी कामयाब हो जायगी, वर्ना मुझे खतरा है कि इस तरह से १२१ लाख रुपया हासिल किया गया है उसके लिये पूरा ध्यान नहीं दिया गया तो फिर ऐसा नहीं हो कि हमारे साथी जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय में इस सदन में आयेंगे,मुमकिन हो जो आज मौजूद है उनमें से भी कई होंगे; उनको यह कहने का मौका नहीं मिले कि १२१ करोड़ रुपया मिला था उसमें से ५० करोड रुपया वापस जा रहा है, बीस करोड रुपया वापस ज़ा रहा है, १० करोड़ रुपया वापस जा रहा है। इस तरह की शिकायत नहीं होनी चाहिए। इसलिए इसका सुझाव मैंने रखा है।

दूसरा सुझाव मैं जो रखना चाहता हूँ वह यह है कि यदि हमारे यहां पर इस योजना को अमल में लाना है तो इस बात को देखना है कि प्लानिंग डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की कोई स्कीम या प्रोपोज़ल फाइनेन्शल में जाकर ठप्प हो जाती है, फाइनेन्स के अधिकारियों को मैं ओलम्भा देना नहीं चाहता क्योंकि फाइनेन्शल इन्टीग्रेशन के रूल्स बने हैं, जो ऑडिट और फाइनेन्स के सिद्धान्त हैं उन पर जो रूल्स बनाये गये हैं उनमें से बहुत से जब सामन्तवाद इस देश में था, जब कि साम्राज्यवाद इस देश में था उस वक्त वे रूल्स बनाये गये थे। उस आधार पर सोश्यलिस्टिक पेटर्न के सिद्धान्त को सामने रखते हुए द्वितीय पंचवर्षीय योजना को फलीभूत करना है, तो उससे काम रुक जाता है।

जो पुराने अधिकारी फाइनेन्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उन आदमियों को बराबर कई साल वहां पर काम करते हुए हो गए, इसलिए उनके लिए एक ढांचा घर कर गया है जिससे बाहर वे नहीं निकल सकते। रफ्तार के साथ बाहर नहीं निकल सकने के कारण फाइनेन्स डिपार्टमेंट में जाकर अच्छी से अच्छी योजना ठप्प हो जाती है या उसमें बहुत देरी हो जाती है. इससे तो उस योजना का मतलब ही खत्म हो जाता है। इस बारे में मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार और भारत सरकार दोनों को फाइनेन्स डिपार्टमेंट में क्रान्तिकारी तब्दीली करनी चाहिए। यदि इस योजना को सही तरीके से आगे बढ़ाना है तो इस तरह का कदम उठाना जरूरी है। यदि यह कदम नहीं उठाया गया तो वही हाल होगा जो नया सवार पुराने घोड़े पर बैठ कर तेजी से नहीं दौड़ा सकता और उसका हाल होता है और खतरा यह है कि जिस उत्साह से यह योजना बनाई गई वह उत्साह आगे नहीं रह सकेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपने फाइनेन्स डिपार्टमेंट को सुधारें।

जहां तक गैर सरकारी एजेन्सी का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि प्रथम योजना में भी गैर सरकारी एजेंसीज़ ने काफी योग दिया है। जितने कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स हैं हिन्दुस्तान भर में उनके लिये श्रमदान फोर्टनाइट मनाई गई थी जिसमें राजस्थान का ४० लाख रु. का श्रमदान था और वह दूसरे स्टेट्स

[श्री मथुरादास मथुर]

के मुकाबले में बहुत आगे बढ़ा। इस बात की हमें तसल्ली है कि राजस्थान के लोग मजदूरी और श्रमदान चाहते हैं। यहां के किसानों को समय है और वे श्रम दे सकते हैं। हमें इस बात की भी खुशी है कि सरकारी लोगों ने भी राजस्थान की जनता के साथ सहयोग दिया है, खास करके प्रोजेक्ट्स एरियाज़ में। यदि यही बात और इलाकों में भी रखी जाय तो मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि पूरा सहयोग मिल सकता है। १२१ करोड़ की द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाई गई है वह जनता की भलाई के लिए बनाई गई है और उसे पूरा करने के लिए जनता का पूरा सहयोग मिल सकता है इसका हमें पूरा विश्वास है।

अब अर्ज करना चाहता हूं, जो चर्चायें सदन में हुई इधर उधर की। कहीं कुछ आरोप भी लगाये गए। उस समय यह मालूम नहीं था कि हम इस योजना को घटा-बढ़ा भी सकते हैं या नहीं। कुछ ऐसी बातें भी कही गई जो क्षेत्रीय भावना को लेकर कही गई थीं। उस समय आपकी अदम मौजूदगी में चेयरमेन साहब पदासीन थे उन्होंने उनको रोका भी। इस योजना को ठीक बनाने के लिए इस वक्त किसी को शिकायत नहीं हो सकती कि मेरे डिस्ट्रिक्ट के बारे में गौर नहीं हुआ। इस योजना के अन्तर्गत काम करने के लिये मोटे रूप से आधार नियत किये गए हैं, उन्हीं के अनुसार यह योजना बनाई गई; जैसे इसमें एक बात यह तय की गई है कि जिस गांव या कस्बे की आबादी साढ़े सात हजार या ऊपर होगी वहां बिजली लगाई जावेगी। हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे गांव मौजूद हैं। यह हो सकता है कि किसी डिस्ट्रिक्ट में इतनी आबादी वाले ३ गांव हैं तो किसी में ७, ६ या १० गांव हैं। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में साढ़े सात हजार की आबादी वाले गांव भिन्न भिन्न संख्या में हैं तो एक डिस्ट्रिक्ट वाले कहें कि फलां डिस्ट्रिक्ट में १० कस्बों में बिजली लगेगी और हमारी डिस्ट्रिक्ट में ३ गांवों में ही लगेगी, यह नहीं होना चाहिए लेकिन जब हमने एक आधार तय कर लिया तो काम उसी आधार के अनुसार होगा। यदि हमें ज्यादा पैसा मिलता हो तो हो सकता था कि हम ५ हजार की आबादी वाले हर गांव में बिजली लगाते और यदि इससे भी कम पैसा मिलता तो साढ़े सात हजार के बजाय १० हजार की आबादी वाले कस्बों में ही बिजली लगवाते। तो फिर यह समझ में नहीं आता कि यह कैसे कहा जाता है कि फलां डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला एक मिनिस्टर है और फलां डिस्ट्रिक्ट का चीफ व्हिप है इसलिए उस डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा जगह बिजली लगेगी और हमारे यहां कम जगह लगेगी। इस योजना में यह तय किया गया है कि ५०,००० की आबादी वाले टाउन्स में ड्रेनेज़ सिस्टम कायम करेंगे। उस डिस्ट्रिक्ट में इतनी आबादी वाले जितने भी टाउन्स होंगे उनमें ड्रेनेज़ सिस्टम होगा। यदि आपकी डिस्ट्रिक्ट में इतनी आबादी वाला कोई भी कस्बा नहीं है तो मजबूरी है। आप अपने कस्बों की आबादी बढ़ाइये, आपके यहां भी ड्रेनेज़ सिस्टम शुरू होगा। इसी तरह यह फैसला हुआ है कि ५०० की आबादी वाले हर गांव में एक स्कूल होगा, यदि गांव वाले स्कूल की बिल्डिंग के लिये कच्चा या पक्का मकान देने को तैयार होंगे। स्कूलों के लिए यह सिद्धान्त मंजूर हुआ। आपकी डिस्ट्रिक्ट में ५०० या उससे ऊपर की आबादी वाले ५० गांव हो सकते हैं और मेरी डिस्ट्रिक्ट में इतनी आबादी वाले ४० गांव

[श्री मथुरादास माथुर]

हो हो सकते हैं तो आपको ५० स्कूलें मिल गईं और मुझे ४० ही मिलीं। इस सिद्धान्त से योजना बनाई गई है कि इतनी उम्र वाले लड़के स्कूल में आने चाहिये और इतनी उम्र वाली लड़कियों को स्कूल में आना चाहिये उनको मुफ्त शिक्षा दी जायगी। इन मोटे सिद्धान्तों को लेकर वह योजना बनाई गई है।

सड़कों के बारे में भी यही चीज है कि ५००० की आबादी वाला कोई भी गांव या कस्बा सड़क से जोड़ा जायगा। कोई भी पुलिस स्टेशन या कोई भी तहसील हेड क्वार्टर सड़क से जोड़ा जायगा, आपके यहां कोटे में १० तहसीलें हैं और मेरे यहां नागौर में ६ तहसीलें हैं तो आपके यहां के १० स्थान सड़कों से जोड़े जायेंगे जबकि मेरे यहां के ६ स्थान ही सड़कों से जोड़े जायेंगे। सिद्धान्त यह है कि ५०,००० की आबादी के पीछे हर तहसील में पुलिस स्टेशन खोले जांय। फिर शिकायत किस बात की है? यह हो सकता है कि किसी जगह ज्यादा बनें, किसी जगह कम बनें। एक बात और लीजिये यह प्रश्न है कि बांध किस जगह बनें? जहां नदियां हैं वहीं बांध बनें लेकिन जहां पानी की नदियां ही नहीं हैं वहां बांध कैसे बन सकते हैं। उदयपुर, कोटा, सवाई माधोपुर में बांध बन सकते हैं लेकिन हमारे इलाके में रेगिस्तान में बांध नहीं बन सकते। हमारे साथी जो जोधपुर से आये हैं उन्होंने शिकायत करदी कि हमारे यहां बांध नहीं बनाये। हमारे यहां तो बंध ही बंध हैं वहां बांधों का क्या सवाल है? आज सदन में जो एक तरह का वातावरण बन गया उसको साफ करने की जरूरत थी इसलिये मैंने इतना अर्ज किया। इसमें यह कहीं गुंजायश नहीं रखी गई है कि कस्बों और डिस्ट्रिक्ट्स की शिकायत आवे कि मेरी तहसील में कुछ नहीं हुआ। नावा में तहसील है, सड़क है, अस्पताल खुला है, वहां पर पंचायत घर है और वहां पर अन्य जरूरी बातें भी हो सकती हैं। योजना जो बनाई गई है काफी सोच-विचार कर बनाई गई है। डिस्ट्रिक्ट्स की जरूरतों के बारे में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेन्ट कमेटीज़ ने अपने सुझाव भेजे हैं। आप लोगों ने उन कमेटीज़ में कितना काम किया, कितना नहीं किया यह तो मुझे पता नहीं लेकिन मैं अपनी बात जानता हूँ कि कई दिनों तक, रोजाना कई घंटों तक बैठकर हमने अपनी योजना बनाई थी, वहां से फिर सारी योजनाएं सरकार के पास आती हैं, सरकार उनकी स्क्रूटिनी करती है और फिर भारत सरकार के पास भेजी गई है। जिन एम. एल. एज़ ने और जिला कांग्रेस कमेटीज़ के सदस्यों ने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेन्ट कमेटीज़ में भाग लिया है उन सबको मालूम है कि योजना किस तरह से बनी है। आप उसमें हिस्सा नहीं लें, आप जावें नहीं और फिर इस तरह की चर्चा करें, यह अच्छा नहीं है। कई माननीय सदस्यों ने इधर उधर की बातें कहीं। यह देश की उन्नति का सवाल है, इसमें सबको सहयोग देना चाहिये।

इसके अलावा मैं एक चीज का और जिक्र करना चाहता हूँ। एक माननीय सदस्य ने कहा कि राजा महाराजाओं के जमाने में किस तरह से तरक्की हुआ करती थी, यह जोधपुर जाकर देखें। मैं भी उसी शहर का रहने वाला हूं जिस जगह से वे आये हैं। उस समय वहां की क्या

[श्री मथुरादास माथुर]

परिस्थिति थी। वहां का ३ करोड़ का बजट था जिसमें से डेढ़ करोड़ रुपया शहर पर ही खर्च होता था। वहां पर कितने अस्पताल थे, सन् ४८ तक किसी भी कस्बे में हाई स्कूल नहीं थी, सिर्फ जोधपुर शहर में कुछ हाई स्कूल्स थी। आज बीबोडी देने वालों की यह मांग है कि हम जो देते हैं वह शहरों में ही खर्च नहीं हो सकता, दूसरों का भी हक है उनको भी हक देना होगा। हमारे ठेकेदार साहब पुराने स्वप्न देख रहे हैं वह नहीं होगा। समाज का ढांचा अब बदल गया है। आप के घर घी के चिराग हों, सिनेमा हों, रेडियो हों, लाइट हो; आपके शहर में डंबर की सड़कें बनें।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—गांवों में नहीं करने के कारण ही मैंने शिकायत की है।

श्री मथुरादास माथुर—(जारी) आपकी सभी तरह को शिकायत है। तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि आज पहली पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ होने के बाद जितने रुपये खर्च हुए हैं और उनसे आपके यहां कितने हाईस्कूल्स खुले हैं, कितने कॉलेजेज़ और स्कूलें खुली हैं, कितने पंचायत घर बने हैं, कितने अस्पताल बढ़े हैं; इसका अन्दाजा आपको लगाना चाहिये। आपने यदि इस योजना को ईमानदारी के साथ पढ़ा हो तो आप सदन में यह बात नहीं कह सकते।

एक बात मैं भी कहना चाहता हूं जो नहीं हुई है, मुझे पूरा संतोष उस पर नहीं हुआ है। जब हमको संतोष हो जायगा तो क्रान्ति रुक जायगी। जो योजना बनाई गई है वह बड़े बड़े मदों को लेकर बनाई गई है, सारी रकम का वैज्ञानिक तरीके से वितरण किया गया है। यह किसी एक दो एम. एल. ए. ने नहीं बनाई है। खास खास सिद्धान्तों के आधार पर बनाई गई है। उसको आप गौर से देखें और समझने की कोशिश करें फिर आप उसी नतीजे पर पहुंचेंगे जिस पर मैं पहुंचा हूं।

अब मैं दो तीन चीजों का जिक्र करना चाहता हूं जो इसमें नहीं है। अधिकारियों को ज्ञात है, आबू हमारा हिल स्टेशन था, हमारे यहां से चला गया था, अब फिर वह हमारा होने वाला है या हो चुका है। आबू हमारे यहां का एकमात्र हिल स्टेशन है, उसको बढ़ाने के लिये हमने कुछ नहीं रखा है। इसके साथ साथ मैं एक चीज अपने स्वार्थ की कहूंगा अपने डिस्ट्रिक्ट की। जब दूसरी जगह नहरें आ रही हैं जैसे हमारे पड़ौसी प्रदेश बीकानेर, जैसलमेर वगैरह में नहरें आयेंगी, उधर कोटा में और जयपुर में नहरें आ जायेंगी, लेकिन हम रेगिस्तान के रहने वाले लोग नहरों से महरूम रह जायेंगे। कुदरत ने शायद हमारी मदद की नहीं। ईश्वर ने प्रकोप नहीं किया होता तो हमारी हालत इस तरह की नहीं होती। अगर ईश्वर ने इस तरह हमारी मदद न की है, कुदरत ने इस तरह का साथ नहीं दिया है तो विज्ञान तो हमारा साथ दे सकता है। अगर इन्जीनियर सोच लें और पक्का इरादा कर लें तो

[श्री मथुरादास माथुर]

नागौर जिले में नहर आ सकती है। हमारे यहां पीने को पानी नहीं है, खारा पानी है। वाटर बोर्ड से कुछ रुपया मिलता है, पर १८ हजार, २० हजार रुपयों में एक कुआ बनता है, ६ हजार रुपये गांव वाले नहीं दे सकते, इसकी ओर भी गौर करें और इसे हल करने की कोशिश करें।

जिस तरह गंगानगर में नहर आने से गंगानगर इलाका ही सरसब्ज नहीं हुआ, हमारे यहां का प्रोडक्शन भी बढ़ा है, और सामाजिक जीवन बढ़ा है; वैसे ही अगर हमारे यहां नहर आ जाय तो हमारे यहां भी प्रोडक्शन और सामाजिक जीवन स्तर बढ़ सकता है। यह नहीं कहें कि आपके यहां का प्लेटो बड़ा ही ऊंचा है इसलिये आपके यहां नहर नहीं आ सकती, आपके यहां बिजली सस्ती नहीं आ सकती। बिजली डेढ़ आना, दो आना यूनिट और १२ आना यूनिट में भी देते हैं, इसका सरकारी अधिकारी ध्यान रखेंगे।

इस चीज को इस प्लान में नहीं रखने में मुझे कोई शिकवा-शिकायत नहीं है, पर मैं चाहता हूं कि इस प्लान में इस पर दिमाग लगे। १०, २०, ५० हजार रुपया लगें और आगे जा कर नागौर-सीकर के इलाके में इस पानी को लाकर डाल दिया जाय, नागौर और सीकर इलाके में नहरें लाई जायं। यहां के मवेशी, इन्सान, पशु खनिज, जमीन सब अच्छे हैं। कुदरत ने मुकाबिला करने के लिये यहां के इन्सानों को ताकत दी है, अगर इस इलाके में पानी आ जाय तो यह क्षेत्र राजस्थान की बहुत बड़ी सेवा कर सकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये राजस्थान सरकार को धन्यवाद देते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री मानसिंह महार —माननीय अध्यक्ष, इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर मैं भी अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ।

यह सारी चीजें तो खतम हो चुकी हैं, जो कुछ भारत सरकार से मिलना था और हमारी राजस्थान सरकार को इस बारे में जो कुछ करना था, वह सब किया जा चुका है, अब इस बारे में ज्यादा कहना तो ठीक उसी तरह है जिस तरह भैंस के आगे बीन बजाना। मैं यही मान कर चलता हूँ।

हमारे मुख्य सचेतक ने जिन लफ्जों में इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना की तारीफ की है, उसके लायक मैं इसे नहीं समझता। मैं यह मानता हूँ कि इस योजना के अन्दर अगर कोई ऐसी बात होती कि जिससे हमें यह महसूस होता कि कांग्रेस के समाजवादी ढांचे के प्रस्ताव को किसी प्रकार से प्रोत्साहन मिलता है तो हम यह कह सकते थे कि यह आइडियल योजना है।

[श्री मानसिंह महार]

मैं मानता हूँ कि इसमें शहरों के लिये काफी कुछ किया गया है जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा कि ५० हजार की आबादी के कस्बों में यह किया जायगा, साढ़े सात हजार से ऊपर की आबादी के कस्बों में यह किया जायगा।

मैं इस योजना में यह सब चीजें न देख कर, यह चाहता था कि ५० से कम आबादी के गावों को यह सहायता देंगे, और ३०० से ऊपर की आबादी वाले गांवों को यह सहायता देंगे। अगर इस योजना में यह होता तो हम इस योजना को एक आइडियल योजना कहते। जयपुर में तो पहले से ही अस्पताल हैं, अगर इस योजना में यह होता कि १०० से कम आबादी के गांवों में जहां किसी तरह के शफाखाने का प्रबन्ध नहीं है वहां मोटर एम्बुलेंस होंगी और वहां से बीमारों को मोटर एम्बुलेंस में यहां लाकर इलाज कराया जायगा और उनके लड़कों को यहां कालेजों में शिक्षा दी जायगी, कृषि कॉलेज में शिक्षा दी जायगी और उन्हें यह शिक्षा दी जायगी कि किस तरह कृषि में उत्थान हो सकता है। यह होता तो मैं मानता कि यह आदर्श योजना है, हमें १२१ करोड़ रुपया मिला है और जब इसमें हमारा श्रमदान जोड़ा जायगा तो काफी होगा, पर इसमें वही शहरीपन टपकता है, हमारी इस योजना बनाने का आधार है वह शहरीपन पर बना हुआ है।

मेरे मित्र ने कहा कि जोधपुर रियासत की ३ करोड की आमदनी में से डेढ़ करोड रुपया जोधपुर पर खर्च होता था, पर मैं तो यह कहता हूँ कि शहरों में जितना काम होना चाहिये उसका प्रोपोरशन यहां ठीक नहीं बैठता। शहरों में टैक्स कम है और टैक्स लगाने की कोशिश नहीं की जाती। पर गांवों में कोई स्कूल खोलेंगे तो हम गरीबों को दबायेंगे कि आधे पैसे दो, इस तरह श्रमदान करो। परन्तु जयपुर शहर में या दूसरे शहरोंमें पैसा लगाया जायगा; गन्दे पानी को साफ करने के लिये नालियां लगाई जायंगी तो यहां की जनता को नहीं कहा जायगा कि आधे पैसे तुम लगाओ। तो मैं यह कहूँगा कि यह शहर वालों के मुकाबिले में गांव वालों के साथ सरासर अन्याय है और कम से कम हम गांवों में बसने वाले कभी नहीं कहेंगे कि इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमारे साथ न्याय हुआ है।

मुझे यह कहना है कि राजस्थान में अगर कोई वाकई यह मान कर चले कि राजस्थान की जनता का सही माने में उत्थान करेंगे तो वह तभी कर सकते हैं जबकि राजस्थान के एग्रीकल्चर विभाग को ऊंचा उठाया जाय। हमारे राजस्थान प्रदेश की उन्नति गांवों के काश्तकारों और किसानों में निहित है, उनके उत्थान के लिये जब तक हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को ठीक नहीं बना देते, इसे इस तरह का नहीं बना देते कि हर किसान तक हमारी नई योजना पहुँचे तब तक माननीय अध्यक्ष, में आपके द्वारा नेता महोदय को बता देना चाहता हूँ कि उनकी यह स्वर्ण योजना थोड़े स्थानों के लिये रह जायगी।

[श्री मानसिंह महार]

एग्रीकल्चर महकमा आज नहीं के बराबर है, इससे गांवों में कोई फायदा नहीं हो रहा है, यह महकमा जो है वह बिल्कुल बेकार महकमा है, इसमें जो कुछ पैसे खर्च किये जा रहे हैं वह शीयर वेस्ट ऑफ मनी है और अगर इसको सही कर देते हैं, १२ करोड़ का ऐसा पैसा रखा है, उनको सही ढंग से खर्च कर देंगे तो मैं यह कह देना चाहता हूँ कि योजना के कुल १२१ करोड़ रुपयों से उतने प्रोपोरशन में लाभ नहीं होगा जितना कि इन १२ करोड़ रुपयों से होगा।

इसके बाद मैं कहना चाहता हूँ, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि पिछली पंचवर्षीय योजना में हमारी प्रगति ढीली रही, पर अब जब कि इतनी भारी रकम मिल रही है तो वह हमें किसी न किसी तरह से सदुपयोग में लानी चाहिये। जो कुछ हो गया है उसमें हेरफेर होने की या करने की बात हमारे बस की नहीं है, लेकिन जो कुछ मिला है उसको सही ढंग से खर्च कर सकें यही हमारा लक्ष्य होना चाहिये।

मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जो कुछ कहा उससे यह महसूस होता है कि कुछ हल्के इस प्रकार के हैं जो नये कार्य किये जाने से करीब करीब महरूम रहते हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि जमुवा रामगढ़ का इलाका और आमेर का इलाका, इसमें जो कुछ डेवलपमेन्ट का काम हुआ है वह नहीं के बराबर है और अगर माननीय मंत्री महोदय जवाब में यह फरमावेंगे कि वहां काम हुआ तो मैं बता देना चाहता हूँ कि यहां काम नहीं हुआ। हम इस पंचवर्षीय योजना में इस लक्ष्य को लेकर चलते हैं कि यह जो कुछ पैसा लगाते हैं वह पैसा प्रत्येक गांव में पहुँचे, प्रत्येक खेत में पहुंचे और हर एक किसान और गांव के रहने वाले यह महसूस करें कि हमारी सरकार ने यह कोई नई चीज कराई है, लेकिन यह थोड़ा बहुत पैसा जो गांवों में खर्च होने के लिये होता है वह भी इस तरह अव्यवस्थित ढंग से खर्च होता है कि कहीं कहीं दो तीन जगह गांवों में काम करा दिया जाता है और जो बेचारे ऐसे गांव होते हैं जिनमें कोई बोलने वाला नहीं, या बोलनेवालों की कमी होती है उनमें कोई काम नहीं होता। डेवलपमेंट बोर्ड की कमेटी में मैंने यह सुझाव दिया था कि जो कुछ कार्य गांवों में किया जावे वह एक जाल बिछा कर करें। हमारा हर एक काम जाल बिछा कर होना चाहिये। लेकिन आपने गांवों में पंचायतें बना दी हैं। वहां पर होस्पिटल बनावें, सड़कें बनावें। हमारा यह लक्ष्य होना चाहिये कि ज्यादा से ज्यादा गांवों में यह रुपया स्प्रेड करके काम कराया जावे। जब तक इस उद्देश्य से पंचवर्षीय योजना नहीं बनाते है तो फिर वह योजना पूरी नहीं हो सकेगी। इसके अलावा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां पर चंबल और भाकरा की बातें हो रही हैं कि जिससे सिंचाई बढ़ेगी। मगर मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारे जमुआ रामगढ़ के इलाके में, जोकि एक कौने में है, वहाँ पर हमारे न भाकरा की नहर आवेगी और न चंबल की नहर आवेगी। इस इलाके के लिये अगर आप थोड़ा बहुत इधर उधर पैसा तालाबों और बांधों के लिये रख देते तो बेचारे किसानों का भला हो सकता था। हमारे ४४ करोड रूपयों में से हमें कोई आशा नहीं है कि इस पर कुछ खर्च किया जावेगा, जो आप लगाने वाले हैं।

जयपुर रियासत के समय से ही हम यह सोचते आ रहे थे कि जयपुर के आस पास के इलाकों में बिजली लगेगी। बिजली को खींच-खांच कर दौसा तक तो ले गये हैं जो मिनिस्टर के रहने का स्थान

[श्री मानसिंह महार]

था। मगर वे अब मिनिस्टर नहीं हैं। चौमू वगैरह का इलाका है, उसको बिलकुल छोड़ दिया गया है। जयपुर से ६ मील तक बिजली गई है और जयपुर से चोमू १८ मील है। अगर वहां पर ले जाई जाती तो लोगों को काफी फायदा होता। मगर वहां नहीं ले जाकर दौसा तक बिजली ले गये हैं। मुझे आशा है कि हमारी सरकार इस योजना के अनुसार हमारी भलाई के लिये चौमू वगैरह जयपुर के आसपास के कस्बों तक बिजली पहुंचायगी जो बहुत अच्छे कस्बे हैं।

इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान में मिनरल रिसोर्सेज़ बहुत हैं जो कम डेवलप्ड हैं। इसके लिये हमारी सरकार ने कुछ भी नहीं रखा है, हमें यह कहा गया था कि यह भारत सरकार के विचाराधीन है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसलमेर में पेट्रोल और दूसरे इलाकों में जिन्क आदि दूसरी चीजों के लिये सर्वे बिल्कुल अधूरी पड़ी हुई है। इसलिये अगर इस काम के लिये भारत सरकार को नहीं लिखा जावेगा तो भारत सरकार दूसरी जगह सर्वे करायगी और यहां पर नहीं करावेगी, इसलिये में यह उचित समझता हूं कि हमें हमारी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहिये ताकि हमारी सरकार भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करे। हमारे यहां मिनरल सेन्टर्स है, वहां पर सड़कों का सही ढंग से प्रबन्ध नहीं है। भारत सरकार को चाहिये कि वहाँ तक सडकें पहुंचाए और इसका जल्दी से ज़ल्दी डेवलपमेंट करे ताकि राजस्थान की जनता को फायदा पहुंचे और भला हो सके।

इसके बाद में मैं कोम्युनिकेशन्स के बारे में कुछ निवेदन करूंगा। जैसा कि हमको हमारे चीफ मिनिस्टर ने फरमाया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में राजस्थान में रेलों का बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं हुआ। अब हमारे यहां दूसरी पंचवर्षीय योजना है और इस दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमें प्रयास करना चाहिये कि हमें दुगुना मिले क्योंकि पहले हमें कुछ नहीं मिला था। अगर इस प्रकार के पोइन्टों को सेन्टर में प्रेस किया जायेगा तो रेलवे में काफी प्रगति होगी। इसके अलावा राजस्थान में सड़कों की हालत बहुत खराब है। सडकें जो नई बन रही हैं वे तो बन रही हैं हीं लेकिन पुरानी सड़कों की ऐसी सोचनीय दशा है कि जगह जगह गड्डे पड़े हुए हैं और किनारे पर कटी हुई हैं। जब कभी हमारे माननीय मंत्री उधर से होकर गुजरते हैं तो कहते हैं कि सड़कें सुधरनी चाहिये, लेकिन यह केवल जब तक ढचके लगते हैं उतनी देर का मामला रहता है। उसके बाद वे भूल जाते हैं। जयपुर से चौमू तक सड़क और वहां से सामोद तक को सडक बहुत खराब है। वहां पर आइरन ओर भी है। वहां से हमेशा स्टेशन तक ५० ट्रक आते हैं। सरकार को इससे सैकडों रुपये की आमदनी है। लेकिन वह नहीं सुधराई जाती है। वह सड़क कई जगह से बुरी तरह कटी हुई है। कहीं कहीं १॥ हाथ का गड्ढा है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि उस सड़क की तरफ ध्यान अवश्य दिया जावे और फौरन सुधराई जावे। दूसरी सड़कों की तरफ ध्यान दिया जावे, लेकिन इसकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।

इसके अलावा इसके अन्दर कुछ श्रम पर जोर दिया गया है। आपके इस जोश के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं और उसकी एक छोटी सी मिसाल माननीय अध्यक्ष, आपके सामने

[श्री मानसिंह महार]

रखूंगा जिससे श्रम के लिये काफी टेम्पो बन गया है, लेकिन कभी कभी सरकार का रुख ऐसा हो जाता है कि ग्रामीणों का यह टेम्पो खत्म हो जाता है।

हमारे सामोद में एक मिडिल स्कूल है उसको सरकार के डिप्टी इन्सपेक्टर ओफ स्कूल ने यह लिख कर दिया कि अगर आप १० हजार रुपये इकट्ठे करोगे तो तुम्हारे यहां हाई स्कूल खुल जावेगा। इसके बाद डिप्टी इन्सपेक्टर ओफ स्कूल ने यह कहा कि ४ हजार रुपया युनिवर्सिटी में जमा करा दीजिये उसके बाद हाई स्कूल खोल दिया जावेगा। चार हजार रुपये इकट्ठे कर लिये जाते हैं, उसके बाद यह जवाब मिलता है कि हम हाई स्कूल नहीं खोल सकते। जब यह जवाब मिलता है तो उनके दिल भर गये, उनकी छातियें भर गईं और वे उनको कहते हैं कि हम गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। अब अगर उनसे कुछ कार्य के लिये कहा जाता है तो वे यह कहते हैं; वे कहते हैं, आप अपने पहले वादों को पूरा कीजिये। आप कम वायदे कीजिये और काम ज्यादा कीजिये, आप दो वायदे कीजिये और चार काम कीजिये, आप चार काम करने के स्थान पर १० वायदे मत कीजिये। इससे गांव में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को बहुत शर्मिन्दा होना पड़ता है।

और ये चन्द शब्द कहते हुए और मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद के साथ उलहाना देते हुए कि यह योजना अगर पहले हमारे सामने रखी जाती तो उसको गांवों के बेसिस पर तैयार करते न कि शहरों पर। आशा है, १२१ करोड़ रुपयों का हमारी सरकार सदुपयोग करेगी।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय अध्यक्ष......

श्री अध्यक्ष—आप (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) कितना समय लेंगे जवाब देने में ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—करीब पौन घंटा। ६। बजे जवाब देना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष—६। बजे जवाब देना चाहेंगे तब तक मैं जानना चाहूंगा कि कितने सदस्य बोलने वाले हैं। लिस्ट बना कर मेरे पास भेज दीजिये।

श्री ईश्वरीसिंह—एक तो मैं बोलूंगा।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए जो प्रयत्न रुपया प्राप्त करने का राजस्थान गवर्नमेन्ट ने किया है सबसे पहले मैं भी अपना यह कर्तव्य समझता हूं कि गवर्नमेन्ट को इसके लिए बधाई दूं। (हियर, हियर)

[श्री गोपीलाल यादव]

इसमें कोई शक नहीं है कि यदि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसी प्रकार इतना रुपया प्राप्त कर लेते जैसा इसमें मिला है तो इस १२१ करोड़ रुपयों से कहीं ज्यादा २०० करोड़ के करीब प्राप्त कर लेते, लेकिन पहली योजना में कम प्राप्त करने के कारण आज हमको बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं हुई है। मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं इस सिलसिले में कि जब प्रथम पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में विचार करने के लिए एक कमेटी यहां पर बुलाई गई थी उस वक्त भी मैंने यह कहा था कि आपके सामने एक रुकावट है कि राजस्थान गवर्नमेन्ट को कुछ रुपया कॉन्ट्रिब्यूट करना पड़ता है और उसके लिए आप अपने को असमर्थ पाकर इतनी थोड़ी योजना बना सके कि यह १७, १८ करोड़ तक पहुँची; आप रुपयों की चिन्ता न करें, बहुत रिसोर्सेज़ है, और अगर उनको टेप किया जाय तो काफी रुपया मिल सकता है। बहुत थोड़ी योजना रखी गवर्नमेंट के सामने, नहीं रखी जा सकती थी, तो नतीजा यह हुआ कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने यह समझा कि राजस्थान सरकार न योजना बना सकी है और न खर्च कर सकती है। जब यह दोनों काम नहीं कर सकी तो ज्यादा रुपया देने का सवाल ही कहां आता है? इसमें कोई शक नहीं कि अब के निहायत जोर के साथ, अच्छी योजना रखी और सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने उसमें ४० करोड़ कम कर दिया। अब भी यह नहीं मान कर चलना चाहिए कि जो कमी हो गई है वह कम हो ही जायगा। जब सतरह करोड़ से १६१ करोड़ तक पहुँच गये हैं तो वह ४० करोड़ भी हमें मिल जायगा।

इस योजना में क्या कमी है इसको, मैं यह समझता हूं कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना और कमी बतलाना एक ऐसी चीज है कि जैसे इस योजना को पढ़ कर ही लोगों को सुना देना है। इसके अन्दर खुद गवर्नमेंट ने माना है कि हरएक चीज़ में कितनी कमी है, हर एक चीज से राजस्थान की हालत कितनी थी, एजुकेशन में, पानी में, और जब पूरी की पूरी हालत सेन्ट्रल गवर्नमेंट को बतलाई गई तो इतना रुपया मिला। इसका दूसरा पहलू यह है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना, या द्वितीय पंचवर्षीय योजना या तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, मैं समझता हूं, कम से कम पांच सात योजनायें तो निश्चित बनानी पड़ेंगी जब तक कि हमारा देश, हमारा प्रान्त, हमारी स्टेट उस हालत पर आ जाय जिस पर हम लाना चाहते हैं। जब तक कि वह अन्तिम योजना बने तब तक निश्चित कमियां होंगी क्योंकि जब कमियां हैं ही तब ही तो उनको पूरा करने के लिए एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी योजनायें बनाई जाती हैं। आज हम यह आशा करें कि चूंकि गवर्नमेंट ने योजना बनाई है उससे तो ४५ फी सदी ही पढ़ सकेंगे सो फी सदी नहीं। मैं समझता हूं यह ठीक है। आज पांच साल में वह काम पूरा नहीं कर सके जो रूस ने तीन साल में किया था। मैं यह बतलाना चाहता हूं कि इस योजना को बनाने वाली जो गवर्नमेंट है उसको क्रिटिसाइज़ करना ल होगी।

[श्री गोपीलाल यादव]

अब सवाल रह गया है कि जो रुपया हमारे पास आया है वह किस ढंग से खर्च किये जांय। कुछ इसमें अच्छी चीजें हैं कि जिनके बारे में कल मुख्य मंत्रीजी ने बतलाया था कि जिनमें तब्दीलियां नहीं हो सकी हैं। कुछ में हो सकती हैं। एक चीज की ओर मुख्य मंत्रीजी का ध्यान खास तौर पर दिलाना चाहता हूं; वह यह है कि राजस्थान के अन्दर एक बहुत बड़ी रकम आप खर्च करने जा रहे हैं लेकिन इस योजना में आपने १५००० कुओं का आयोजन रखा है कि वे बनाए जांय और उन पर तीस लाख की रकम, जो उसमें लिखी हुई है, खर्च की जायगी। मैंने प्रथम पंचवर्षीय योजना के वक्त भी यह चीज बताई थी कि राजस्थान की आबादी १ करोड़ ६० लाख के करीब है जिसका २५ फीसदी हिस्सा यानि ४० लाख शहरों में या कस्बों में रहने वाले समझना चाहिए। तो १ करोड़ २० लाख आबादी ऐसी रही कि जो देहातों में रहती है और पांच आदमियों के एवरेज पर एक फेमिली मानें तो २४ लाख परिवार देहातों में रहते हैं। हमें यह बात ध्यान में रख कर चलना चाहिए कि हर एक योजना में यह योजना रख कर चलें, प्रथम में तो नहीं हो सकती थी, कि चार योजना में उसको यह काम पूरा कर देना है कि हर एक चार परिवारों के बीच में कम से कम एक कुआ जरूर हो। इसके माने यह हैं कि आपको ६ लाख कुए चाहिए। छः लाख कुओं में से मैं यह मानकर चलता हूं कि आधे आधे ऐसे हो सकते हैं कि जो मरम्मत काबिल हों, कुए हों, नहरी इलाका हो या नहरों से कनेक्टेड हों। तीन लाख के करीब कुए आपको बनाने हैं और जिस हिसाब से खर्चा किया है उस हिसाब से ३० लाख लगेगा। तो इस हिसाब से ६० करोड़ रुपया चाहिए उनको बनाने के लिए। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आगे भी यह चीज रखें। इसमें २० करोड़ रुपये वे कान्ट्रीब्यूट करें गे जो कुए बनाना चाहते हैं और चालीस करोड़ रुपया गवर्नमेंट की ओर से होगा। उनमें से २० करोड़ रुपया गवर्नमेन्ट की ओर से लोन होगा जो कि २०-३० साल में इन्स्टालमेंन्ट के रूप में वसूल कर लिये जायं और २० करोड़ रुपयों की उनको ग्रान्ट हो गई। नतीजा यह हुआ कि इतनी बड़ी योजना के लिए ४० करोड़ रुपये चाहिये २० करोड़ रुपया आप लोन में देंगे, हालांकि वह वसूल होगा और बाकी २० करोड़ रुपया गवर्नमेंट का होगा। अगर आप इसको दो तीन योजनाओं में फैला दें तो मैं समझता हूं कि पहली योजना में पांच करोड़ रुपया आयगा और सेन्ट्रल गवर्नमेंट से कोशिश की जाय पूरी ताकत से कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी हमें पांच करोड़ रुपया दें। ५ करोड़ रुपया आप कुओं पर खर्च कर सकते हैं।

(घंटी)

इसके सिवाय मेरा दूसरा सुझाव है और जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया था, और आज भी कर देना चाहता हूं। आज देहातों से शिकायतें आ रही हैं कि हमारे यहां, हमारे इलाके में पानी नहीं है, तीनसौ आबादी के गांवों में कुछ नहीं कर रहे हैं; जहां पर पानी की कमी है, रेगिस्तानी इलाका है वहां पर आपको एक योजना निश्चित बनानी पड़ेगी कि जहां १०० आदमियों का गांव है उसको निश्चित रूप से तीन हजार या चार हजार का बनाइये। जैसे जैसलमेर है, उसकी निज्वे

[श्री गोपीलाल यादव]

हजार की आबादी है। अगर पांच हजार की आबादी पर एक ट्यूब वेल बने तो तीस ट्यूब वेल से जैसलमेर ठीक हो जायगा। इस प्रकार का प्रयत्न करना चाहिए कि गवर्नमेंट एक ब्लॉक बना कर कि इतने गांवों को, इतने आदमियों को एक जगह कन्सन्ट्रेट कर दे और वहां ट्यूब वेल बना दें इससे उनको पानी भी पीने के लिए मिल सकता है और सिंचाई भी हो सकती है। इस तरह देहातों में कर सकते हैं। एक, दो तीन देहात आते हैं, उन्हें आपस में मिला दें। नदी घाटी जो योजनायें हैं उनसे तो जो नजदीक के गांव हैं उनको फायदा होगा। राजस्थान को फूड के माने में एक सरप्लस एरिया भी बना दें, एक्सपोर्ट भी करने लग जांय तब भी उन लोगों की गरीबी नहीं मिटने वाली है कि जिनके यहां पानी नहीं बरसता है। इन दो सुझावों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष—मेरे पास बोलने वालों के बीस नाम आये हैं और एक घन्टे का समय है। इसलिए मैं माननीय सदस्यों को कहूंगा कि वे तीन मिनिट से पांच मिनिट के बीच अपने भाषण समाप्त करदें।

श्री भैरुसिंह (केलवा)—माननीय अध्यक्ष, यह जो योजना हमारे सामने प्रस्तुत हुई है उसमें केवल डिस्ट्रिक्टों की ही उन्नति का दृष्टिकोण रखा गया हो, यह बात नहीं। इसमें प्रयत्न किया गया है कि हर स्थान को हर जगह की सर्वांगीण उन्नति हो, यह इसमें दृष्टिकोण रखा गया है। फिर भी कुछ भौगोलिक दृष्टिकोण से ऐसे स्थान मैं बताऊंगा जिन स्थानों की उन्नति होना वहां के लोगों के लिए और वहां की जनता के लिए और वहां की आम जनता के लिए बहुत फायदेमन्द साबित हो सकता है। एक ऐसा भाग जो अजमेर से लेकर आबू के पहाड़ों तक लगा हुआ है वहां ऐसे लोग रहते हैं जिनके प्रति अब तक इस योजना में कोई ध्यान नहीं दिया गया है जिससे उन लोगों को लाभ हो सके। यहां ज्यादातर पहाड़ी हिस्सा है, इस हिस्से में बहुत छोटे छोटे खेत हैं। मुश्किल से एक आदमी के पास एक बीघा या दो बीघा खेत हो। इस इलाके में पहाड़ों की कमी नहीं, फिर भी बान्ध बंधवाना बहुत जरूरी है। केवल इरिगेशन के लिए ही बांध नहीं बंधते। यदि इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखा गया तो वहां इससे कोई आमदनी होने वाली नहीं क्योंकि वहां जमीन बहुत थोड़ी है। बांध बड़ी बड़ी जगहों पर बनते हैं जहां फैलाव होता है। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि ऐसे इलाकों के लिए इरीगेशन का ऐसा सिस्टम रखा जाय जिससे छोटे छोटे बांध पहाड़ी इलाकों में बांधे जावें। ऐसी योजना इरीगेशन विभाग बनावे जिसमें ऐसे किसानों के दृष्टिकोण को ध्यान में रखा जावे। अगर इस इलाके के किसानों को राहत पहुँचाना है तो कोई न कोई तरीका आपको अख्तयार करना होगा। छोटे छोटे बांध हरेक गांव के पास बनाइये।

दूसरा लोगों को, रेगिस्तान में रहने वाले लोगों को कुआ न होने की शिकायत रहती है। वहां कुओं की कमी है या खारा पानी है तो ऐसी जगहों के लिए मैं निवेदन करूंगा कि पानी बहुत

[श्री भैरोंसिंह केलवा]

है लेकिन फिर भी बांध बंधवाने की आवश्यकता है। बावड़ियों के पानी पीने से वहां नहरू की इतनी शिकायतें हैं कि वहां की आबादी एक चौथाई भाग नहरू की तकलीफ से सफर करते हैं। जिस वक्त बरसात के दिन आते हैं और उधर खेत को बोने के दिन आते हैं तो बादलों की गर्जना के साथ इसका भी जोर ज्यादा बढ़ता जाता है। वहां की भूमि का एक चौथाई भाग इसके कारण बेकार पड़ा रहता है क्योंकि वहां की आबादी का चौथाई भाग इस बीमारी से पीड़ित रहता है। आज तक मैं नहीं समझ पाया कि इसकी रोकथाम के लिए सरकार द्वारा प्रयत्न क्यों नहीं किया गया ? मेरा इसके बारे में यह सुझाव है कि एक बटा तीन हिस्सा जो कॉन्ट्रीब्यूशन बावड़ियों के बनवाने के लिए सरकार जनता से लेती है वह न लेकर गवर्नमेंट अपने खर्चे से पीने के पानी का इन्तजाम करे तो इस बीमारी की रोकथाम हो सकती है। यह नियम हटा दिया जाय ⅓ हिस्सा लेने का तो इस बीमारी की रोकथाम हो सकती है। ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करूंगा कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह बहुत जरूरी है। वहां के लिए छः छः हजार का दृष्टिकोण ठीक नहीं बैठता। ये गांव ऐसे बसे हुए हैं जिन इलाकों में छः हजार की आबादी नहीं हो सकती। ऐसे ऐसे गांव, जहां १०० घर की आबादी है; ऐसे भी गांव हैं जिनमें सिर्फ पांच सात ही घर बसे हुए हैं; वहां न तो हाई ड्रो इलेक्ट्रिक ही पहुंच सकती है क्योंकि वे पहाड़ियों की तलेटियों में बसे हुए हैं, अतः इन इलाकों का भी ध्यान रहना चाहिये। वहां के लोग सिर्फ जो खाने के काम में अनाज आता है उसकी ही फसलें बोते हैं। कोमर्शियल क्रोप बोना नहीं जानते। वहां के लिये एक्सपर्ट लोगों की यह राय है कि उस इलाके में नरसरी या बगीचे लगाये जायें तो उस इलाके की उन्नति हो सकती है; इसके लिये बहुत थोड़ी रकम रखी गई है। मेरा आपसे यह निवेदन है कि इन लोगों को राहत पहुँचानेके लिये ज्यादा रकम रखी जानी चाहिये। यह इलाका पहाड़ियों से घिरा हुआ है, यहां नई सिंचाई योजना कामयाब नहीं हो सकती। इस एरिया के लिये मैं यह कहूंगा कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट के अन्तर्गत भी चार पांच साल हो गये, वहां कुछ काम नहीं हुआ है। अब उन लोगों में इसके प्रति उत्साह पैदा हो गया है इसलिये इस काम के लिये काफी पैसा रखा जाना चाहिये। इस वक्त भी लोग श्रमदान करने को तैयार हैं क्योंकि कम्युनिटी प्रोजेक्ट का समय समाप्त होने जा रहा है। उस समय जो स्टाफ था वह एक्सपीरिएन्स्ड, नहीं था पैसा लेने का तरीका भी नहीं जानते थे। दो तीन सालसे उनको भी तजुर्बा हो गया अब वे इसके महत्व को पहिचानने लगे हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट का जो एरिया चला आ रहा है उसको एक्सटेन्ड किया जावे और इस दूसरी पंचवर्षीय योजना में विशेष रूप से काम लगाया जावे वरना लोगों में जो स्पिरिट पैदा हुई है वह स्टोप न हो जाय।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मुझे काफी निवेदन करना था किन्तु समय हो गया है। इतना ही निवेदन करूंगा कि हमारी आमेट तहसील में पेट्रोल की भी गुंजाइश है, उसका रिसर्च होना चाहिये।

रेलमगरा में तांबे की खानें हैं। उन खानों की ओर भी गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया। मेरा यह निवेदन है कि इस ओर भी गवर्नमेंट ध्यान दे।

[श्री भैरोंसिंह केलवा]

सड़कों के बारे में यह जो क्रेटिरिया रखा गया है कि पांच हजार को आबादी वाला हर कस्बा सड़कों से जोड़ दिया जायगा मेरा इसमें यह निवेदन है कि मेनरी के जितने भी सेन्टर्स हों उनको भी इम्पोर्टेन्स देना चाहिये। इस ओर सरकार को रेलवे लाइन भी निकालने के लिये सेन्टर को सिफारिश करनी चाहिये। रेलमगरा और बनास का एरिया ऐसा है जो मेनरी एरिया है, इसको रेलवे लाइन से जोड़ने के लिये भारत सरकार को सिफारिश की जानी चाहिये। रेलवे लाइन खोलने में केवल पेसेन्जरों का ही खयाल न रखा जावे गुड्स का दृष्टिकोण भी रखा जावे; तो ऐसे इलाकों के लये फायदेमन्द होगा।

मैंने राजस्थान सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं देखी जिसके अन्तर्गत जो बेगर्स का प्रोब्लेम बढ़ता जा रहा है उसको सोल्व करने का कुछ उपाय हो। यह एक महत्वपूर्ण प्रोब्लेम है। इस सम्बन्ध में कोई योजना होनी चाहिये। बेगर्स हमारे लिये अभिशाप है। इस अभिशाप को कम करने के लिये कुछ योजना बनानी चाहिये। जिस प्रकार जेलों में सुधार के प्रयत्न किये जाते हैं वहां कैदियों को अच्छा नागरिक बना कर बाहर निकालना चाहते हैं उसी प्रकार बेगर्स के लिये पुअर हाउस का इन्तजाम किया जावे। वहां उनको धंधों की ट्रेनिंग दी जाय और जो हैबिट पड़ गई है उनको छुड़ा कर अच्छे नागरिक बना कर उनको पुअर हाउसेज़ से निकालना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जिस एरिया का मैंने जिक्र किया है उसका ध्यान रखा जावे और प्रोजेक्ट का जो काम चल रहा है उसको न रोका जावे।

श्री बलवीरसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, दो दिनों से द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर विचार हो रहा है। राजस्थान सरकार और राजस्थान सरकार के अधिकारी गण को मैं धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता जिन्होंने मेहनत करके इतनी बड़ी योजना सदन के सामने रखी। इसके साथ साथ मैं इस योजना में कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। उन सुझावों के लिये मैं आपके जरिये हमारे मंत्रिमंडल को दरख्वास्त करूंगा कि आयन्दा इन सुझावों का अवश्य ध्यान रखें। इस तरह की इसमें कई स्कीमें हैं जो फ्लेक्सीबल स्कीम्स हैं, उनमें अदलाबदली हो सकती है; जहां तक हो सके उनको बदला न जाय ऐसा मेरा निवेदन है।

इसके अलावा इसके अन्दर जो सड़कों के लिये रकम रखी गई है वह पहले से ज्यादा है। अगर पहली योजना की तरह ही इसमें सड़कों का काम चला तो शायद मेरे ख्याल से ज्यादा फायदा न हो। हमारे सीकर जिले के लिये कई सड़कें मन्जूर हुई थीं, किन्तु अभी तक १०, १२ मील के अलावा कहीं सड़क कोई पूरी नहीं बनी जब कि स्कीम्स में काफी सड़कें थीं। तो सड़कों के मामले में एक तो अभी इस तरह की स्कीम रखी गई कि ५ हजार और उमसे जो बड़े कसबों को तहसील हैडक्वार्टर से जोड़ दिया जाय। तो मैं आप से अर्ज करूं कि जहां पर लोगों की

[श्री बलवीर सिंह]

आबादी का स्तर कम है और हमारे यहां किसी भी गांव के अन्दर ५ हजार की आबादी नामुमकिन सी है। ऐसे कस्बे १०, १५ बड़ी मुश्किल से मिलेंगे। जिस कन्स्टीटुएन्सी से में आया हूं उसकी मैं बतलाता हूं कि उस कन्स्टीटुएन्सी की २,१०,००० की आबादी में कुल ३ कस्बे ऐसे हैं जिनकी आबादी ५ हजार से बड़ी हो। बाकी किसी की आबादी ४ हजार, किसी की ३ हजार से भी कम पड़ती है। तोउनका नम्बर आनाबड़ा मुश्किल पड़ेगा जबकि सारी की सारी पब्लिक इतनी है जो कि देहात में बसती है, और ऐसे गांव जितने भी होंगे वह इससे महरूम रहेंगे, जिससे कि वे लोग जिनके बलबूते पर सरकार चलती है, महात्मा गांधी का स्वप्न जो कहा गया कि एक झोंपड़ी में रहने वाले को प्राइम मिनिस्टर देखना चाहता हूं, वह स्वप्न पूरा नहीं होगा। इस तरह की चीज जब हम महसूस करते हैं, तो यह सोचते हैं कि ४ हजार या ५ हजार का जो रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है इस तरह काम लगाया जाकर इस तरह से हो सकता है कि माइलेज का रेस्ट्रिक्शन लगाया जाय कि इतने मील के एरिया में एक औषधालय होगा और इतने मील के एरिया में डिस्पेन्सरी खोली जाय। लेकिन यह जो ५ हजार या १० हजार का जो रेस्ट्रिक्शन है वह इस तरह का है कि जिससे मीलों देहात में रहने वाली जनता उससे बिल्कुल महरूम रह जायगी। वहां की जनता को पंचवर्षीय योजना से फायदा नहीं होने वाला है।

जब हम देखते हैं इसके अन्दर कि २ करोड़ रुपया बीकानेर में वन विकास के लिए खर्च किया जा रहा है, लेकिन इस सिलसिले में मैं आप से अर्ज करूं कि हमारे जिले में इस तरह का बीड़ है जिस बीड़ के अन्दर कम से कम, दो नहीं तीन तहसीलों के मवेशी चरते हैं और उन मवेशियोंको उससे काफी फायदा होता है, लेकिन जिस स्थितिमें आज वह बीड़ है उसकोहम विकसित नहीं कह सकते हैं। उसका अगर विकास नहीं करते हैं तो उससे उतना फायदा नहीं हो सकता है। उतना क्या उसमें आजकल बहुत ही कम घास पैदा होने लगी है और काफी पहले से कम उसमें पेड़ पौधे रहे हैं। (समय समाप्ति सूचक घंटी) इसलिए मैं, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि कम से कम इस तरह की जो स्कीमें हैं उनमें सब जगहों को लिया जाय। पिछली पंचवर्षीय योजना में सीकर जिले को कम से कम एवोइड कर दिया गया था और इस बार भी जब माननीय मुख्य मंत्रीजी यह कह रहे थे कि कम से कम ६६ लाख रुपया आया है, लेकिन हमारे यहां मैं समझता हूँ ६६ लाख छोड़ ६६०० रुपया भी उस आबादी में नहीं आया है और मैं समझता हूँ कि आगे इस तरह की स्कीमे हों कि जिन स्कीमों में हमारे जिले को एवोइड किया गया है इसलिए माननीय अध्यक्ष, मैं आपके जरिये माननीय मंत्री महोदयों और मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि कम से कम उस तरह की जो चीजें होती हैं उनको ध्यान में रखें। चूंकि समय नहीं है इसलिए ज्यादा अर्ज नहीं करना चाहता हूँ और अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री हंसराज जटिया—अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की पंचवर्षीय योजना पर सदन में दो दिन से वाद-विवाद हो रहा है। राजस्थान के भिन्न २ क्षेत्रों से आये हुए सदस्यों ने अपने २ सुझाव

[श्री हंसराज जटिया]

रखें हैं; बातें रखी हैं। मेरा भी, अध्यक्ष महोदय, एक सुझाव है। वह इस प्रकार का है कि वहां पर ४४,४५ मील की रेलवे लाइन की जरूरत है। २४ मील करौली तक बढ़ाकर और २० मील गंगापुर तक बढ़ाकर उसको मिलाया जाय। धौलपुर राज्य जब था उसमें सारी चीजें वहां पर जनता के लिए उपलब्ध थीं लेकिन बहुत बड़ी तब्दिलियां हो रही हैं। पंचवर्षीय योजना में भी उसकी तरफ कोई ख्याल नहीं किया गया है। धौलपुर में अगर सरकार चाहे तो तांबे की खान भी बड़ी आसानी के साथ निकल सकती है। इसके अलावा धौलपुर में राजस्थान के वन विभाग का स्कूल खोले जाने के लिए भी काफी स्थान मौजूद हैं। वहां पर मकतबशाही एक स्थान है जहां बादशाह शाहजहां के जमाने का स्कूल बना हुआ है,वहां पर स्कूल और विद्यार्थियों तक के रहने के लिए काफी जगह है। धौलपुर में चमड़े का स्कूल खोल दिया गया है। राजस्थान में कोई चमड़े का कारखाना नहीं है, इसलिए वहां पर, चूंकि आगरा धौलपुर के बहुत समीप पड़ता है, इसलिए चमड़े की सामग्री वहां पर पास में बहुत अच्छी और सस्ती उपलब्ध हो सकती है। परन्तु राजस्थान की और जगहों के मुकाबले में धौलपुर में अब तक अराजकता बराबर चली आ रही है। एक दफा सदन में, तारीख मुझे याद नहीं है, एक प्रश्न के उत्तर में यह जवाब दिया गया था कि और भी ऐसी जगहें हैं जहां जिले बनाये जाने का सवाल है और धौलपुर का भी उसमें नाम है। इसके लिए अब तक कुछ भी सरकार की तरफ से नहीं हुआ है। वहां ऐसे स्थान हैं जो अत्यन्त शीघ्र बनाये जाने के योग्य हैं। वहां पर पक्की सड़कें धौलपुर से मथुरा, धौलपुर से करौली तथा बारी से श्योपुर होनी चाहिए। बारी धौलपुर सब डिविज़न का एक बड़ा कस्बा है। सब जगह हाईस्कूल खुल रहे हैं लेकिन उस क्षेत्र के रहने वालों का इसमें स्थान नहीं है। (समय समाप्ति सूचक घंटी) धौलपुर सब डिविज़न में पशुओं के चराने का अब तक कोई प्रबन्ध नहीं हुआ है। वहां किसी प्रकार की सुविधा नहीं है।

जनजातियों के लिए २० लाख रुपया और अनुसूचित जातियों के लिए ५५ लाख रखा गया है। अनुसूचित जातियां तादाद में बहुत हैं, संख्या में बहुत हैं। अनुसूचित जन जातियाँ संख्या में कम हैं। इतने से रुपये से राजस्थान की बेकवर्ड क्लासेज़ के लिए क्या फायदा हो सकता है, अब तक उनके लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है जब कि वे राजस्थान के नागरिक माने जा चुके हैं। अन्य नागरिकों के समान उनको भी फायदा होना चाहिए। बस इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा।

श्री अध्यक्ष—श्री जगतसिंह झाला।

श्री जगतसिंह झाला—माननीय अध्यक्ष, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के ऊपर मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। मेरे निवेदन करने का मतलब यह है, अध्यक्ष महोदय, कि पंचवर्षीय योजनाएं राष्ट्र निर्माण के लिए बनाई जाती हैं। वह योजना सार्वजनिक होनी चाहिए। उसमें

[श्री जगतसिंह झाला]

सभी जिलों के लिए, सभी तहसीलों में समान रूप से काम होना चाहिये। इसलिए यह निवेदन करने की जरूरत हो जाती है। जैसा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में हुआ वैसे ही इस योजना में कार्य रखे गये हैं। एक और निवेदन करना चाहता हूं, वह यह है कि जान बूझ कर हमारे क्षेत्र को अवज्ञापूर्वक छोड़ा गया है। उनके लिए भी इसी प्रकार से काम होना चाहिए जिस प्रकार से दूसरे व्यक्तियों के क्षेत्रों में काम हुए हैं। मेरे निवेदन करने का तात्पर्य यह है कि हमारे क्षेत्र में बड़ी सादड़ी से छोटी सादड़ी तक केवल एक सड़क पंचवर्षीय योजना में रखी गई है। वह सड़क केवल तीन मील ही बनी है, और इस रफ्तार से अगर वह चली तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी समाप्त नहीं होगी।

इसके अलावा और भी निवेदन करना चाहता हूं जो वह यह है कि कृषि के ऊपर एक बहुत बड़ी धनराशि खर्च करने के लिये पंचवर्षीय योजना में रखी गई है, लेकिन कृषि को बढ़ाने के के लिए चूंकि हमारे यहां छोटे छोटे कृषक हैं और उनको बैलों के लिए आवश्यकता होती है, इस पशुधन को बचाने के लिए मेरे निवेदन करने का तात्पर्य यह है कि राजस्थान सरकार को अपनी नीति बदलनी होगी। वह इस तरह से कि यहां से गायों की निकासी होती है, उस निकासी को रोकने के लिए राज्य में मुख्य मंत्री यह आश्वासन दें तो मैं कह सकता हूं कि गायों की निकासी को रोककर पशुधन को बढ़ाना होगा, तो आपकी पंचवर्षीय योजना जरूर बड़ी हो सफलतापूर्वक चल सकेगी। मेरे निवेदन करने का मतलब यह है कि भावनाओं को, मेरा ख्याल है, राइज़ करने की बात नहीं है, लेकिन यह ऐसी चीज है कि पशुधन को बाहर जाने से रोका जाय, गायों की निकासी के लिये और दूसरे प्रान्तों में भी रोक लगाई गई है। (हियर हियर) मैं चाहता हूं कि हमारे प्रान्त में भी इस प्रकार की रोक लगाई जाय।

दूसरी बात यह है कि वेजिटेबल घी जो स्वास्थ्य के लिये अत्यन्त हानिकारक है उसको यहां आने देने से रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है, इस कारण भी जन-स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है और लोगों की दशा ऐसी सोचनीय हो रही है कि जन-स्वास्थ्य के लिये आप कितने ही रुपये खर्च करते हैं वे सब यों ही जाते हैं। यदि आप वेजिटेबल घी पर रोक नहीं लगायेंगे तो बहुत अधिक हानि होगी और हमारा स्वास्थ्य गिरता जायगा।

एक और बात निवेदन करना चाहता हूं जो यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहां बहुत सी स्कूलें खुलती हैं उसके लिए मुझे खुशी है। इसके लिए मैं सरकार की प्रशंसा करूंगा। इस क्षेत्र में हमें काफी प्रगति मिली है, लेकिन मैं एक विशेष बात का उल्लेख करना आवश्यक समझता हूं कि राष्ट्रीय शिक्षा पर जो प्रभाव क्रिश्चियन मिशिनरीज़ का आजकल पड़ रहा है उसको फौरन बन्द करना चाहिये, इसका बहुत बुरा असर हमारे विद्यार्थियों पर पड़ता है। मुझे उम्मीद है कि इस दिशा में शीघ्र ही कार्यवाही की जायेगी। मैं इतना ही कह कर बैठना चाहता हूं।

श्री ईश्वरी सिंह—अध्यक्ष महोदय, पंचवर्षीय योजना के वास्ते अच्छी अच्छी बातों के वास्ते भोत सा रूपिया राख मेलिया है या भोत आच्छी बात है। मेरी समझ में इयांनकी चीज हो रही है कि जो कुछ इमदाद राखी गई है वा मालदारां के वास्ते है। त्रियों के वास्ते राज बहुत बड़ा रूपया खर्च करणा मंजूर करिया है और बहुत आछो योजना बनाई है, पर बी से भूमिवालों, गरीबों को फायदो नहीं है क्योंकि पहले तो जमीन नीलाम कर मोल ले ली जायगी। दूसरी बात या है कि वां पर ७५ रूपया लगान का किया तो गरीब पहले ७५ रू० दे।

दूसरी बात या है कि शिक्षा को बहुत अच्छो बड़ो महकमो है। दुनिया को आखिर सुधार हो सके है तो शिक्षा से हो सके है। शिक्षा में गरीबों की कोई चीज नहीं आई। गरीब कियां पढ़ सके। शहरों में बड़े बड़े क्षेत्र में ओर्डर लगाया है तो कम से कम कोई भी आदमी गांवों में फायदो नहीं उठायो। लड़का लड़कियों को एक सो हक है तो शहरों में लड़कियों की स्कूलें है लेकिन बाहर गांवों में लड़कियों का स्कूल खोलने को सवाल न तो कोई उठायो। और न सरकार कोई रूपया ही काम के तांई राखिया। लड़कियों को भी बराबरी को हक होणो चाहिये। पढ़ाई को इन्तजाम होणो चाहिये।

दूसरो गरीब, वो समजियो जावे है जो हाथ पांव, कान नाक आंख सब खराब हो रया है एक तरफ पडियो है, पग में जेवडी घाल मेली है, वांके वास्ते सरकार कांई इन्तजाम करियो। प्रजातन्त्र को नाम तो हो रयो है और पंचवर्षीय योजना में सुधार हो रयो है लेकिन सुधार इण रूप में हो रयो है। भैंस खल खाते तो क्यों खावे ई वास्ते खावे कि वा स्वाद लागे पर घर को धणी ओ समझे कि खल खावेला तो घी आजायलो तो सुधार इण तरे को हो रयो है तो आपके लिये भैंस वाली धारणा आ जावे है, आंपणों तो भलो हो ही जावेलो।

जल बोर्ड बनायो जद भीं आ बात ही कि तमाम दुनियां में धन बांटियो जा रयो है पाणी के वास्ते। पर जद रूपया देवणा री बात आई तो आ बात जाण पड़ी कि कांग्रेस का जितना आदमी चुनाव में हारया है वां जगां मेम्बर बैठाया गया उण गांवों ने ए रूपिया नहीं मिल सके। इयों की सरकार में लूट मच रहीं है। जो जल बोर्ड बणायो है वह बंटवारो ठीक तरह से सोच समझ करे तो लोगों को दुख दर्द मिट सके है। और भी जो प्रोग्राम बणाया है उवां को हाल भी उणी तरह को हो रयो है। इण तरह की चीज नहीं होनी चाहिए।

श्री प्रभुदयाल—उपाध्यक्ष महोदय, पंचवर्षीय योजना को पढ़कर इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि सरकार ने बहुत मेहनत के साथ १२१ करोड़ रुपयों की मंजूरी कराई है (हियर, हियर)। मैं उन अधिकारियों को धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता जिन्होंने समाज कल्याणकारी राज्य समझ कर इस योजना को बनाने में योग दिया है। जहां तक मैंने इस योजना को पढ़ा है मैं यही समझ पाया हूँ कि यह बहुत अच्छी योजना है। लेकिन मैं अधिकारियों और सरकार का ध्यान उन कमियों की ओर दिलाना चाहता हूँ जो भूल से रह गई हैं, मैं यह नहीं कह सकता कि सोच समझ

[श्री प्रभुदयाल]

कर रखदी गई हैं, इतनी बड़ी योजना में भूल हो सकती है। सरकार को मालूम है और अधिकारियों को मालूम है कि बीकानेर डिविजन का बहुत बड़ा हिस्सा इस योजना से फायदा उठानेवाले हिस्सों में शामिल हो रहा है। मेरा जिला जो है चूरू, उसमें ७ तहसीलें हैं। उस जिले की एक इंच जमीन भी सिंचाई के अंतर्गत नहीं आनेवाली है। इसलिये मैं मुख्य मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरे इलाके में जहां सिंचाई योजना नहीं लागू होगी वहां कुओं का पानी खारा है। वहां पर जल बोर्ड का पैसा ज्यादा से ज्यादा खर्च किया जाय। जहां बंध बन जाना जरूरी है और सिंचाई की योजना के अंतर्गत जहां नहरें जा सकें वहां जाना जरूरी है, लेकिन जिस इलाके में नहरें नहीं बन सकतीं, जहां का पानी खारा है वहां पानी का समस्या को हल करने के लिये सरकार को ज्यादा पैसा लगाना चाहिये क्योंकि इस इलाके की जनता को मालूम है कि उनकी स्थिति कितनी खराब है। उनका तमाम जीवन पानी के लिये ही लगता है और कमाई धन्धे के लिये शायद उसको समय नहीं मिलता। मैं सदन के नेता का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि बहुत से इलाकों में सिंचाई नहरों से हो रही है और बहुत से इलाकों में बांध बन रहे हैं, लेकिन मेरे इलाके में सिंचाई के साधन नहीं हैं। कम से कम कुओं आदि पर रकम लगा कर पानी की समस्या को हल करना चाहिये।

मेरे इस इलाके में भेड़ें काफी हैं। उनकी नस्ल आदि सुधार कर ऊन के व्यापार की तरक्की करनी चाहिये। यह व्यापार काफी अच्छा चल सकता है, इससे गरीबों का भला हो सकता है। मैं नेता महोदय का ध्यान इस ओर दिलाता हुआ यह अर्ज करूंगा कि इस ओर विशेष गौर फरमावें।

मैं एक और निवेदन करना चाहता हूँ, वह यह है कि मेरे इलाके में जिप्सम बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। उससे सरकार को बहुत बड़ी आमदनी हो सकती है लेकिन यहां रेल का पूरा साधन नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान सरकार अपनी ओर से केन्द्रीय सरकार को मजबूर करे कि वहां रेल की लाइन अधिक करने की व्यवस्था करे।

इसके अलावा मैं यह बतलाना चाहता हूँ कि मेरे इलाके में तारानगर तहसील है जहां नेता महोदय खुद पधार चुके हैं, वहां का पानी बहुत खारा है। जिन स्थानों का पानी खारा है उनका नाम लिस्ट में बताया गया है। इस तरह के २५, ३० शहरों एवं कस्बों के नाम उस लिस्ट में दर्ज हैं, लेकिन तारानगर का पानी खारा होते हुए भी उसका नाम लिस्ट में नहीं है। मैं प्रार्थना करूंगा कि उसका नाम भी उस लिस्ट में जरूर आना चाहिये।

इस जिले का सेन्टर चूरू है। वहां पर सरकार की ओर से न तो डाक बंगले हैं और न कलेक्टोरेट आदि की सरकारी बिल्डिंग ही है। इस योजना में साफ तौर से बताना चाहिये था कि वहां पर सरकार बिल्डिंग बनायेगी। मैं प्रार्थना करूंगा कि इस कमी की ओर गौर फरमावें और

[श्री प्रभुदयाल]

कम से कम जिला अदालत, न्यायालय आदि की बिल्डिंग तो जरूर बननी ही चाहिये। इस तरह की जो कमियें है उनकी ओर आपका ध्यान दिलाता हुआ इतना ही कहना बहुत है कि मेरा इलाका पिछड़ा हुआ है, वहां पर सड़कें नहीं है। यह सड़क है जो २०,२५ माइल की है जो बहुत पहले बनी थी। यह टूट चुकी है। बहुत दफा असेम्बली में प्रश्न इसके बारे में आये कि डामर की सड़क बननी चाहिये लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। मेरा इलाका पिछड़ा हुआ है, उस ओर गौर करना चाहिये। जो इलाके एडवान्स्ड है, जिनमें सिंचाई के साधन मौजूद हैं, धंधा हो सकता है उनकी तो आप और भी उन्नति करते हैं लेकिन जो पिछड़ा हुआ इलाका है उस ओर अधिक गौर करना चाहिये। मैं नेता महोदय से प्रार्थना करूंगा कि योजना में कम रह सकती है, अधिकारियों की भूल के कारण हो सकता है कि कमी रह गई हो, लेकिन मेरे इलाके की ओर गौर फरमाकर इस ओर विशेष ध्यान फरमाकर पूरा करने की कृपा करेंगे।

राव श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—अध्यक्ष महोदय, यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना की पीली कापी देखी गई और इसका अध्ययन किया। इसमें कोई सन्देह नहीं कि करीब सवा अरब रुपया हम इसमें खर्च करने जा रहे हैं और अधिकतर यह रुपया भारत सरकार राजस्थान को देगी। इसमें कुछ रुपया यहां भी हर तरह से संग्रह करने की आवश्यकता होगी।

सवा अरब रुपया एक खासा रकम है और ५ सालों में यह खर्च की जावेगी। इसमें कोई सन्देह नहीं कि हर तरह की स्कीमें इसमें मौजूद हैं। क्या शिक्षा में, क्या मेडिसिन्स में, क्या रोड्स में, इरीगेशन में और इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स आदि में, काफी रुपया खर्च किया जावेगा और आशा हमें यह करनी चाहिये कि इसका अन्तिम परिणाम बहुत ही अच्छा निकलेगा। लेकिन यह कहावत हैं :

"The proof of pudding lies in eating."

यह पुडिंग तो तैयार हो गया है पर ५ साल बाद हम जब इसे खायेंगे तब मालूम पड़ेगा कि यह पुडिंग कैसा बना है।

राजस्थान ने क्या तरक्की की और हमारी क्या हालत है, मैं आशा करता हूँ कि भारत सरकार ने इस बात का ध्यान अवश्य रखा होगा कि इतनी धन राशि खर्च करने पर और इतने अनएम्प्लोयड को काम देने पर हम किस स्टेज पर पहुंच जायेंगे। आयन्दा हमारे पास इतनी धन राशि होगी कि नहीं, कि इतनी धन राशि खर्च करने को तैयार होंगे कि नहीं। क्या इतनी धन राशि खर्च करने से जितनी धन राशि हम इस पंचवर्षीय योजना पर खर्च करेंगे, उतनी रकम प्राप्त कर सकेंगे कि नहीं, मैं समझता हूँ कि स्कीम बनाने वाले सज्जनों ने अवश्य इस बात पर ध्यान दिया होगा।

[राज श्री हिम्मतसिंह]

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि " हैल्थ इज़ वैल्थ " तो जन स्वास्थ्य अच्छा हो, सबसे पहले हमें इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह स्वास्थ्य अच्छा कैसे होगा ? खाली डाक्टरों को रखने से अथवा रकम बजट में अलोट कर देने से तो काम नहीं चलेगा। इसके लिए शिक्षा ऐसी जरूरी है और इसमें काफी रुपया लगाया है कि इसके कारण लोग बाग शिक्षित होकर अपने स्वास्थ्य पर विचार कर सकेंगे, पर केवल स्वास्थ्य पर विचार करने मात्र से काम नहीं चलेगा। जब तक खाने पीने की चीजें, न्युट्रिशन और विटेमिन्स नहीं मिलेंगे तब तक कैसे आम लोगों की तन्दुरूस्ती ठीक हो सकती है ? राजस्थान में दूध दही की हमेशा नदियां बहती रही हैं और राजस्थान ऐसा प्रान्त है जहां गौधन बहुत है, इसके ऊपर मैं समझता हूं कि आवश्यक धन खर्च किया जायगा।

पर नस्ल किस तरह सुधारी जावेगी, कैसे गौरक्षा की जावेगी ? हर साल काल पड़ते हैं। लाखों गायें काल में इधर से उधर फिरती हैं, क्या इन्तजाम इसके लिए किया जावेगा ? मारवाड़ से आने वाले सदस्यों ने इस बात पर ध्यान दिलाया था कि हमारा भाग इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना से बिल्कुल बाहर रखा गया है।

(वक्ता महोदय द्वारा हंसी)

इसके अलावा मैं यह अर्ज करूंगा कि जहां तक आयुर्वेदिक औषधालयों का सवाल है इसके लिए काफी रकम रख दी गई है। हम चाहते हैं कि कम से कम इतना अवश्य होना चाहिए कि हर पंचायत के सरकल में १ वैद्य रहना चाहिए ताकि गांव वालों को जरूरत के समय दवाई मिल सके। जैसे कि बताया गया है कि मलेरिया, मलेरिया ऐसी बीमारी है कि वैद्यों के काबू के बाहर की बात है, इसके लिए हमें आवश्यक माकूल इन्तजाम करना चाहिये..........

(वक्ता महोदय द्वारा पुनः हंसने पर श्री अध्यक्ष द्वारा संकेत से पूछने पर)

चीफ मिनिस्टर साहब हंस रहे हैं, इसलिये मुझे भी हंसी आ रही है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री)—मैं किसी और बात पर हंसा हूं।

श्री हिम्मतसिंह—इसी बात पर हंस रहे हैं, मेरी बात पर।

श्री भोगीलाल पंड्या—आपके भाषण पर हम सब बहुत प्रसन्न हैं।

(श्री हिम्मतसिंह द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर बनाये गये कार्टून को जो श्री मुख्य मन्त्री के पास पहुंचाया गया था, देख कर पुनः हंसी)

श्री अध्यक्ष—(उसी कार्टून की ओर संकेत करते हुए) आपको जो कुछ कहना था कह दिया है।

श्री हिम्मतसिंह—पर वह रेकर्ड में नहीं आयेगा।

एक थोड़ी सी बात कह दूं जो नारवा (गिनी वार्म) की बीमारी का सवाल यहां खड़ा हो रहा है, वह बहुत ही उग्र रूप धारण कर रहा है। इसके लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। अगर इस पर तवज्जोह दी जावे तो लोगों को इससे बहुत फायदा पहुंचेगा। यह मेरा खुद का अनुभव शुदा है। जब मैं मुलाजिम रियासत था और तहसील में काम करता था तो इस बीमारी से हजारों लोग पीड़ित होते थे और हजारों बीघा जमीन पड़त रह जाती थी। मैंने इस पर सोचा और एक दवाई मुझे ऐसी मिली है जिसका मैंने इस बीमारी पर प्रयोग करना शुरू किया। दो साल में ही मुझे पता चला कि जो हजारों बीघा जमीन पड़त रहती थी, वह पड़त नहीं रहती और यहां तक कि और लोगों ने भी इस दवाई की मांग की। वह दवाई मामूली है और इसको डिस्क्लोज़ करने में, बताने में कोई ऐसी बात नहीं है। यह होमियोपैथिक दवाई है। स्पेसिफिक नं० ३३ और होमियोपैथिक डिस्पेन्सरीज़ से मिलती है। जहां मेरे मित्र मिलते हैं बता देता हूं। जन सेवा करना चाहें तो यह दवाई काम में लावें, इससे काफी लाभ होगा। ७५ परसेंट मुझको इसमें कामयाबी हुई है।

होमियोपैथी को इसमें स्थान दें तो अच्छा है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए मैं गवर्नमेंट को बधाई देता हूं।

श्री अध्यक्ष—श्री हरिदेव जोशी।

श्री हरिदेव जोशी—मैं नहीं बोलना चाहता।

श्री अध्यक्ष—श्री नाथूराम मिर्धा।

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय अध्यक्ष, मैं भी नहीं बोलना चाहता।

श्री लक्ष्मण हीरात—माननीय अध्यक्ष, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो हमारे सामने रखी है उस पर कल से विचार हो रहा है। इस पर मैं भी अपने कुछ विचार रखना चाहता हूं। जो मेरे पूर्व वक्ताओं ने बातें बता दी हैं उनको दोहरा कर मैं सदन का समय नहीं लूंगा। इसमें यह कहा गया कि यह किया जावेगा और वह किया जावेगा और इस वक्त यहां तक कहा गया कि इस योजना से हर एक तहसील और गांव को व हर एक डिस्ट्रिक्ट और हर एक जिले को एक दूसरे से मिलाने वाली सड़कों का निर्माण होगा। इसके अलावा हर एक पुलिस स्टेशन को भी सड़कों से मिला दिया जावेगा। लेकिन माननीय अध्यक्ष, मेरे समझ में नहीं आता कि किस तरह ऐसा हो

[श्री लक्ष्मण हीरात]

जावेगा । प्रथम पंचवर्षीय योजना हमारे सामने थी, उसका काम धीरे धीरे समाप्त होने वाला है। उसमें कोई काम नहीं हुआ । फिर दूसरी पंच वर्षीय योजना में बिजली की तरह बटन दबाते ही काम हो जायगा, यह कैसे हो जावेगा, यह मेरे समझ में नहीं आया । माननीय अध्यक्ष, जो रकम सामुदायिक विकास योजनाओं के लिये रखी गई है वह ऐसी है जिससे ऐसा मालूम होता है कि तीन चार सालों से काम हो रहा है । वह कुछ नहीं होने के बराबर है और सिर्फ आम जनता की भावना और प्रचार के लिए पिछले सालों में जोर दिया गया है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले वक्ताओं ने यह कहा है कि इस पंच वर्षीय योजना में बहुत बड़ा काम हो जावेगा , राजस्थान हरा भरा हो जायगा और राजस्थान कल्याणकारी राज्य बन जावेगा; लेकिन माननीय अध्यक्ष, मैं बताऊं कि शिक्षा के लिए जो आंकड़े दिये गये हैं वे १० करोड़ के करीब हैं ।

इससे काफी काम होने वाला है. यह नहीं होगा और इससे लोग दिन ब दिन होशियार होंगे ऐसा, मेरी समझ में नहीं आता । मेरे खयाल से जो आंकड़े दिये गये हैं वे बहुत कम मालूम पड़ते है । राजस्थान के लोग अधिक गांवों में रहते हैं । मगर उनके लिए इतनी बड़ी आबादी के होते हुए भी पानी, पढ़ाई, डिस्पेन्सरी व सड़कों आदि के साधन नहीं हैं जो शहरों में हैं । शहरों में बड़े बड़े होस्पिटल्स, कॉलेजेज़, हाई स्कूल्स व मिडिल स्कूल्स हैं । लेकिन माननीय अध्यक्ष मेरी समझ में नहीं आता है कि बाहर भी बन जावेंगी, यह कहा जाता है कि वह कैसे बन जावेंगी । जब तक हम शिक्षा में आगे नहीं बढ़ेंगे और सर्व साधारण को अच्छी शिक्षा जो कि उनके हर प्रकार हर रोज के काम में आने वाली है नहीं दी जावेगी तब तक हम आगे नहीं बढ सकते हैं । माननीय अध्यक्ष, आपके द्वारा मैं उदयपुर की ओर सदन के सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जहां आबादी आदिवासियों की है और उनको भलाई के लिए बहुत कम रकम दी गई है,

(घंटी)

जिसमे इनका भला होने वाला नहीं है । भाकरा नहर, चम्बल को योजना आदि से राजस्थान के दूसरे हिस्सों को फायदा पहुँचने वाला है । मगर इससे इस हिस्से को कोई फायदा होने वाला नहीं । इसलिये मैं हाउस का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं कि इस द्वितीय योजना में कुछ कार्य किया जावे जिससे इन आदिवासियों का ज्यादा से ज्यादा कल्याण और भला हो । इसलिये मैं चाहूंगा कि इस हाउस का ध्यान, जल्दी से जल्दी इन आदिवासियों की भलाई के लिए सिफारिश करने की ओर लगे ।

श्री **धूलजी भाई**—अध्यक्ष महोदय, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज हमारे सामने चीफ मिनिस्टर ने यह पंचवर्षीय योजना चर्चा करने के लिये रखी जिससे हमारे राजस्थान

[श्री धूलजी भाई]

की विशेष प्रगति होने वाली है। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो हमारे राजस्थान में चालू हुई थी उससे राजस्थान में जो काम हुआ उसको देख कर राजस्थान के लोगों में उत्साह बढ़ा और नेताओं ने आम लोगों में श्रमदान की भावना पैदा की। जिससे लोगों में भावना ऐसी पैदा हो गई है कि हम व जनता अपना श्रमदान देकर राज की तरफ से जो निधि आती है उसको सार्वजनिक कामों में लगावें। इस तरह से इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बहुत अच्छे अच्छे काम राजस्थान में होने वाले हैं उसे देखकर हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। इससे हमारे बहुत से सदस्यों को आत्म संतोष होगा। मगर फिर भी हमारी कुछ कठिनाइयें भी हैं और कुछ लोगों के उजर भी हैं कि जब इस पंचवर्षीय योजना में कई करोड़ रुपये लगेंगे और सरकार खर्च करेगी तो उससे राजस्थान की सारी पब्लिक को अवश्य लाभ होने वाला है। इसमें कार्य करने के लिये विधान तथा नियम हैं कि जो पिछड़े हुए जिले हैं उनमें उस प्रकार से कार्य होगा। मुझे इस बात का विश्वास है कि यह काम होगा इसके लिये मुझे कोई बात नहीं कहनी है और न आपत्ति करने की जरूरत है। लेकिन मुझे एक बात अपने जिले के बारे में कह देना आवश्यक है। हमारा जिला खेती प्रधान देश है। वहां सिंचाई के लिये छोटे छोटे बांध बनाये हैं। वहां मारी नदी का प्रोजेक्ट-लिया गया है, उसको बांधने की योजना है अगर बड़ी योजना में उसको ले लिया जाता है। तो बहुत कुछ बांसवाडा जिले की काया पलट हो जायेगी क्योंकि यहां पर ११ हजार किलोवाट बिजली तैयार हो सकती है; वह योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है। इससे बांसवाडा जिला आदि को और राजस्थान को काफी लाभ होने वाला है। अगर यह योजना सरकार ने स्वीकार की होती और अधिक रकम प्राप्त की होती तो इससे सिंचाई का काम इतना होने वाला है कि २ लाख टन अनाज की पैदावार होने वाली है। यहां के हाइड्रो-इलेक्ट्रिक की योजना सरकार के विचाराधीन है। इसलिये इसको बनाया जावे और बढ़ाया जावे तो हमारे राजस्थान का बड़ा लाभ होने वाला है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि हमारी सरकार जिस पंचवर्षीय योजना को लक्ष्य में लेकर काम करती है।

(घंटी)

देहाती लोगों को श्रम भावना के लिये, उनका प्रेम पैदा करने के लिये अगर इसके अन्दर हमारे सभी व्यक्तियों का श्रम लगे और बुद्धिजीवी अपना योग दें तो हमारे देश का निर्माण अच्छी तरह से हो सकेगा। इसलिये मैं आशा करता हूँ कि जो पंचवर्षीय योजना हमारे सामने पेश की गई है वह सराहनीय है। इसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने सारे राजस्थान का संकलन करके इस प्रकार की योजना को बनाया है। मेरा तो उनको धन्यवाद के साथ और माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन है कि जिन्होंने यह योजना बनाई है वे इस माही प्रोजेक्ट के बारे में भी अवश्य विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष—श्री लालबहादुर।

Page No.99

श्री लालबहादुर—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना को देखकर मेरे दिल में एक भावना उत्पन्न हुई है और वह यह है कि हमारी सरकार और उसका अधिकारी वर्ग बधाई के पात्र हैं और धन्यवाद के पात्र भी। धन्यवाद के पात्र तो इसलिए हैं कि उन्होंने हमारी जो पिछड़ी हुई राजस्थान की स्थिति है वह भारत सरकार के पास पहुँचाई और बधाई के पात्र इसलिए हैं कि उन्होंने मेहनत करके इस योजना को बनाया और मंजूर करवाया। लेकिन साथ ही साथ में चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि यहीं पर ही सरकार का और अधिकारियों का फर्ज पूरा नहीं हो गया है। जैसा कि नगर भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने फरमाया था कि राजस्थान गवर्नमेंट इस बात में कामयाब हुई कि भारत सरकार के दिमाग में यह बात पैदा करे कि राजस्थान बेकवर्ड है और राजस्थान की मदद करना भारत सरकार का परम कर्त्तव्य है और आगे इस बारे में हमारे अधिकारी और सरकार ऐसी योजनायें बनावें और भारत सरकार को पेश करे ताकि वे तृतीय पंचवर्षीय योजना में सफल हों और इस योजना में जो ४० करोड़ रुपया काटा गया है वह पूरा हो जाने की संभावना है।

साथ साथ मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस सदन में माननीय विरोधी दल के नेता ने जो बातें फरमाईं, कई हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट्स का नाम लेकर उन्होंने आलोचना की थी। उनको संतोष सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जितनी योजना बनी है वह हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट और उनके सहयोगियों से बनी है और उनकी जिम्मेदारी भी है कि इसको वे पूरा करें और यदि इसको पूरा नहीं करेंगे तो वे अपने फर्ज को पूरा नहीं करेंगे और आयन्दा उनकी तरक्की और बहबूदी भी इसी पर मुनस्सर है। उनका फर्ज है कि इस योजना को सफल करें, अगर उनके पास और काम है, वक्त इतना नहीं है कि पूरा रुपया खर्च करें तो उन्हें वक्त निकाल कर इस ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, यदि वे रुपया पूरा, समय के पहले भी खर्च कर दें तो और रुपया मांगे, एडीशनल रुपया मंजूर करायें और हमारी सरकार फिर नये नये इन्जीनियर्स मुकर्रर करें।

एक बहार से आने वाले इन्जीनियर्स का भी सुझाव विरोधी दल के माननीय नेता ने

(घंटी)

रखा था तो उस सम्बन्ध में मैं यह याद दिलाना चाहूँगा कि इस सदन में यह आवाज उठाई गई थी कि बाहर से आने वाले, अन्य प्रान्तों से आने वाले हमारे प्रान्त की स्थितियों को ठीक तरह से समझ नहीं सकते। जैसे चीफ सेक्रेटरी की ही पोस्ट थी तो उस पर भी हमारा इससे पहले कोई राजस्थानी व्यक्ति नहीं था।

श्री अध्यक्ष—आप फाइव इयर प्लान पर बात करिये।

श्री लाल बहादुर—मैं उस बात पर आ रहा हूँ, इस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। बाहर से इन्जीनियर बुलाये जावें तो क्या हमारे इन्जीनियर्स काबिल नहीं हैं, यही मेरी अर्ज करने की मंशा थी। एक बात जरूर मैं अर्ज कर देना चाहता हूँ जैसा कि डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने फरमाया कि फाइनेन्स डिपार्टमेंट की ओर से ऐसी बात रहती है कि योजना मंजूर हो जाने के बाद भी रुपया देने में कमी दिखाते हैं। मैं अर्ज करूं कि यह स्वाभाविक है और वे सोच समझ कर रुपया देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी न जाने क्या स्थिति है कि काफी देर लग जाती है। मैं आपको पाटन म्युनिसिपैलीटी को १,५०० हजार रुपया के देने सम्बन्ध में बताऊं कि वे कागजात लोकल सेल्फ डिपार्टमेंट और फाइनेन्स डिपार्टमेंट के बीच में ही अटक रहे हैं और न जाने और कितना समय लगेगा ?

श्री कपिलदेव अग्रवाल—यह बहुत खराबी की बात है।

श्री लाल बहादुर (अपना भाषण जारी रखते हुए)— माननीय अध्यक्ष, एक बात की ओर मैं ध्यान दिलाना अपना फर्ज समझता हूँ। हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सोया हुआ है। यह इसलिए अर्ज करने की हिम्मत करता हूँ कि इस पंचवर्षीय योजना में चम्बल के लिए काफी धनराशि मंजूर की हुई है। जब चम्बल की नहरों से सिंचाई होगी, आस-पास के एरिया में कपास होगा, शुगरकेन होगी लेकिन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने यह देखने की अब तक कोशिश नहीं की है कि कौनसा बीज वहां के लिए उपयुक्त होगा, कौनसी खेती वहां कामयाब हो सकती है, जो माल पैदा हो वह कैसा हो, कौनसा ऐसा माल हो जिसको कि एक्सपोर्ट करने पर अच्छा पैसा प्राप्त हो ? द्वितीय पंचवर्षीय योजना कामयाब होने के बाद लोग मांग करेंगे, उससे पहले ही उनको इसके लिए बताया जाय, बीज वितरण किया जाय तो काफी अच्छी तरक्की कर सकते हैं. लेकिन इस विभाग के द्वारा अब तक वहां कोई कदम नहीं उठाया गया है। मैं आशा करता हूं कि मेरी सरकार और अधिकारी इस ओर ध्यान देंगे।

(हंसी एवं घंटी)

श्री कपिलदेव अग्रवाल—साहब, यह सरकार राजस्थान की है। यह कह रहे हैं, मेरी है।

(हंसी एवं कुछ विराम के अनन्तर)

मैं समझा कोई ईडियम (idiom) बोल रहे हैं।

(हंसी)

श्री हंसराज आर्य—(स्पष्ट न सुनाई देने से अश्रव्य-भाषण अनुमोदित होकर प्राप्त नहीं हुआ)।

[श्री हंसराज आर्य]

पैसे के लिए कहा गया है कि पैसा खर्च होगा या नहीं। इसमें से कितने रुपये खर्च हो जावेंगे ? पहली योजना बनी, जो भी रकम रखी गई थी उसमें से चार साल में तो बहुत ही कम खर्च हुआ और उस रकम को इस एक साल में भी खर्च कर सकेंगे या नहीं, इसमें भी सन्देह है। आने वाली योजना में जो पैसा रखा गया है वह भी पूरा खर्च हो जायगा या नहीं, इसके लिए भी सन्देह है क्योंकि जो स्थिति पहली पंचवर्षीय योजना की हुई है उससे स्पष्ट है कि आप अभी तक पूरा खर्च नहीं कर सके हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपसे अर्ज करूंगा कि पानी के लिए १ करोड़ रुपया रखा। चार साल तक वह पैसा खर्च होता रहा लेकिन मुश्किल से कोई २०, २२ लाख रुपया खर्च हो पाया होगा और अन्त में एक बोर्ड नियुक्त करना पड़ा और बोर्ड बना, लेकिन जो बचा हुआ पैसा ६५ लाख रुपये के करीब है, वह नहीं मिला और आज भी पैसा और मिले बोर्ड के द्वारा गांवों में पानी की व्यवस्था के लिए (अश्रव्य) जिस तरह सेपानीका बोर्ड नहीं होसका चार सालमें

(अश्रव्य)

क्या यह हो जायगा ? मेरी, माननीय अध्यक्ष, आपके द्वारा मुख्य मन्त्री जी से प्रार्थना है कि वे इस बात की जांच करें कि यह कमी कहां है ? पैसा मन्जूर होता है, लेकिन खर्च क्यों नहीं होता है ? मैं इस चीज़ को नहीं समझ पाया हूँ। इस योजना में जितनी कमी की गई है वह हमारे फाइनेन्स विभाग की वजह से। वह ऐसा स्थान है कि जहां कागज एक बार जाने के बाद छः महीने से पहले नहीं लौटता और जितनी रकम लैप्स होती है उसकी जिम्मेदारी फाइनेन्स विभाग की है। इसी तरह से हमारे स्थानीय कर्मचारी भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। या तो पैसा खर्च नहीं होता है या वे इतने योग्य नहीं हैं कि खर्च कर सकें। जो भी है उसका पता करके माननीय मुख्य मन्त्री जी को इसकी कोशिश करनी चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि इस योजना को पूर्ण रूप से सफल बनाया जाय। मैं बड़े अदब के साथ माननीय अध्यक्ष, आपके द्वारा हाउस के नेता से प्रार्थना करता हूँ कि जो कमियां हैं उनको वे दूर करें और यदि फिर भी उनको विश्वास हो कि पैसा पूरा खर्च नहीं हो सकेगा, जल बोर्ड की तरह से तो उसके लिए और तरह से प्लान किया जाय और गैर सरकारी योग्य व्यक्ति हैं उनका सहयोग लिया जाकर पैसा खर्च किया जाय। इसके साथ साथ मैं यह भी प्रार्थना करूंगा कि वैसे तो पहली योजना के मुकाबले दूसरी योजना में ऐसी योजनाओं के लिए दो करोड़ रुपया जो रखा है यह सामुदायिक योजनाओं के लिए रुपया है। सामुदायिक योजना और जल बोर्ड आदि के लिए जो रुपया रखा गया है वह करीब साढ़े तीन करोड़ बैठता है। फिर भी राजस्थान में जैसी पानी की स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए इसको पूरा पैसा नहीं माना जा सकता।

राजस्थान में जैसी पानी की स्थिति है वैसी अन्य किसी प्रान्त में नहीं होगी। मेरा सिर्फ यही निवेदन है कि इस पैसे को और बढाया जाय। आज ऐसी स्थिति है, कई ऐसे इलाके हैं जहां १५, २० मील तक पीने का पानी नहीं मिलता। इसके लिए तालाबों और कुओं को ऐसा बनाया

[श्री हंसराज आर्य]

जाय जिससे यदि चार साल तक भी वरसा न हो तो भी पानी की कमी न आये इसी प्रकार पानी का स्थायी इलाज होना चाहिये। मेरी यही प्रार्थना है ।

श्री मोहम्मद इब्राहीम—मि० स्पीकर साहब, दो दिन से दूसरी फाइव ईयर प्लान पर बहस हो रही है। इसके लिए सेन्टर और खुसुसन हमारे महबूब वजीरे आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू सब से ज्यादा मुबारिकबाद के मुस्तहक हैं। वे अपने देश के साथ साथ इस राजस्थान को भी बहुत तेजी के साथ आगे ले जा रहे हैं। वह इन मामलों में मुल्क की तरक्की के लिए रात दिन प्रयत्न कर रहे हैं। बावजूद इसके कि पंडित जी को बेनुल अकवामी सियासत से एक मिनिट की भी फुरसत नहीं है मगर जहां पंडित जी ने बेनुल अकवामी दुनियां में हिन्दुस्तान का मैयार बुलन्द किया है वहां अन्दरूने मुल्क की तरक्की का भी रात दिन ख्याल है, जो आपके सामने है। पिछले पांच वर्षों में देश ने जो तरक्कियां की वह सेन्टर की मदद से ही पूरी हो सकीं। वे जानते हैं कि हमारे मुल्क की तरक्की के लिए किस तरह से काम होना चाहिये ।

मरकजी हकूमत के साथ साथ हमारी राजस्थान की सरकार भी मुबारिकबादी की मुस्तहक है। मैं राजस्थान की हकूमत का ध्यान देहातों की ओर दिलाना चाहता हूं, वे देहातों की हालत की तरफ भी गौर फरमायें। आज जब कि बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े अस्पताल हैं, पहले ही से मौजूद हैं, सब प्रकार के डाक्टर्स रहते हैं वहां गांवों में न दाइयों की न डाक्टरों की तरफ ध्यान है और न जानवरों के अस्पताल की तरफ ध्यान है। आज जितनी भी योजना बनती है वह सब शहरों के लिये बनती है, देहात के पैसे का फायदा शहरी जनता को मिलता है। इन्कलाब आ गया किन्तु हमारे गांवों की देहातों की हालत में सुधार नहीं हुआ। आपको देहातों का नक्शा पलटना चाहिये। आप जयपुर जैसे बड़े शहरों का ध्यान छोड़कर देहातों में बड़े बड़े अस्पताल बनवाइये, वहां नर्सेज़ का इन्तजाम कीजिये, जानवरों के अस्पताल का इन्तजाम कीजिये। देहातों में आप देखेंगे कि खास तौर से मैं अपनी कोन्स्टीट्यूएन्सी की ओर आपकी तवज्जुह दिलाना चाहता हूं; मेरी कोन्स्टीट्यूएन्सी जहां एक लाख की आबादी है और १००फीसदी किसानों की आबादी है वहां एक भी मवेशियों का अस्पताल नहीं। सरदी के दिनों में जब ज्यादा सरदी पड़ती है ऐसे जानवर गायें भैंसे हजारों की तादाद में तड़प तड़प कर मरते हैं लेकिन उनके लिए कोई इन्तजाम नहीं। इसके लिए ऐसा फंड मुकर्रर करना चाहिये, पंचायती एक ऐसे मकान होना चाहिये जहां गांव वाले ऐसे मवेशी रख सकें। और वहां चारे का भी इन्तजाम हो ; जो इसी फाइव इयर प्लान के पैसे से होना चाहिये। इसी तरह तकावी के रुपये मिलने में भी देरी नहीं होनी चाहिये। मैंने बीसों आदमियों की दरख्वास्तें दिलवाई, कुओं के लिये रुपया चाहिये लेकिन वह वक्त पर नहीं मिलता। उसमें ऐसी ऐसी अड़चनें आती हैं कि सरकारी दफ्तरों में कागजात ऐसे अटक जाते हैं कि देहात के आदमियों को बड़ी परेशानी होती है अपने कागजों को निकलवाने में, इसलिये मेरी अर्ज है कि देहात के आदमियों को फौरन दरख्वास्त पर पैसा मिलना चाहिये। छः महिना और साल भर तक पैसा नहीं मिलता ।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

दो मिनिट और दीजिये।

इसके साथ साथ मेरी यह भी गुजारिश है कि जब आप मेडिकल कौन्सिल पर करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं तो हमारी आयुर्वेदिक और तिब्बे यूनानी पर एक दफा इतना ही रुपया खर्च करके देखिये कि इससे किस कदर लोगों को फायदा होता है? देशी जड़ी बूटियों के साथ सौतेली मां का सलूक क्यों किया जाता है? आप जितना खर्चा मेडिकल कौन्सिल पर कर रहे हैं, उसमें से आधा रुपया आपको आयुर्वेदिक और यूनानी दवाखानों पर खर्च करना चाहिये जैसा कि हमारी मरकजी सरकार करती है। दिल्ली में आयुर्वेदिक और तिब्बे यूनानी के लिए जो बजट मन्जूर होता है उसमें से आधा तिब्बे यूनानी पर और आधा आयुर्वेदिक पर खर्च होता है। लेकिन राजस्थान में ८० डिस्पेन्सिरियां आयुर्वेदिक की इस साल खुलवाई जा रही हैं, मगर तिब्बे यूनानी की सिर्फ ३-४ ही खुलवाई जा रही हैं। आयुर्वेद और तिब्बे यूनानी हमारे मुल्ककी रीढकी हड्डी है। हकीमअजमलखां साहिब मरहूम जिनका तिब्बिया कालेज दिल्ली में है गांधीजी ने जिस वक्त हकीम अजमल खां को कांग्रेस में शिरकत की दावत दी उस वक्त अंग्रेजों ने हकीम अजमल खां साहिब को बीस करोड़ रुपया देना चाहा, मगर हकीम साहिब ने सब पर लात मार दी और मुल्क की आजादी के लिए गांधीजी के साथ वह कुरबानी दी जिसकी वजह से हकीम साहिब काफी दिन तक इन्डियन नेशनल कांग्रेस के सदर रहे। मगर आज उनकी हिकमत के साथ ये सौतेली मां का सलूक जमूहरी स्प्रिट के बिल्कुल खिलाफ है और इस तर्जेअमल से गांधीजी की हकीम अजमल खां साहिब की रूह को सख्त तकलीफ पहुंच रही है। हकीम अजमल खां ने महात्मा गांधीजी के साथ मुल्क की खिदमत करके इस देश को आज़ाद कराया वे महात्मा गांधी के मुरीद बनकर उनके साथ रहे। आज उनका कॉलेज हकीमों की खिदमत कर रहा है, यही इन्सान का फर्ज होता है।

हिन्दुस्तान में इन्कलाब आया, हमारे नेता महात्मा गांधी ने फिरका परस्ती के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने कहा हिन्दू मुस्लिम, सिक्ख, इसाई, ये सब एक बागके फूल हैं। कोई लाल है, कोई हरा है, तो कोई नीला, इस तरह से हरएक के साथ एक सा बरताव किया जाना चाहिये। हमारे सूबे में २ लाख मेव अलवर भरतपुर में रहते हैं। जहां मुल्क में तरक्की की बड़ी बड़ी स्कीम बन रही हैं वहां इसी सूबे में २ लाख मेव अपने हक्क के शहरयत से भी महरूम हैं न। उन्हें अपनी जमीन मिली है, न मकान। क्या इसी का नाम तरक्की है? इलेक्शन को हुए ४ साल होगये एक साल और बाकी है। हर शख्श मुसलमानों के वोट का हकदार बनेगा, मगर आज तक हाउस में किसी एक मेम्बर ने भी मेवों के मुत्तल्लिक जबान नहीं खोली, इसलिये मैं चीफ मिनिस्टर साहब से अपील करूंगा कि वे मेवों के मसले को जल्द से जल्द हल करें ताकि मेव भी इत्मिनान की सांस ले सकें और अपने हकके शहरयत का पूरा पूरा फायदा उठा सकें और मुल्क की तरक्की में पूरा हिस्सा ले सकें। मि० स्पीकर साहब के जरिये मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप क्या उनको जमीनें नहीं देंगे? आज उनकी हालत को ठीक नहीं करेंगे तो कब करेंगे? क्या इलेक्शन की वक्त हल करेंगे? गांधीजी देश में इन्कलाब लाये, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि एक देहात का रहने वाला हिन्दुस्तान का प्राइमर मिनिस्टर हो। क्या आप उनके उसूलों को मानने वाले नहीं है? आपको सब के साथ एक सा बर्ताव करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—Order ! order !! आप जितना कहना चाहते थे जिक्र कर चुके।

श्री घीसीसिंह—माननीय अध्यक्ष, जो योजना हमारे भरतपुर के लिए माननीय नेता ने बतलाई उसके लिए मुझे यहपूछना है कि यह लाइन गांव में होकर जायगी या सीधी सड़क होकर जायगी ?

दूसरी बात यह है कि हमारे भरतपुर के लिए वाटर वर्क्स की योजना है, जो पहली पंचवर्षीय योजना में भी थी और अब दूसरी पंचवर्षीय योजना में भी रखी। इस प्रकार दिन दिन आगे बढ़ती जा रही है। क्योंकि हम पहले इतने जानते नहीं थे कि इससे क्या फायदे हैं, हम अब जानने लग गये हैं। अब एक पैसा भी खाली रहने नहीं देंगे। हम अब इतने बच्चे नहीं रहे, हमें मचलाने की नौबत न आने दीजिये। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए जो रुपया रखा है वह हम लेंगे।

हमारे भरतपुर में पुराने बांध कई हैं। अगर उनकी ही मरम्मत कर दी जाय और उनके पानी के आदान प्रदान की व्यवस्था कर दी जाय तो जितना आप जमुना के जल को सिंचाई के काम के लिए न मालूम कितने दिन के बाद करेंगे, लेकिन उनसे तत्काल ही फायदा जनता को पहुँच सकता है।

(घंटी)

एक बात यह है कि बयाना का एरिया ऐसा है कि जहां न कोई नहर ला सकते हैं और न कोई बिजली का कनेक्शन वहां पहुँच सकता है। इसलिए एक पॉवर हाउस के लिए हमारी बड़े दिनों से मांग है कि वहां पर पॉवर हाउस इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नियुक्त कर दिया जाय।

एक मांग हमारी बर तहसील में हाई स्कूल के लिए है, जो कि देहातन के बीच में है। इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उसको कायम कर दिया जाय। हमें तो इतना ही कहना है।

यह जो कर्मचारियों के मुतल्लिक बात कही कि वे सुस्ती से काम करते हैं, यह तो इसलिए कि अब तक हम अनभिज्ञ थे इसलिए सारा काम सुस्ती से हुआ। अब हम इनकी नींद खोल देंगे और इनको सुस्त नहीं रहने देंगे, इसका फायदा लेंगे। अब हम अनुभवी इन्सान बन चुके हैं। यह पंचवर्षीय योजना हमारे कितने कल्याण की है, इसमें सुस्ती में हम अपने कल्याण को नहीं छोड़ेंगे।

श्री अध्यक्ष—श्री जयसिंह राणावत। संक्षेप में कहियेगा।

श्री जयसिंह राणावत—अध्यक्ष महोदय, मुझे अपने क्षेत्र के लिए कई छोटी-मोटी बातें अर्ज करनी हैं। इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो धनराशि प्रदान की गई है इसमें जिन विभिन्न मदों के ऊपर जो रकमें रखी गई हैं वे वास्तव में यथोचित हैं, किन्तु मैं आपको निवेदन करूं कि मुझे आश्चर्य हुआ, और मैं आपका ध्यान पृष्ठ संख्या २४ के दूसरे पेरेग्राफ के नीचे की ओर ले जाता हूं जिसमें कि राजस्थान का सार रूप से चित्र दिया गया है और दूसरा मैं आपका ध्यान उस सूची की ओर दिलाता हूं जिसमें अनुदान की रकमें बताई गई हैं। तो यह बड़े आश्चर्य की बात है कि जहां बड़े बड़े छापेखाने हैं और सरकार का स्टेशनरी एण्ड प्रिंटिंग के मद पर लाखों रुपयों का खर्चा है और जिसकी देखभाल के लिए अच्छे से अच्छे अधिकारी नियुक्त हैं, वहां पर छापेखाने की ऐसी भूलें हों तो ये बुरी दृष्टि से देखी जाती हैं।

मैं अपने इन दो दिनों के साथियों के वादविवादों को सुन कर इस नतीजे पर, अध्यक्ष महोदय, पहुँचा हूं कि यह ठीक है कि वे सदस्य जो हमारे सामने विराजमान हैं वे हमारी अच्छी से अच्छी योजनाओं की, अच्छी से अच्छी स्कीमों की आलोचना प्रत्यालोचना करें, लेकिन मुझे खेद इस बात का है कि हमारे इधर बैठने वाले साथी जिन्होंने मिलकर सरकार बनाई है, अब वह युग जाता रहा जिस युग में हम कहा करते थे कि जैसा 'राजा' ;वैसी 'प्रजा' लेकिन हमारे साथियों को हमने चुन कर भेजा है, और जो योजना अब ऊपर से बनकर नीचे नहीं आई है, बल्कि नीचे से बन कर ऊपर आई है, उसके लिए उसी प्रकार से सरकार की आलोचना करें, तो मुझे यह चीज न्यायसंगत नहीं मालूम होती है। अगर मान लिया जाय कि कुछ अंशों में सरकार में कमी रह गई है तो वह सरकार हमारी है जो अपनी सरकार की गलती है; वह हमारी गलती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह कोई ठीक बात नहीं है कि जिसके लिए उस सूरत में आलोचना की जाय जब कि हमारे मुख्य मन्त्री जी इस पर बहुत विस्तृत भाषण दे चुके हैं। (समय समाप्ति सूचक घंटी)। आज के युग में और पहले भी रामराज्य के वक्त में इस प्रकार के आलोचक मौजूद थे जिन्होंने सीताजी जैसी महादेवीजी को भी कलंक लगाया था। सरकार कितनीही अच्छी से अच्छी योजना प्रस्तुत करे हमारे विरोधी पक्ष के साथी कुछ न कुछ उसमें देखेंगे और आलोचना करेंगे। इन शब्दों में कहा गया है कि

"निन्दक नियरे राखिये आंगन कुटी छवाय।
बिन पानी बिन साबुना निर्मल करे सुभाव"॥

आलोचक को अपने समक्ष रखिये, साथ रखिये, इसलिए कि वे समय समय पर कुछ न कुछ ठीक सुझाव पेश करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, वास्तव में द्वितीय पंचवर्षीय योजना बहुत सुन्दर है, और इसमें यदि सरकार के अधिकारियों का सहयोग रहा तो अवश्य ही हम इस प्रान्त के मान को बहुत आगे बढ़ा सकेंगे, इसमें कोई शक नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय अध्यक्ष, सबसे पहले मैं, जिन माननीय सदस्यों ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर बहस के अन्दर हिस्सा लिया......

श्री अध्यक्ष—38 Members.

श्री मोहनलाल सुखाडिया—उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस योजना को मेरे ख्याल से, पढ़कर समझने का प्रयत्न किया होगा, और उससे बहुत से सुझाव दिये। आम तौर से जिन महानुभावों ने यहां पर अपनेविचार प्रकट किये उनमें मुझे यह अनुभव हुआ कि जो कुछ प्रयास किया गया है उसके लिए प्रशंसा के ही शब्द उसमें थे, उसके लिए हम उनके आभारी हैं।

अब मैं एक एक विषय के अन्दर विस्तार से न जाते हुए कुछ मूल बातों के ऊपर कहना चाहूंगा। हमारे एक माननीय सदस्य ने यह बात कही कि जो प्लान फ्रेम्ड था और जो इसमेंएक समाजवादी ढांचे की कल्पना की जाती थी और देश में जिस समाजवादी ढांचे की कल्पना की गई है उसके अनुरूप इस पंचवर्षीय योजना को देखने से आभास नहीं मिलता है। यह एक बहुत मुद्दे की बात है और इस पर विचार करना भी, मैं समझता हूं सदन के माननीय सदस्यों के लिए उचित है, क्योंकि हम यह कहना चाहते हैं कि हमारी योजनाओं को हम उस ओर ले जाना चाहते हैं। उन्हीं माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि स्टेट सेक्टर के अन्दर हमने अधिक योजनाओं को नहीं रखा, बल्कि नई जितनी योजनायें इस प्लान के देखने से नजर आती हैं उनसे भी ऐसा आभास मालूम होता है कि हम उस ओर नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इस योजना को देखने से ज्ञात होगा कि पब्लिक सेक्टर के अन्दर और प्राइवेट सेक्टर में किन किन चीजों को रखा गया, इसके सम्बन्ध में एक सेन्ट्रल पोलिसी बनाई गई है। तो उस सेन्ट्रल पोलिसी के मुताबिक जो हैवी इन्डस्ट्रीज़ हैं, कुछ दूसरे बड़े खनिज पदार्थ की इन्डस्ट्रीज़ हैं उनको पब्लिक सेक्टर के अन्दर लिया है। बाकी बहुत सी चीजों को अभी प्राइवेट सेक्टर के अन्दर चलाने के लिए गुंजाइश रखी गई है। हमारे यहां पर हमें इस बात को देखना है कि लिगनाइट का काम जो किया जायगा वह पब्लिक सेक्टर में ही करने की बात है, लेकिन उसके अलावा मिनरल डेवलपमेंट के लिए जैसे लीड एन्ड ज़िन्क के स्पेल्टर प्लान्ट के बारे में इसमें कहा गया है, तो उसके अलावा बैराइल की इन्डस्ट्री के बारे में कहा गया है, माईका को मिल करने के लिये एक इन्डस्ट्री एस्टेब्लिश करने के बारे में कहा गया है। और कुछ चीज़ों के लिए इसमें जो बातें कही गई हैं वह भारत सरकार ने फरदर इन्वेस्टीगेशन इकोनामिकली एज़ वेल एज़ ज्योलॉजीकली करने के बाद उसको लेने के लिए कहते हैं। वे परमानेंटली ड्राप करदी गई हैं, ऐसा नहीं मानना चाहिये लेकिन क्योंकि अभी उसके लिये पूरा जितना उसका विकास करने के लिए आवश्यक मेटिरियल चाहिये उतना मेटिरीयल उपलब्ध नहीं होने के कारण फरदर इन्वेस्टिगेशन जिसे कहा जाय उस तरीके से माइनिंग डिपार्टमेंट को रेफर किया गया है। लैड और ज़िन्क माइन्स के बारे में बहुत हद तक विश्वास दिलाया जा रहा है। इसमें मैं समझता हूँ ५, ६ करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। इसके बारे में हमने

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

प्रेस किया है कि इसको स्टेट सेक्टर में लिया जाना चाहिए। हम यह मानते हैं कि दिन ब दिन हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बीच में बेलेन्स पब्लिक सेक्टर का बढ़ना चाहिये लेकिन इससे हमे आगे बढ़ कर प्राइवेट सेक्टर को बिल्कुल अलग करदें ऐसी बात नहीं हो सकती क्यों कि अभी इस पर धनराशि लगाना और दूसरे प्रश्न लगे हुए हैं इसलिये प्राइवेट सेक्टर भी इस काम को कर सकता है इसलिये इसमें से ६ करोड़ रुपये काट लिये गये हैं। प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेट करने के लिये ६ करोड़ रुपये रखे गये हैं। इस पर प्लानिंग कमीशन को ऐतराज था। प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन के लिये इंडस्ट्रियल फाइनेन्स कोर्पोरेशन और राजस्थान फाइनेन्सकोर्पोरेशन है और इसके अलावा एक और लोन देने की ऐजेन्सी है जिसका नाम इस समय याद नहीं पड़ रहा है। जरूरत पड़ने पर इंडस्ट्रीज़ को लोन मिलता है, तो स्टेट पार्टिसिपेशन रखनेवाली बात नहीं आती है। प्राइवेट सेक्टर का डेवलपमेंट होने के बाद उनका असर भी सामने पड़ा है, तो यह राज्य की नीति है कि हम पब्लिक सेक्टर के अन्दर अपने यहां के उद्योग नहीं बढ़ाना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसके लिये दरअसल में कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, यह देखने की बात आती है। मैं शुरू में जैसा निवेदन कर चुका था जैसलमेर में पेट्रोलियम के लिये आज इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। अभी ठीक नहीं कहा जा सकता कि उसका क्या परिणाम है लेकिन उसको वक्त और ज्यादा तेजी के साथ चालू करनेवाले हैं। यदि पेट्रोलियम मिलता है तो हमें उससे बहुत लाभ होनेवाला है। खेतड़ी, अलवर में कोपर की काफी जांच हो रही है, यदि अच्छी तरह से मिल गया तो उससे भी काफी लाभ होनेवाला है। ये चीजें ऐसी हैं कि जो अभी तो प्लान में नजर नहीं आतीं लेकिन सेकन्ड फाइव ईयर प्लान में उसकी सारी जांच के बाद मेटिरीयल अवेलेएबल होता है तो उनके संबंध में फैसला होगा। मेरी निश्चित मान्यता है कि १५० करोड़ की योजना दिखती है, यदि पूरा ध्यान दिया तो आगे भी प्लान काफी बढ़ेगा। इसमें प्राइवेट का बराबर नहीं आता। ५५०० के जो फिगर हैं उनमें प्राइवेट सेक्टर के फिगर्स इन्क्ल्यूडेड हैं इसलिये इसको वर्क आउट करके देखा जाय तो यह १४४ या १५० करोड़ के आस पास न रह कर और भी बढ़ जाता है। तो इसको कम्पेरिजन से स्टडी करने का सवाल आता है कि हमारे यहां क्या संभावना है, क्या नहीं है।

दूसरी बात यह कही गई है कि हमने अपनी योजना तो इतनी बड़ी बनाई है लेकिन इसको कार्यान्वित करने के लिये पर्सनल्स हमारे पास अवेलेबल होंगे या नहीं। जो योजना हमने बनाई है उसके लिये व्यक्ति उपलब्ध होंगे या नहीं, यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। रुपये यदि इससे भी ज्यादा उपलब्ध हों और पर्सोनल्स नहीं हों तो कामयाबी नहीं हो सकती, लेकिन इस विषय में हम शुरू से सतर्क रहे हैं। हमें इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स, एक्सपीरियेन्स्ड वेटरनरी के आदमियों की जरूरत पड़ेगी। कोटेज इंडस्ट्रीज़ के लिये एक्सपीरियेन्स्ड आदमियों की जरूरत पड़ेगी, टेक्निकल आदमियों की जरूरत पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, पंचवर्षीय योजना की जो कोपी सर्क्यूलेट की गई है उसके पेज २५ पर इसके बारे मे डिटेल में तो नहीं लेकिन प्रशिक्षण और विशेषज्ञ के बारे में कुछ लिखा गया है। उसमें उल्लेख किया गया है कि हम यहां पर इसकी पूर्ति

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

के लिये क्या करना चाहते हैं। यह ठीक है कि आज के दिन हम अनुभव करते हैं कि प्रथम योजना में यह अनुभव हुआ कि हमें इंजीनियर्स की इतनी कमी नहीं हुई लेकिन ओवरसियर्स की बहुत कमी हुई डॉक्टर्स की कुछ कमी हुई शुरू में, लेकिन लेडी डक्टर्स की बहुत कमी हुई, नरसेज़ और मिडवाइव्ज़ की बहुत कमी मालूम होती है लेकिन उनकी पूर्ति के लिये अलग ट्रेनिंग सेन्टर्स खोले गये हैं, वेटरनरी ट्रेनिंग के लिये और स्टोकमेन की ट्रेनिंग के लिये भी व्यवस्था की गई है। हमने सारी चीजों को एसेस किया है कि हमें प्रोग्राम के मुताबिक पहले साल में कितनी जरूरत होगी, दूसरे साल में कितनी जरूरत होगी। सारी चीजों को देखते हुए हमारा निश्चित मत है कि आवश्यक पर्सोनल्स उपलब्ध होंगे। यह सही है कि सबसे मुश्किल काम पर्सोनल्स में है, तो कोटेज इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिये जो टेक्निकल पर्सोनल चाहिये यह बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं है। उसका कोई केरिकुलम, खास निश्चित बात हो, ऐसा नहीं है। बहुत सी चीजों के लिये व्यवस्था करनी होगी। उस व्यवस्था के लिये अभी से कार्यवाही करना दिख रहा है। जब इतनी बड़ी योजना को कार्यान्वित कर रहे हैं तो इस बात को सोच कर चलते हैं अध्यक्ष महोदय, कि समय समय पर इसका असर लोगों पर क्या होता है, शुरू में जब प्लान बनाया तब भी यह कल्पना करके तैयार किया था कि अगले ५ वर्ष बाद एवरेज २५ प्रतिशत लोगों की इन्कम में बृद्धि होगी। इस बृद्धि को दृष्टि में रख कर चलते हैं कि ऐसा असर हो रहा है या नहीं, जो फिज़िकल टारजेट्स हैं उनके अनुकूल कितनी प्रोग्रेस करते हैं, यह देखने की बात है। हमने जब प्लान किया तब ३ लाख से ऊपर लोगों को एम्पलोयमेन्ट प्रोवाइड करेंगे, ऐसी कल्पना थी लेकिन एक्च्युली फिगर्स उतने नहीं आये, उसमें वाकई कुछ कटौती हो रही है, जितने की योजना बनाई गई थी उतनी मंजूर नहीं हुई। प्लानिंग कमीशन की मंजूरी के बाद इसको देखना है कि असल में कितने पर्सोनल इस में एम्पलोय हो सकेंगे, इसको एग्ज़ामिन करना जरूरी है। फिजीकल टारजेट्स को एग्ज़ामिन करने का प्रश्न है, उसको देखने की जरूरत है। इसके लिये विचार किया जायगा और इसके लिये जितना सम्भव हो सकेगा हम इसमें तरक्की करने का प्रयत्न करेंगे।

हमारे एक माननीय साथी ने कहा कि सोशियल जस्टिस के ख्याल से सीलिंग्ज के मामले को तय करना है रूरल क्रेडिट के लिये अधिक से अधिक व्यवस्था करनी है। मैं समझता हूं, इन चीजों में सिद्धान्त की दृष्टि से, हमारी नीति की दृष्टि से, इन दोमद्दों पर मतभेद का प्रश्न नहीं आता और सीलिंग्ज के सम्बन्ध में मेरा ख्याल है कि सदन के सामने बहुत जल्दी एक बिल भी आयेगा जिस पर सदन को अपनी राय जाहिर करने का अवसर प्राप्त होगा। इसके लिये एक कमेटी सेट अप की गई थी जिसने प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी कम्पलीट कर ली है, उसको रिपोर्ट तैयार करना है।

रूरल क्रेडिट राजस्थानमें दुर्भाग्यसे बहुत पिछड़ी हुई दशामें रही मुझे पता नहीं, भारतवर्ष में कोओपरेटिव के जरिये रूरल्ड क्रेडिट पर क्या विचार व्यक्त किया गया था। राजस्थानके केसमें भीविचार नहीं कर सके, लेकिन इस पंचवर्षीय योजना में अध्यक्ष महोदय, हमने हमारे यहां के बेक ग्राउन्ड

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

को, एडमिनिस्ट्रेटिव केपेसिटी को और अन्य सारी चीजों को लक्ष्य में रखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की है । रिज़र्व बैंक से रुपये मिलने की बात कही है, उसमें और भी आगे मिल सकते हैं यदि हम उपयुक्त वातावरण पैदा करें क्योंकि कोओपरेटिव मूवमेन्ट एडमिनिस्ट्रेटिव केपेसिटी का मूवमेन्ट नहीं है बल्कि लोगों का, आम जनता का मूवमेंट है । एक बात और निवेदन करूंगा कि यह पर्सोनल और दूसरे लोगों की व्यवस्था है और सबसे बड़ी आवश्यकता आज है तो प्लान को इम्प्लीमेन्ट करने के लिये ज्यादा से ज्यादा अनुकूल वातावरण पैदा करने की आवश्यकता है क्यों कि जैसा कल निवेदन किया था प्लान को इंपलीमेन्ट करना चाहते हैं । तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय 'राजस्थान के लिये ऐसा समय होगा जब कि अपने को धैर्य के साथ महनत करने की आवश्यकता पड़ेगी । द्वितीय पंच वर्षीय योजना में जो रकम और महनत खर्च की जायगी वह और प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो खर्च की गई है उसका परिणाम तृतीय पंचवर्षीय योजना में मिलेगा जब कि खर्च वाले फेक्टर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में काफी आने वाले हैं ।

चाहे भाखरा को लीजिये, चाहे राजस्थान केनाल को लीजिये, चाहे और किसी योजना को लीजिये सैकन्ड फाइव ईयर प्लान का परिणाम और रिटर्न होता है थर्ड फाइव ईयर प्लान में जो आयेगा, जब राजस्थान की फाइनेन्शियल शेप सेट अप होगी तब । इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना को पूरा करने के लिये अगर हम चाहते हैं कि आगे बढ़ने के लिये हमारे अन्दर वातावरण पैदा हो तो इसके लिये काफी प्रयत्न करना होगा । एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से और सारे माननीय सदस्य जो यहां सदन में उपस्थित हैं और जो उपस्थित नहीं हैं, उनकी तरफ से राजस्थान के अन्दर इसको कामयाब बनाने के लिये वातावरण पैदा करना होगा और प्रयत्न करना होगा और वह स्थिति हुई तो किसी भी कारण से यह सम्भव नहीं होगा कि हम आगे नहीं बढ़ सकें ।

आज सुबह जब बहस हो रही थी तो एक प्रश्न उठाया गया था कि हमने यहां स्कूल गोइंग एज के विद्यार्थियों के लिये अगली पंचवर्षीय योजना के अन्दर भी ५० से ५५ प्रतिशत के आंकड़े रखे हैं, वह जरा कम ही हैं । इसे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि ज्यादा रखते तो अच्छा होता । सोशियल सर्विस के ऊपर ज्यादा रखते तो अच्छा होता, इसमें दो राय नहीं हो सकती । पर सोशियल सर्विस पर भी जो हम खर्च करना चाहते हैं वह हमारी रेवेन्यु इन्कम से भी सम्बन्धित है क्योंकि जो सोशियल सर्विस पर खर्च करना चाहते हैं वहां रेवेन्यु का रेकरिंग एक्स्पेन्डीचर का सवाल आता है, अस्पताल खोलते हैं तो वह खर्चा बढ़ाने वाला है और इसके लिये हमारी रेवेन्यु इन्कम कितनी बढ़ती चली जायगी इसका लक्ष्य हमें रखना जरूरी है ।

इन सब बातों को लक्ष्य में रखते हुए ही इस बारे में सोचना पड़ता है और काम करना पड़ता है । अच्छा होता कि इन कामों पर ज्यादा खर्चा होता और हम आगे बढ़ते; मजबूरी जरूर महसूस हो रही हैं । जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना में बजट के वक्त उन्होंने कहा था

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

कि राजस्थान डेफिसिट में चल रहा है, कमी करिये; जितनी कमी कर सकते हैं, उतनी कमी करिये। तो बहुत से काम यहां के प्रोफिट के ऊपर निर्भर करने वाले हैं। राजस्थान की उन्नति की ओर अगर सब मिलकर इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में काम करेंगे तो राजस्थान की उन्नति होगी और यह सब करेंगे तो अब मुश्किल नहीं होगी।

हमारे कई माननीय मित्रों ने इन चीजों के ऊपर अलग अलग क्षेत्रों के सम्बन्ध में बातें कहीं और इन कई बातों के अन्दर किसी ने पीने के पानी की व्यवस्था अधिक होनी चाहिये, मलेरिया और गिनी वोर्म के लिये व्यवस्था होनी चाहिये और कई खामियों के बारे में चर्चा की। हमारे विरोधी दल के नेता ने इस बात पर जोर दिया कि डिपार्टमेंट्स के हैड्स को ज्यादा तनख्वाह देकर भी योग्य से योग्य हों उनको रखना चाहिये। मैं इस राय से मतभेद नहीं रखता। अगर किसी डिपार्टमेंट में इस बात की आवश्यकता है कि हमारे उस डिपार्टमेंट के लिये हमारे पास कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं है और उस काम के लिये उपयुक्त व्यक्ति यहां से या बाहर से कुछ ज्यादा खर्चा करके लाने की बात है तो इसके लिये हम प्रयत्न नहीं करें, ऐसी बात नहीं है। हमने इसके लिये प्रयत्न किया है। अभी भी ऐसे व्यक्तियों को रखा है और आगे भी आवश्यकता होगी तो सरकार ध्यान में रखेगी। पर यह समझ लेना कि हमारे यहां उपयुक्त व्यक्ति नहीं हैं, ऐसी भी बात नहीं है। हमारे यहां उपयुक्त व्यक्ति हैं; इस बात को मैं मानता हूँ। जो यह प्लान हमारे यहां के ऑफीसर्स ने बनाया है, जितना व्यवस्थित बनाया है, उसके लिये उन्हें बधाई देनी चाहिये। उन्होंने यह प्लान काफी मेहनत और होशियारी से बनाया वहां भेजा और इसका असर प्लानिंग कमीशन पर भी हुआ। हमारे प्लान को देखते हैं तो हमसे एक आध स्टेट छोटी है; दूसरी सब स्टेटों के मुकाबिले में बहुत रिडक्शन हुआ है।

तो हमारे यहां भी आदमी हैं जो कामयाबी के साथ काम कर सकते हैं, और जो कमी है उसके लिये सोचें।

अभी कुछ माननीय सदस्यों ने हमारे वित्त विभाग के ऊपर, एक आध सदस्य ने कहा, उसके बाद मुझे खयाल हुआ कि शायद सभी न कहना शुरू कर दें। कहा गया कि पिछली बार पूरी तौर से नहीं हो पाया इसकी वजह केवल वित विभाग है।

पिछली बार हमारा १५ करोड़ का प्लान था, पर वह प्लान बढ़ता चला गया और इसके लिये जो रूल्स हमारे यहां थे, उनमें परिवर्तन की आवश्यकता है, कुछ परिवर्तन किये गये हैं और कुछ और किये जायेंगे। वित्त विभाग अगर सारी छान बीन नहीं करें तो हमारी पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी जो बाद में बैठती है वह कुछ और ही दृष्टिकोण वहां लेती है, इस वक्त और दृष्टिकोण होता है बाद में और ही दृष्टिकोण होता है। इसलिये गवर्नमेंट के लिये, वित्त

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

विभाग के लिये और विभागीय अध्यक्षों के लिये बड़ी और(कठिन)स्थिति है। जल्दी करते हैं तो कहते कि यह सब छानबीन नहीं की, यह गलतियां रख दीं, यह प्रोसीजर पूरा नहीं किया गया और अगर देर करते हैं तो कहा जाता है कि इतनी देर क्यों की गई ? तो सबका समन्वय करना जरूरी है। जो देर होती है वह देर करने की है, बिल्कुल लूज़ करने की बात भी नहीं होती; इससे भी कई दिक्कतें पैदा होती हैं ।

अब मैं अगर जुदा जुदा एक एक महानुभाव ने कई अलग अलग चीजें कही हैं, उन एक एक की डिटेल में न जाऊं तो अच्छा होगा। इन पर अलग अलग बातों पर कहना आवश्यक नहीं होगा, क्योंकि वह एक बहुत बड़ा फहरिश्त है।

किसी ने कहा कि शाहपुरा में वाटर वर्क्स होगा कि नहीं ? किसी ने कहा कि भरतपुर में तो पहले ही दिया गया था, अब इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्यों दिया ? पहली पंचवर्षीय योजना में लिखा गया था पर वह हुआ नहीं इसलिये इसमें रखा गया है, पैसा उसी बजट में से आयेगा।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि शाहपुरा कौनसा है, अलवर के पास वाला या भीलवाड़ा के पास वाला शाहपुरा। मैं अर्ज कर दूं कि भीलवाड़ा के पास वाला शाहपुरा है। अलवर के पास वाला शाहपुरा इतना आबाद नहीं है।

एक बात मुझे और कहनी पड़ेगी। जो विरोधी दल के नेता ने कहा कि बीकानेर जिले में प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुछ काम नहीं हुआ। मैं उनसे इस संबन्ध में निवेदन करूंगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में भाकरा और चम्बल की योजना का काम शुरू हुआ।......

कु० श्री जसवन्तसिंह—मैंने बीकानेर कोन्स्टीटुएन्सी के बारे में कहा था।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—वह काम पूरा नहीं हुआ ? इसके बाद नेशनल एक्सटेन्शन ब्लोक्स वहां शुरू किये गये, शीप एण्ड वूल का काम शुरू किया गया। इसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्दर आप देखेंगे कि राजस्थान केनल, एक्सटेन्शन ब्लोक्स खोलने का और वूल इन्डस्ट्री के बारे में कहा गया। डिस्पेन्सरीज़ से कोई जिला बाकी नहीं रहेगा। आपने वूल के लिए कहा है, उसके बारे में दुबारा ध्यान दिया जावे। मैं समझता हूँ कि इस सम्बन्ध में एनिमल हस्बेन्ड्री और एग्रिकलचर डिपार्टमेंट से जो फैसला किया गया उसके अनुसार ६८ लाख रुपया रखा गया है और वह इसी उद्देश्य से रखा गया है कि राजस्थान के अन्दर वूल के उद्योग को जल्दी से जल्दी पनपाया जावे। पीने के पानी के बारे में कहा गया। मैंने शुरू में आपसे निवेदन किया था कि हम आशा करते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक करीब करीब सभी गांवों के अन्दर पीने के पानी का कुछ न कुछ इन्तजाम हम कर पावेंगे।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

अंत में मैं ज्यादा न कह कर, जिन माननीय सदस्यों ने इस बहस में हिस्सा लिया और जो सुझाव दिये हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो सुझाव हमारे सामने आये हैं उनमें से बहुत से कन्स्ट्रक्टिव सुझाव हैं, उन पर हम पूरा ध्यान देंगे और योजना इस प्रकार की है उसकी समय समय पर प्रगति व हमारी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आप अपना सहयोग देंगे। यह कर मैं सुझावों लिए धन्यवाद देता हूं।

(हर्ष-ध्वनि)

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि मैंने सारी स्थिति साफ कर दी है। अत: एक बार फिर सुझावों के लिए माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हुआ अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष—As regards the motion for consideration of the Rajasthan Panchayat Bill, 1955, I may just say that as theBill was not ripe the motion was not allowed.

(कुछ विराम के अनन्तर)

अब सदन को स्थगित करते हैं साइन डाई (sine die), बगैर कोई तारीख निश्चित किये।

[तत्पश्चात सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित हुई]

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक—१५ अक्टूबर, १९५५

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ सं०	लाईन सं०	अशुद्ध	शुद्ध
१५२०	२	सयंकालीन	सायंकालीन
१५२५	शीर्षक	घर	पर
१५२६	शीर्षक	सुभ्झावों	सुझावों
१९२६	२	मथुर	माथुर
१५२८	शीर्षक	तंचवर्षीय	पंचवर्षीय
१५२९	शीर्षक	द्वितिय	द्वितीय
१५३३	शीर्षक	व्राद-विवाद	वाद-विवाद
१५३७	,,	द्वितिय	द्वितीय
१५६२	शीर्षक	पंचवहीय	पंचवर्षीय